हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 13 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डॉ राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

13.2.2019/1100/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 878

श्री सुरेश कुमार **कश्यपः (पच्छाद)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में दर्शाया गया है कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में 1071 किसानों को लाभान्वित किया गया है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन किसानों को क्या-क्या लाभ दिए गए और इनके ऊपर कितनी धनराशि व्यय की गई?

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन कार्यक्रमों का लाभ किसानों को दिया गया है उसकी सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी गई है। माननीय सदस्य ने कहा कि कितने किसानों को लाभ दिया गया है? मैं, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 1,071 किसानों को और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत 851 किसानों को लाभ पहुचाया गया है। केन्द्र सरकार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 48,94,221/-रुपये खर्च किए गए और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 06,92,22,659/-रुपये खर्च किए गए हैं।

श्री सुरेश कुमार **कश्यपः** माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन यह कृषि विभाग से सम्बन्धित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एच.डी.ओज. की पोस्टें राजगढ़ ब्लॉक और पच्छाद ब्लाक में भी खाली हैं, जिसमें राजगढ़ में दो पोस्टें खाली हैं और पच्छाद ब्लॉक में भी दो पोस्टें खाली हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक इन पोस्टों को भर दिया जाएगा।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि वहां पर चार पोस्टें खाली हैं। हमने निकट भविष्य में पोस्टें भरने के लिए **हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस** कमिशन को कहा है,

जैसे ही उनका रिजल्ट निकलेगा, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके चुनाव क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर पोस्टें भर दी जाएंगी।

13-02-2019/1105/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1345

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उद्योगों द्वारा गंदा पानी सरसा नदी, चिकनी नदी, बाल्द नदी तथा अन्य नालों में जा रहा है। जिससे नदी-नालों में जो पहले स्वच्छ पानी होता था, वह प्रदूषित हो गया है। न तो उस पानी को पशु पी सकते हैं और न ही कोई आदमी पैदल चलकर उसे क्रॉस कर सकता है क्योंकि इससे चर्म रोग पैदा होता है। यहां पर सूचना दी गई है कि 12 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 15 उद्योगों को जल प्रवाह उपचार संयंत्र में सुधार के लिए कहा गया है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं जो हमारे पुराने नदियां-नाले आज उद्योगों की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए सरकार क्या कठोर कदम अपना रही है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता माननीय सदस्य जी ने जाहिर की है, हम उनसे सहमत हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारे दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज़ लगी है। वह नालागढ़ और बद्दी का इलाका है। जहां भी इंडस्ट्री लगती है वहां पर पर्यावरण खराब होने की सम्भावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन सरकार इस सारे मसले को लेकर बहुत गम्भीर है। जहां आपने दो नदियों का ज़िक्र किया कि उन दोनों नदियों में उद्योगों से डिस्चार्ज होने के बाद जो पानी जाता है उससे नदियों का पानी जहरीला हो रहा है। पशु अगर वह पानी पियें तो उनके बीमार होने की सम्भावना हो जाती है और कोई आदमी वहां नंगे पांव उस पानी के बीच से पार निकलता है तो चर्म रोग होने की सम्भावना हो जाती है। आपने इस बात का ज़िक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बातें बीच-बीच में उठती भी रही हैं और कुछ जगह इस प्रकार की बातें ध्यान में भी आई हैं। कुछ जगह जिस स्तर पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है उसमें पहले कमियां रही हैं। लेकिन जहां भी इस प्रकार की बात ध्यान में आती है हम समय-समय पर उस पर कार्रवाई करते हैं। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है कि इस इलाके के नज़दीक जितने भी नदी-नाले हैं, हम

वहां से समय-समय पर पानी के सैम्पल लेते रहते हैं कि कहीं किसी कारण से पानी में प्रदूषण ज्यादा तो नहीं फैल गया, जिसके कारण जानवरों और किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सके। इस बात को लेकर हम बार-बार सैम्पल लेते रहते हैं। हमने एक साल में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 12 इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका हमने उत्तर में ज़िक्र किया है। मुझे लगता है कि इस कार्रवाई का सार्थक परिणाम सामने आया है और आगे कई चीज़ें बेहतर हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2018-19 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 15 औद्योगिक इकाइयों के जल प्रवाह उपचार संयंत्र में सुधार किया है। फैक्टरी वालों को इस बात के आदेश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जल प्रदूषण न हो। अगर प्रदूषण थोड़ा भी फैलता है या किसी कारण से उद्योगों से डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज के कारण पर्यावरण खराब होने की सम्भावना रहती है और उसके साथ-साथ नदी-नाले में जो पानी वहां से बहता है उसके कारण जल प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है, तो उसको रोकने के लिए हमने समय-समय पर कदम उठाए हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने इस सारी बात को लेकर कहा है, एक तो मैंने कह दिया कि हम नदी-नालों के सैम्पल बीच में समय-समय पर लेते रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं जहां भी हमको थोड़ा-सा प्रदूषण लगता है तो उसमें तुरन्त आगे बढ़ करके कार्रवाई करते हैं कि कहां से डिस्चार्ज आ रहा है और किस प्रकार से उसको रोकना है।

13.2.2019/1110/केएस/डीसी/1

इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो प्लांट्स लगे हैं, उनको हिदायत भी दी जाती है । जहां से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि यहां से डिस्चार्ज पानी में जा रहा है तो उनके खिलाफ समय-समय पर हम कार्रवाई भी करते रहते हैं। मेरा यह कहना है कि **हम इस सारे मामले को ले कर गम्भीर हैं और सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हैं, पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी कोताही करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।**

श्री परमजीत सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने वैसे तो विस्तृत उत्तर दे दिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि केंदुवाल में जो सी.ई.टी.पी. प्लांट लगाया है, इसमें सारे उद्योग कनैक्टिड नहीं हैं। जब बारिश का मौसम होता है, हरियाणा में कालका की तरफ ही बारिश हो रही होती है तो वे लोग नालों में पानी छोड़ देते हैं। ट्रीटमैंट प्लांट जो इन्होंने इंडस्ट्री में लगा रखे हैं, जब विभाग के लोग जाते हैं, उस समय तो वे उनको चालू कर देते हैं लेकिन उनके वहां गेट से बाहर निकलते ही वे लोग ट्रीटमैंट प्लांट को बंद कर देते हैं। उससे यह समस्या पैदा हो रही है। हम भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ आएं, इससे हम सभी को फायदा होता है लेकिन इससे हमारे बहुत से लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। पशुओं की बहुत ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। मेरी एक पंचायत है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें 7 मौतें पिछले एक साल के अंदर-अंदर कैंसर से पीड़ित लोगों की हुई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उद्योग ऐसा कर रहे हैं, ट्रीटमैंट प्लांट जब विभाग जाता है, उस वक्त चालू कर दते हैं और बाद में बन्द कर देते हैं, क्या विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उसके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि केंदुवाल, तहसील बद्दी में 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल शोधन क्षमता का एक सामान्य प्रवाह उपचार संयन्त्र यानि कि Common Effluent Treatment Plant (CETP) स्थापित किया गया है। जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ उद्योग थोड़ी देर के लिए तो उसको जोड़ देते हैं, फिर बाद में उसका पानी सीधा नदी-नालों में जाने देते हैं। माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया, मैं सुनिश्चित करुंगा, आप मुझे उस पंचायत के बारे में लिखकर दें। मैं जानकारी भी हासिल करुंगा। अगर कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट ने ट्रीटमैंट प्लांट से अपने आप को कनैक्ट न करके सीधा डिस्चार्ज नदी-नालों में जाने दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो आप कंदुवाल का ज़िक्र कर रहे हैं, वहां से बीच-बीच में

सैम्पल लिए गए हैं। अभी तक इस प्रकार की बात सामने नहीं आई है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि **अगर आप मुझे सपैसिफिक बताएंगे तो मैं सुनिश्चित करुंगा कि वहां टीम जा कर विज़िट करें और वहां से आज की तारीख में सैम्पल लें और अगर इस प्रकार की बात पाई जाती है, वहां पर अगर पानी में प्रदूषण है और किसी यूनिट ने अगर वहां पर हमारा जो ट्रीटमैंट प्लांट सी.ई.टी.पी. है, उसमें न जोड़कर डिस्चार्ज को बाहर छोड़ दिया है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।**

प्रश्न संख्या 1346

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न संख्या 1346 में सूचना मांगी गई है, वह "क" एवं "ख" में रखी गई है लेकिन निर्वाचन क्षेत्रवार सूचना मांगी है जबकि हमारी योजनाओं का आकलन हम विकास खण्ड वार करते हैं । तो सूचना एकत्रित की जा रही है।

13.2.2019/1115/av/dc/1

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ब्लॉकवाईज सप्लिमैंटरी सूचना चाहता हूं कि किस-किस ब्लॉक में कितने-कितने घर स्वीकृत हुए। प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत घर वरिष्ठता के आधार पर स्वीकृत होते हैं। अतः ऐसे कितने भूमिहीन लोग हैं जिनके लिए घर स्वीकृत हुए और वे घर अभी तक भूमि न होने के कारण बने नहीं हैं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास ब्लॉकवाईज सूचना तो होगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : इस बारे में सारी सूचना एकत्रित करके आपको इसी सत्र में दे दी जायेगी।

श्री सुख राम : माननीय मंत्री महोदय, फिर आप मुझे यह सूचना भी दें कि ऐसे कितने लोग हैं जो भूमिहीन हैं और जिनके घर आपने स्वीकृत कर दिए हैं। सम्बंधित विभाग के पास उनके केस लम्बित पड़े हैं, उनको भूमि अलॉट करके घर बनाने का क्या माननीय मंत्री जी विश्वास दिलायेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय सदस्य, मैंने कहा है कि इस बारे में सारी सूचना इकट्ठी करके आपको इसी सत्र के दौरान उपलब्ध करवा दी जायेगी।

प्रश्न संख्या : 1347

श्री जवाहर ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में चम्बा, कुल्लू, मण्डी और शिमला; चार जिले ऐसे हैं जहां पर साढ़े पांच हजार फीट से नौ हजार फीट की ऊंचाई तक इतने घने जंगल हैं जो 12 महीने हरे-भरे रहते हैं। मगर ये जंगल इतने पुराने हो चुके हैं कि उनमें अब न तो जानवर व पक्षी रहते हैं और उनमें इनसान को जाना भी मुश्किल होता है। ये जंगल इतने घने हैं कि इनमें अब धूप और हवा भी ठीक से क्रोस नहीं कर पाती। मेरा मानना है कि ऐसे जंगलों का साईंटिफिक तरीके से दोहन होना चाहिए। इन जंगलों में इतने ज्यादा हाफ ड्राई और गिरे हुए पेड़ हैं जिनकी वजह से उनमें कोई नई पैदावार भी नहीं लग रही है। ऐसे जंगलों से पर्यावरण को भी कोई लाभ नहीं पहुंचता। मंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे कई जंगल हैं और पहले भी जंगलों का दोहन होता था उसमें बी0बी0-। की मार्किंग होती थी। उसमें केवल प्राकृतिक बीजदार और स्वस्थ पेड़ों को रखा जाता था व बाकी पेड़ों को निकाल दिया जाता था जिसके बाद उसमें प्राकृतिक पेड़ लगते थे। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे जंगल हैं जहां पर नये हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं। इसलिए इन जंगलों में दयार, कायल, रई, तूस इत्यादि के जो सैंकड़ों सड़े-गले व गिरे हुए पेड़ हैं इनका दोहन किया जाए। ऐसा करने

से सरकार को इससे रेवन्यू भी जनरेट होगा और जंगल भी नये तरीके से विकसित हो पायेंगे। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या विभाग इस बारे में विचार कर रहा है?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगलों से सूखे-गिरे पेड़ों की लकड़ी और बिरोजे के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विपणन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का दिनांक 25.3.1974 को एकमात्र एजैंसी के रूप में गठन किया गया था। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इस सतत् प्रक्रिया के कारण लगभग हर वर्ष इस तरह के लॉट बनाये जाते हैं।

13/02/2019/1120 /टी0सी0वी0/एच0के0/1

अभी वर्ष 2018-19 में एक लाख 34 हजार पेड़, जिनकी 1,46,605 घन मीटर लकड़ी हिमाचल प्रदेश विकास निगम को दी गई। इन वृक्षों को निकालने की यह सत्त प्रक्रिया है। केवलमात्र ऐसे जंगल जो वन्य प्राणी अभयारण और नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के CWP-202/96 के अंतर्गत गोदा वर्मन बनाम भारत संघ वन्य के निर्णय के अनुसार उन वृक्षों को नहीं निकाला जाता है। वन विभाग के वैज्ञानिकों के आधार पर यह निर्णय सही है। बाकी सब जंगलों से इस प्रकार के वृक्षों निकाला जाता है।

प्रश्न संख्याः 1348

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, डीलिमिटेशन में धर्मपुर क्षेत्र की 4 पंचायतों, जैसाकि प्रश्न के जवाब में बताया गया है, सरकाघाट चुनाव क्षेत्र में शामिल कर दी गई है। ये सारी पंचायतें सरकाघाट टाउन से लगती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इन पंचायतों को सरकाघाट में शामिल किया जाए। इसमें बी0डी0ओ0 का ऑफिस तो बदल गया है, लेकिन लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि और बी0एम0ओ0 के ऑफिस भी यदि सरकाघाट में आ जाएं तो इससे जनता को बड़ी सुविधा होगी। मैं माननीय मंत्री जी से इसका आश्वासन चाहता हूं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रीः <u>माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मांग उठाई है, वह पूरी कर दी जाएगी।</u>

प्रश्न संख्याः 1349

श्री विनय कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के 'ख' भाग में जो उत्तर दिया है, उसमें दर्शाया गया है कि इसकी अनुमानित लागत जो 2015 में थी वह बढ़कर 2018 में 70000 करोड़ रुपये हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका जो रिऐस्टिमेट प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजना है, उसमें कितना समय लगेगा?

दूसरा, जो सैंक्चुअरी और प्राइवेट लैंड ट्रांसफर हुई है, उनको अभी तक मुआव़जा नहीं मिला, उसमें कितना समय और लगेगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सैंटरल वॉटर कमीशन के माध्यम इसके लिए 2015 4596.76 करोड़ रुपये का अनुमान था और अब 2018 में इसकी लागत 70000 करोड़ रुपये निश्चित हुई है। इसका कारण यह रहा है कि इसमें 954.27 प्राइवेट लैंड एक्वायर होनी थी, लैंड एक्वाजिशन के माध्यम से लगभग 916 हैक्टेयर लैंड और 31.31 हैक्टेयर लैंड नेगोशिएशन के माध्यम से एक्वायार की गई है। इस तरह से लगभग कुल 948 हैक्टेयर लैंड एक्वायर की गई है। परन्तु अदालत की चुनौती के बाद लैंड की जो कीमत है, वह बढ़ गई है। अभी इसका केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। इसलिए 2277 करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी लागत बढ़ी है।

13-02-2019/1125/NS/HK/1

श्री विनय कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाह रहा था कि जो रि-एस्टिमेट प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजना है, इसमें कितना समय लगेगा और कब तक हो

जाएगा? दूसरा, जब आप डैम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो इसमें जो एल्ट्रनेटिव रूट्स हैं, पहले आपको इन रूट्स को बनाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर अभी जो रूट है, वह बंद हो जाएगा और इसके लिए एच0पी0पी0सी0एल0 के पास कितनी धनराशि पड़ी हुई है और क्या आप डैम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इस रूट को शुरू करवाएंगे?

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर एच0पी0पी0सी0एल0 के माध्यम construction of the project राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और इनके माध्यम से ही इसमें काम किया जाएगा। पहले तो लैंड एक्विजिशन की बात है क्योंकि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 40 मेगा वाट बिजली के दोहन की क्षमता है। जब प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा तो पहले यह ध्यान रखा जाएगा कि एल्ट्रनेटिव रूट्स के निर्माण हों और फिर काम शुरू किया जाएगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि आप कब तक एस्टिमेट केंद्र सरकार को भेज देंगे?

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और मैंने अपने जवाब के 'ख' भाग में कहा है कि इसमें तकनीकी सलाहकार समिति से मंजूरी आनी है और इसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अप्रूवल आनी है। जब ये सारी अप्रूवल हमारे पास आएंगी तो उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्षः माननीय राकेश सिंघा जी, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछिए।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही कहा कि ये हमारे प्रदेश को लाभ ही लाभ देगा। क्योंकि इसकी कोस्ट बहुत कम है। मैं आपसे दो महत्वपूर्ण प्रश्न

13-02-2019/1125/NS/HK/2

पूछना चाहूंगा। पहला, हमारे अधिकार हैं, जो परमार साहब ने लड़ कर देश के स्तर पर Riparian State Rights इसको बचाने के लिए आप क्या-क्या कदम उठाएंगे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा चली है कि जहां भी प्रोजेक्ट बनेगा, वहां पर कुछ प्रभावशाली लोग गरीब को ठग कर जमीन ले लेते हैं और क्या आप इसमें छानबीन करने को तैयार हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ प्रभावशाली लोगों ने गरीब आदमी को ठग कर जमीन अपने नाम कर ली है। ये सारी जमीनें बेनामी है। क्या आप इसमें छानबीन करेंगे?

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो लैंड एक्विजिशन की बात की है तो लैंड एक्विजिशन में एक्ट 1894 के अधीन लैंड एक्वायर की जा रही है। पहले जब लैंड एक्वायर की जा रही थी तो उसमें अलग-अलग तरीका था। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय में यह बात गई तो उनका सारा एरिया सबमर्ज़ हो जाएगा तथा लैंड की कोस्ट बराबर मानी जाए। इसकी वज़ह से ही कोस्ट एस्केलेशन हुई है। दूसरा, माननीय सदस्य ने छानबीन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इस माननीय सदन में इसके बारे में कोई बात हुई है या नहीं। अभी लेटेस्ट इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है और मेरे पास इसकी जानकारी होगी तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुख राम अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा रेणुका डैम का जो एम0ओ0यू0 साईन हुआ है, यह किस तारीख को साईन हुआ है? दूसरा, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जब इनके एम0ओ0यू0 साईन होते हैं, मैं दो प्रोजेक्ट्स का आपको यहां पर कोड करना चाहता हूंः खोदरी पावर हाउस और छिबरू पावर हाउस हैं। ये दोनों पावर हाउस पहले उत्तर प्रदेश की सरकार (वर्तमान उत्तराखंड) ने बना लिए हैं। आज वहां के लोग पीने-के-पानी और सिंचाई की स्कीम तक नहीं बना सकते हैं और यहां तक कि हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार इस एम0ओ0यू0 में पीने के पानी और सिंचाई स्कीम बनाने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं?

13.02.2019/1130/RKS/YK-1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रोजैक्ट का एम.ओ.यू. 12 मई, 1994 को साइन हुआ था। लेकिन जब 11 जनवरी, 2019 को 6 राज्यों के साथ एम.ओ.यू. साइन हुआ तो उसमें इस प्रोजैक्ट को गति प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया जिसके लिए हम माननीय नितिन गडकरी और माननीय मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं। इस एम.ओ.यू. में इरिगेशन इत्यादि हर चीज़ का ध्यान रखा गया है।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट फेस में 40 मेगावाट का प्रोजैक्ट लग रहा है और दूसरे चरण में 60 मेगावाट का प्रोजैक्ट गिरि में लगा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो यह प्रोजैक्ट लगना प्रस्तावित है इस प्रोजैक्ट का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा या बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा? दूसरा, इस प्रोजैक्ट में जो कर्मचारी रखे जाएंगे क्या वे हिमाचल प्रदेश से ही रख जाएंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रोजैक्ट 40 मेगावाट का लगाया जाएगा उसे हिमाचल प्रदेश पॉवर कोर्पोरेशन के माध्यम से लगाया जाएगा। इसमें जो एम.ओ.यू. साइन हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार ने यह माना है कि इसके निर्माण कार्य के लिए 90 प्रतिशत पैसा दिल्ली सरकार वहन करेगी। इस तरीके से प्रदेश सरकार केवल 10 प्रतिशत पैसा ही खर्च करेगी। क्योंकि सबमर्ज एरिया का पैसा भारत सरकार वहन कर रही है। माननीय सदस्य ने कर्मचारियों को रखने की बात कही, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश से 70 प्रतिशत कर्मचारी रखने का क्राइटेरिया है उसी तरह इस प्रोजैक्ट में भी 70 प्रतिशत कर्मचारी हिमाचल प्रदेश से ही रखे जाएंगे।

श्री विनय कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछना चाहा था कि HPPCL के पास अदायगी के लिए कितने फंड्स बाकी बचे हुए हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तो लैंड एक्वायर की प्रक्रिया चल रही है। लैंड एक्वायर करने के लिए विभाग के पास 686.80 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं जिसके विरूद्ध 451.28 करोड़ रुपये लैंड एक्वायर के लिए दे दिए गए हैं। यह पैसा केवल लैंड रेक्विज़िशन के लिए आया है। कंस्ट्रक्शन्ज के लिए पैसा तब आएगा जब अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होगी।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। एम.ओ.यू में एक प्रयास यह हुआ था कि जो प्रोजैक्ट बनाया जाएगा उसका खर्चा स्टेट गवर्नमैंट ही वहन करेगी लेकिन उस के लिए हम सहमत नहीं हुए। जब शाम को एम.ओ.यू. की कॉपी भेजी गई और दूसरे दिन इस एम.ओ.यू. पर एग्रीमैंट होना था तो उसमें छोटी-सी बात छूट गई थी। हम दिल्ली को पानी देने जा रहे हैं, दिल्ली को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है और दिल्ली वालों ने कहा कि आप इस प्रोजैक्ट को लगाइए और हम इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि आपको पूरी मदद करनी पड़ेगी और हमने इसमें इस कंडिशन को इंसर्ट किया। हिमाचल प्रदेश में 40 मेगावाट का प्रोजैक्ट लगेगा जिसका 90 प्रतिशत खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी।

13.02.2019/1135/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 1350

श्री रमेश चन्द ध्वाला (ज्वालामुखी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इसमें लगभग 42.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मेरे देहरा ब्लॉक में 46 मकान स्वीकृत हुए हैं। इन्होंने यह लिखा है कि जो पंचायतों में जनरल हाउस की मिटिंग होती है उसमें मैरिट के आधार पर पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है और उस सूची में से मकान सवीकृत किए जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बरसात में

काफी मकान गिर चुके हैं इनके बारे में पटवारी ने भी लिख कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मकान रहने के काबिल नहीं रह गए हैं। इसके अलावा कुछ मकान लोगों के जले भी थे। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 42.19 करोड़ रुपया रखा है और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 10 प्रतिशत पैसा आपदा राहत के लिए दिया जाएगा । इसमें से कितने मकानों को पैसा दिया गया है, कितने मकानों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और कितने मामले इनके पास ऐसे लंबित पड़े है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बड़ा विस्तृत उत्तर हमने दिया है । फिर भी माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 में 42.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसमें 2898 मकान मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष प्रावधान किया है । अब वह प्रावधान इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है परंतु बी.पी.एल. में या किसी अन्य मापदंड में नहीं आतें है लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा में उनका मकान गिर जाता है, जल जाता है, या बादल फटने की स्थिति में मकान बह जाता है, ऐसे लोगों को भी मुख्य मंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। इसमें 10 प्रतिश का कोटा रखा गया है। ऐसे लोगों को इसमें कंसीडर किया जाएगा और उन्हें दो लाख रुपये की राशि मकान बनाने के लिए प्रदान की जाएगी। चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने और भी प्रावधान किया है वह यह है कि किसी दीनहीन स्थिति में कोई परिवार है परंतु वह बी.पी.एल. में कवर नही हो रहा है या अन्य किसी पैमाने पर नहीं आ रहा है लेकिन वह गरीब है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वह मकान नहीं बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी मुख्य मंत्री आवास योजना में 5 प्रतिशत का प्राधान किया गया है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में हमने जो-जो प्रावधान किया है उसमें 75 मकानों को स्वीकृत किया है और 75 और मकानों को स्वीकृति हेतु प्रक्रिया चल रही है । जबकि लोगों की तरफ से 258 प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से जो दीनहीन

स्थिति में हैं ऐसे 29 लोगों को मकानों का प्रावधान कर दिया है। कुछ लोगों की और भी प्रार्थना पत्र आए हैं। जैसे-जैसे हमारे पास प्रावधान होता जाएगा हम उन्हे प्राथमिकता के तौर पर लाभ पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार की सोच है।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देहरा ब्लाक में कितने पार्थना पत्र आए और कितने लोगों को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो घोषणा 10 प्रतिशत की गई है और मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपया उनको दिया जाएगा ? इस तरह के कितने मामले लंबित हैं और कितने लोगों को 2 लाख रुपये मकान बनाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं ?

13.02.2019/1140/DT/HK-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा है देहरा ब्लॉक के लिए 46 मकान स्वीकृत हुए हैं और माननीय सदस्य जी यह पूछ रहे हैं कि ऐसी कितने प्रर्थाना पत्र आए हैं? इस संबंध में मैं आपको पत्र के द्वारा सूचित कर दूंगा। इसकी सुचना मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री सुख राम पांवटा साहिबः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनते हैं उनका चयन आई0आर0डी0 पी0 से ही किया जाता है और जो मुख्यमंत्री आवास योजना में घर बनते है उनका चयन भी आई0आर0डी0पी0 में से ही किया जाता है क्योंकि पंचायत से ही लिस्ट जाती है और रेजोल्यूशन पास होता है। इसलिए जो आम गरीब लोग हैं और आई0आर0डी 0पी0 में नहीं है उनको जरूरी है घर देना, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक सर्वे हुआ है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कितने घरों का सर्वे करके प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र सरकार को भेजा गया है ।

अध्यक्षः मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रश्न है

श्री सुख राम:अध्यक्ष महोदय, मै यही पूछ रहा हूं क्या मुख्यमंत्री आवास योजना में यह जो शर्त आपने लगा रखी है आई0आर0डी0पी0, इसको खत्म करके आम आदमी को भी घर मिले और गरीब लोग भी घर बना सके या तो आर्थिक आधार पर इसका सर्वे करवाइए, आर्थिक आधार पर मकान दीजिए । आई0आर0डी0 पी0 के परिवारों को आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घर दे रहे हैं । कई पंचायतों में तो आई0आर0डी0पी0 के लोग हैं ही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेने वाले । इसलिए मुख्यमंत्री आवास योजना में क्या आप आश्वासन देंगे आम व्यक्ति जो गरीब है उसका चयन करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी ,मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं, जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देते हैं इसका जो आधार है एस0सी0 सी0सी0 पर सर्वे हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना में जो मकान दिए जाते है उसका आधार बी0पी0एल0 है तो इसका आधार अलग-अलग है इस करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी, माननीय मुख्यमत्री जी ने इस बात को केन्द्र सरकार से उठाया था और इस मामले को दोबारा से रिसर्वे करने के लिए कहा गया जो कि ग्राम सभा से होकर प्रोंपर अथॉरिटी से हो करके यह मामला जाएगा तो ऐसे गरीब लोगों को जिनके कच्चे मकान हैं हम उनको भी प्राथमिकता के ऊपर मकान देंगे, यह तय है।

श्री होशयार सिंह (देहरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी बाढ़ आई जिसके कारण काफी सारे मकानों को नुकसान पहुंचा है । आप पटवारी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं तो क्या पटवारी ऐसे केसिज के लिए कैपेबल है ? मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 300 मकान डैमेज हुए हैं जिन्हें 1000-1000 रुपये प्रदान किया गया है। मकान की क्षति 50 हजार या एक लाख रूपये आंकी गई थी परंतु राहत केवल 1000 रुपये की दी गई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह प्राकृतिक आपदा से संबंधित है और यह जो मुख्य मंत्री आवास योजना है इसमें हम पटवारी की रिपोर्ट भी लेते हैं और वहां पर बी.डी.ओ. मौके पर जा करके असैस करता है कि सच में यदि किसी का मकान गिर गया है और उनके पास कोई भी अन्य रहने के लिए

मकान नहीं है और वह गरीब है तो उसको हम मुख्य मंत्री आवास योजना में मकान को प्रोसैस करवाते हैं और उसको हम मदद करते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने बहुत लंबा इसका उत्तर भी दिया है। स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बातें खड़ी होती हैं जैसे माननीय सदस्य होशयार सिंह जी ने कही हैं कि जो

13-02-2019/1145/ए.जी./एन.जी./1

पटवारी रिपोर्ट दे रहा है क्या हम यह मान कर चल सकते हैं कि वो सही रिपोर्ट दे रहा है । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस पर हमें मैकेनिजम डेवलप करने की आवश्यक्ता है । बहुत सारा काम पटवारी के उपर ही दारोमदार है । वह अपनी सुविधा के अनुसार, वह अपने हिसाब के मुताबिक कई जगह वह ऐसी रिपार्ट बनाता है और इसको रिपोर्ट सही देनी होती है उसे ठीक बना कर देता है, चाहे ठीक हो भी या नहीं और जनकी रिपोर्ट ठीक बनानी चाहिए उन्हें ठीक रिपोर्ट बनाकर नहीं देता है । हम जब चुने हुए प्रतिनिधि के नाते फिल्ड में जाते हैं तो देखते है कि एक मकान इतना खराब हालात में है, रहने लायक नहीं है । हम उस व्यक्ति से बोलते हैं की आपको मकान क्यों नहीं मिला तो वह कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं है । हम सामने देखते हैं कि मकान ठीक नहीं है और दूसरी तरफ वह कहता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं है । ऐसी परिस्थिती में एक बहुत बडा प्रश्न खडा होता है । यह मुझे नहीं कहना चाहिए क्यों कि यह महकमा मेरे पास नहीं है लेकिन उसके बावजूद इसे हमे किसी ओर तरिके से टैक्नीकली ठीक करना होगा । ताकी जो सही में जो गरीब आदमी है और जो जरूरत मंद आदमी है उसकी मदद हो सके । जिसके मकान को नुकसान हुआ है उसको सुनिश्चित करें कि एक व्यक्ति पर वो आधारित ना रहे, एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर वो आधारित ना हो । उसमें ब्लाक का बीडीओ और उसके साथ तहसीलदार व रैव्न्यू विभाग का पटवारी/कानूनगो का जिक्र हम कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसमें हमें थोडा और मैकेनिज्म डैवलप करना चाहिए ताकि यदि एक व्यक्ति उसको

लिख कर दे दे कि इस मकान मिलना है या नहीं तो उसके मुताबिक सारी चीजें ना हो और इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे । माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न का उत्तर विस्तार से जानना चाहा है उसमें हमारी मन भावना/मंशा यह थी कि बहुत सारे मकान प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होते हैं । उसके बाद प्रदेश में मुख्यमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत बहुत सारे मकान स्वीकृत होते हैं । उसके बाद हमारा जो वैल्फेयर विभाग है उसमें बहुत सारे मकान स्वीक़त किए जाते हैं । ऐसी परिस्थिती में जो प्रवाधन जोडने की बात आई तो उसे जोडने की वजह यह है कि जितनी भी हमारी हाउसिंग योजना है उसमें किस पात्र व्यक्ति को दिया जा सकता है, उसमें सारी एक व्यवस्था बनी हुई है । प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किसको मिलेगा उसकी एक सैट गाईडलाईन है। मुख्यमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किसको मिलेगा उसकी एक सैट गाईडलाईन है । वैल्फेयर विभाग से मकान स्वीकृती के लिए पात्र लोग कौन है उसके लिए भी एक सैट गाईडलाईन बनी है । लेकिन उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग छूट रहे थे जो बहुत ही गरीब है लेकिन वो बीपीएल में नहीं है, अनुसुचित जाती, ट्राईबल या ओबीसी से भी नहीं है उसके बावजूद भी वो छूट रहे थे परन्तु मकान उन्हें चाहिए क्योंकि उनके पास मकान नहीं है । प्रधानमन्त्री आवास योजना की गाईड लाईन के अन्तर्गत भी वो कवर नहीं हो पा रहे थे । लेकिन उनके मकान के हिसाब से उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और उनका मकान पुराना था और ऐसी स्थिती में वो मकान रहने के लायक नहीं है । इसके लिए हमने अलग से यह प्रावधान जोडा है, जिसका जिक्र माननीय मन्त्री जी ने विस्तार से किया है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बडा वर्ग ऐसा है जो इसमें शामिल होगा । इसमें ऐसा भी नहीं ळै कि जो आवेदन करेंगा उसे मकान मिल जाएगा । इसका हमने सिस्टम बनाया है, उसके वैरिफिकेशन का और वैरिफिकेशन के बाद जो पात्र लोग होंगे, जो लोग इन तीनो हाउसिंग स्कीम की कैटेगरी में कवर नहीं हो पाते हैं उनके लिए यह प्रवाधन है । यह कोई खुला प्रावधान नहीं है इसमें भी लिमिट तय की

है । ऐसे लोग जो इन हाउसिंग स्कीम की कैटेगरी में नहीं आते थे उनके लिए हमने यह प्रावधान किया है।

13/02/2019/1150/RG/DC/1

प्रश्न सं. 1351

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन दो सड़कों का इसमें जिक्र हुआ है, लगभग डेढ़ वर्ष पहले ये सड़कें नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेज दी गई हैं। जबकि पीछे जो प्लानिंग की मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें पूछा था कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत यह जो सीलिंग की बात की जा रही थी कि 90 करोड़ रुपये की जो सीलिंग है, वह कई चुनाव क्षेत्रों में क्रॉस हो गई है, तो वहां यह कहा गया था कि सुजानपुर में अभी 60 करोड़ रुपये नाबार्ड के तहत खर्चा गया है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से दो-तीन जानकारियां लेना चाहता हूं कि एक तो ये जो सड़कें हैं, डेढ़ वर्ष पहले नाबार्ड को चली गई हैं और औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं तो क्या सरकार इनको जल्दी-से-जल्दी करवाने का प्रयास करेगी? दूसरा, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में नाबार्ड के तहत जो और भी कई प्रोजैक्ट्स हैं, क्योंकि अभी तो हमारी लिमिट बहुत है और आपका धन्यवाद है कि आपने अभी 15 करोड़ रुपये और भी बढ़ाया है, तो क्या जो और भी प्रोजैक्ट्स पड़े हैं, उनको सरकार जल्दी-से-जल्दी करवाने की कोशिश करेगी? तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आपने पिछले बजट सत्र के दौरान और उसके पश्चात धर्मशाला में भी यह बात कही थी कि जहां-जहां भी कुछ शरारती तत्वों द्वारा फॉउन्डेशन स्टोन तोड़े गए हैं, वे दुबारा से लगाए जाएंगे और एक महीने के अंदर लगाए जाएंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न अलग है।

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोक निर्माण विभाग से ही संबंधित है। वह सड़क जो नाबार्ड के तहत बनी थी और जो फॉउन्डेशन स्टोन तोड़े गए थे, मेरा कोई लंबा प्रश्न नहीं है, उसमें दो स्टोन तो लगा दिए गए हैं। लेकिन एक लोक निर्माण विभाग का और दूसरा इलैक्ट्रिसिटी विभाग का 33 के.वी. सब-स्टेशन का नहीं लगाया गया, ये दो स्टोन अभी नहीं लगाए गए। तो जो अधिकारी आपके आदेश की अनुपालना नहीं कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? अन्तिम प्रश्न मेरा यह है कि जो पिछली सरकार

के समय भी प्रोजैक्ट्स स्वीकृत थे, लोक निर्माण विभाग खासतौर पर उनमें विलम्ब कर रहा है और एक जगह तो ऐसी घटना घटी कि किसी को ठेका दे दिया, काम शुरू कर दिया गया।

अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, ये दो सड़कों का स्पेसिफिक नाबार्ड का प्रश्न है, आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं या इससे अलग पूछ रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राणा : मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

अध्यक्ष : नहीं, जनरल पी.डब्लू.डी. नहीं, आप इसी से संबंधित पूछिए।

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष जी, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।

अध्यक्ष : लेकिन मुझे तो लिमिटाइज करना है।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है, वह थोड़ा अलग है, नाबार्ड से संबंधित है और स्पेसिफिक दो सड़कों से ही संबंधित है। इसका मैंने उत्तर दे दिया है कि सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के अन्तर्गत झानिकर-पाहाल कुआँ वाया कोहलवीं की डी.पी.आर. मु. 186.31 लाख रुपये की बनाकर दिनांक 22 जून, 2017 को और री-घर्थोली वाया झालेड बलियाना की डी.पी.आर. मु. 198.06 लाख रुपये की बनाकर दिनांक 28 अगस्त, 2017 को नाबार्ड को स्वीकृति हेतु योजना विभाग द्वारा भेजी गई है। यह उत्तर इसमें दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इन्हीं दो सड़कों के बारे में थोड़ी डिटेल पूछी है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत टौणीदेवी मण्डल के अधीन झानिकर-पाहाल कुआॅ वाया कोहलवीं सड़क वर्ष 2015-16 में आर.एन.एस.-4 के अन्तर्गत दिनांक 24 अप्रैल, 2016 को कोहलवीं से सिसवां, झानिकर से परोल-सिसवां-डटवाड वाया कोहलवीं, यह सड़क विधायक प्राथमिकता में सब्सटीटियुट हुई थी। इसकी डी.पी.आर. बनाकर योजना विभाग नाबार्ड को द्वारा दिनांक 22 जून, 2017 को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी सड़क जिसका इन्होंने जिक्र किया है उसमें भी

डी.पी.आर. बनाकर योजना विभाग द्वारा नाबार्ड को दिनांक 28 अगस्त, 2017 को भेजी गई है। अभी दोनों सड़कों की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही औपचारिकताएं पूर्ण होती हैं, इनकी स्वीकृति आने के पश्चात इन पर काम शुरू कर सकेंगे।

13/02/2019/1155/MS/AG/1

माननीय अध्यक्ष जी, यहां माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड की जो लिमिट है, वह 60 करोड़ रुपये एग्जौस्ट हो गई है। मुझे मालूम नहीं है कि कहां कमी रह गई है क्योंकि आप तो खास आदमी थे जबकि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी 90 करोड़ रुपये की लिमिट पूरी एग्जौस्ट कर गए हैं। आपके पास तो अभी 30 करोड़ रुपये की गुंजाइश उसमें ही बची हुई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों की ओर से एक बात के लिए आग्रह आ रहा था कि कुछ माननीय सदस्य नये भी चुनकर आए हैं और उनको लगता था कि जो हमारे से पहले माननीय सदस्य रहे हैं, उन्होंने सारी लिमिट एग्जौस्ट कर दी है तो उसमें उनका क्या कसूर है यानी जो एक विधान सभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड की 90 करोड़ रुपये की लिमिट फिक्स की गई थी जिसमें लोक निर्माण एवं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की सारी स्कीमें आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगा कि चुने हुए प्रतिनिधि की बात को सुनना और मानना चाहिए। इसलिए इस बजट में हमने उस मंशा को देखते हुए इसमें वृद्धि की है और उस 90 करोड़ रुपये की सीलिंग को 105 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है।

जहां तक आपने फाउंडेशन स्टोन से संबधित बात कही है, मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि यह क्रम अच्छा नहीं है। फाउंडेशन स्टोन रखना सभी सरकारों की एक सतत प्रक्रिया रहती है। मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक फाउंडेशन स्टोन रखते हैं और इनोग्रेशन करते हैं। उस व्यवस्था के प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। हमने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में अगर कहीं भी फाउंडेशन स्टोन/शिलान्यास की पट्टिका लगी है और उसको तोड़ दिया गया है तो उस बारे में सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि सभी विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि वे सारी पट्टिकाओं को रिस्टोर करें। उसके साथ-साथ हमने यह भी तय किया है और यह पहले से ही व्यवस्था है कि इन सारे मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज़

होना लाजिमी है यानी जिन लोगों ने फाउंडेशन स्टोन/ शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ा है, उनको नुकसान पहुंचाया है, उन सारी चीजों को लेकर मामला दर्ज़ होना चाहिए। अगर वे लोग पहचाने या पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया है। माननीय सदस्य ने अन्य जो बातें कही हैं, हम उनको ध्यान में रखेंगे।

जहां तक आप काम रोकने या काम चलाने की बात कह रहे है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हमारा तो काम चलाने का कार्यक्रम है। अगर कहीं ऐसा है तो आप हमारे ध्यान में व्यक्तिगत रूप से बात लाएं। अगर कहीं काम रुका हुआ है तो हम सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में हमने कहीं भी ऐसा नहीं चाहा है कि कहां काम ज्यादा हो और कहां कम हो। हम हिमाचल के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में काम को आगे बढ़कर गति देने के लिए काम करने वाले लोगों में से हैं और हम इस बात में विश्वास रखते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में जो बजटिड प्रोजैक्ट्स हैं वे गियरअप हों, तेज गति से उनमें काम हो और उन्हें रोकने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हां, जहां बजट प्रावधान नहीं है और बिना बजट प्रावधान के काम करने की बात आती है तो उसमें मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि तकनीकी ग्राउंड पर किसी काम में कोई बाधा आती है तो उन सारी चीजों को केस-टू-केस वैरिफाई कर सकते हैं, उन बातों को लेकर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में किसी विकास कार्य के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण हैं, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वहां उस काम को तेज गति से पूरा किया जाए।

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछला 30 करोड़ रुपया बकाया है की बात चल रही थी, मैं जानना चाहता हूं कि सुजानपुर के जो प्रोजैक्ट्स लम्बित हैं क्या सरकार उनको एक्सपेडाइट करने के लिए जल्दी-से जल्दी प्रयास करेगी? दूसरा, जिन अधिकारियों ने आपके आदेश की अनुपालना नहीं की है क्या उनके खिलाफ सरकार कोई ऐक्शन लेगी?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा कि नाबार्ड की जो बची हुई गुंजाइश है, उस गुंजाइश में, क्योंकि नाबार्ड की पूरी स्टेट के लिए एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंतर्गत ही वे पैसा देते हैं और यह पैसा ग्रांट की शेप में नहीं है बल्कि यह पैसा लोन की शेप में होता है। स्टेट के लिए बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोजैक्ट्स हमने भेजे

हैं, वे बहुत सारे लम्बित हैं। आपके चुनाव क्षेत्र के कौन-कौन से प्रोजैक्ट्स लम्बित हैं, उन पर गुण और दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

13.2.2019/1200/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1352

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है इसमें 990 हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं, इनमें कुछ अलॉटिड हैं, कुछ क्लीयरैंसिज़ के हैं, कुछ कमिशन्ड हैं और लगभग 5 मैगावाट से 19 मैगावाट तक प्रोजैक्ट्स हैं। यह बहुत लम्बी-चौड़ी सूचना होगी। क्योंकि यह बहुत लम्बी सूचना है, इसमें बहुत समय लगेगा।

13.2.2019/1200/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्या 1353

अध्यक्षः श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। (अनुपस्थित)

13.2.2019/1200/जेके/एजी/3

प्रश्न संख्याः1354

प्रश्न काल समाप्त।

13.2.2019/1200/जेके/एजी/4

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। ...(व्यवधान)... मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं है। ...(व्यवधान)... विषय रोज़ चले हुए हैं। आप लोग मुझे अगला विषय लेने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप मुझे नोटिस दे देते तो मैं आपको अलाउ कर देता। आपने मुझे नोटिस ही नहीं दिया। आप मुझे नोटिस दे देते। आप मेरे ध्यान में ला देते तो मैं अलाउ कर देता। ...(व्यवधान)...(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने सीट पर खड़े हुए) आप लोग बैठिए । मैं देता हूं। ...(व्यवधान)... आप नोटिस तो दे सकते थे। आप तो पांच बार के विधायक हैं। ...(व्यवधान)...इस विषय में सभी के खड़े होने का कोई कारण नहीं है। आप बैठिए मैं खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)... आप लोग बैठिए, तभी मैं समय दूंगा। ...(व्यवधान)... मुकेश अग्निहोत्री जी, एक मिनट, आप लोग क्यों आपस में बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... जब हम लगातार हर माननीय विधायक को समय दे रहे हैं। मैं हर्षवर्धन जी से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि बैठिए,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी

उसके बाद सारे खड़े हो करके समय देने के लिए बाध्य करना चाह रहे हैं तो वह उचित नहीं है। जब हर विषय में समय देने वाले हैं और दे रहे हैं ...(व्यवधान)... हर्षवर्धन जी, आप एक मिनट बैठिये। मैं खड़ा हूं और व्यवस्था दे रहा हूं। आप सबसे सीनियर आदमी हैं। थोड़ा-सा इंतजार तो करना चाहिए। मैं अगली उद्घोषणा कर रहा हूं और आप इतना भी वेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे पास नोटिस कोई नहीं है, सूचना कोई नहीं है।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको नोटिस दिया है।

अध्यक्षः आप कम-से-कम शांति तो रखिये।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण कोई इश्यु नहीं हो सकता है।

अध्यक्षः आप फिर बोलने लग गए हैं, मैं आपको समय नहीं दूंगा। अगर आप मेरे खड़े होते-होते बोल रहे हैं तो मैं आपको समय नहीं दूंगा। आप समय लेना चाहते हैं और उसके बाद भी मेरे खड़े होते-होते बोल रहे हैं। कोई नया व्यक्ति बोले तो समझ में आता है। आप मेरे से भी ज्यादा सीनियर आदमी हैं। श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आप दो मिनट अपनी बात बोल लें।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। यह विधायकों के प्रिवीलेजिज़, विधायकों के राइटस और विधायकों की फंक्शनिंग से संबंधित मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि विधायकों को एक साल में डिस्क्रिशनरी ग्रांट 7 लाख रुपये दी जाती है और जिन लाभार्थियों को हम वह पैसा सैंक्शन करते हैं उनको इसी वित्तीय वर्ष में वह पैसा देना पड़ता है। तीन व्यक्ति श्री संतराम, श्री मुख राम और श्री चमन लाल हैं मैंने इनको 20 हजार और 15-15 हजार रुपये सैंक्शन किये। मगर एस0डी0एम0 पांवटा द्वारा इनको जो चैक दिए गये हैं वे 5 अप्रैल, 2019 के दिए गए हैं। उसका मतलब है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए हैं। यह क्या इंटैंशन है? क्या यह जान-बूझकर किया गया है? यह इमेज

खराब करने की कोशिश है। एम0एल0ऐज़0 इंस्टिट्यूशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। एम0एल0ए इंस्टिट्यूशन को कमजोर करने की कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दो। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके कहने से, किसकी साजिश से हुआ है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने विधायक निधि विधायकों को दी है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पुरानी विधायक निधि के 34 लाख रुपये पैंडिंग पड़े हैं। जिसके बारे में मुझे असैम्बली क्वैश्चन के माध्यम से बताया गया कि अनस्पैंट मनी है। अनस्पैंट इसलिए है कि लैंड उपलब्ध नहीं है। कहीं एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस नहीं है। मैंने कई बार डी0सी0 से रिक्वैस्ट की कि इन स्कीमों को दूसरी स्कीमों में चेंज कर दिया जाए ताकि विधायक निधि के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सके। लेकिन मेरे लिखित रूप में देने और मौखिक रूप से बोलने के बावजूद तीन-चार महीने से यह पैंडिंग है। यह मज़ाक नहीं तो और क्या है? आप एम0एल0ऐज़0 इंस्टिट्यूशन को प्रोटैक्ट नहीं करेंगे, एम0एल0ए0 निधि और डिस्क्रिशनरी ग्रांट का इस तरह से मज़ाक उड़ाया जायेगा तो वह ठीक बात नहीं है। यह बहुत सीरियस मैटर है। मैंने आपको प्रिवीलेज का नोटिस दिया है। उस पर ऐक्शन लें और इस मामले को प्रिवीलेज कमेटी को रैफर किया जाए।

अध्यक्षः अगर प्रिवीलेज कमेटी को रैफर करना है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर क्यों देना है। फिर आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मामले की वस्तुस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि इस सारे विषय को ले करके इतना चिन्तित होने की या इस तरह से गुस्सा होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मनुष्य गलती का पुतला है और किसी से भी कहीं भी गलती हो जाती है। हमने डिप्टी कमिश्नर से पता किया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह टाइपिंग मिस्टेक है। क्लैरीकल मिस्टेक है। जिस 5 अप्रैल, 2019 के चैक का आपने ज़िक्र किया है, वह गलती से हुआ है।

मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने आवश्यकता नहीं है जब वैरीफाई कर लिया, जब बात हो गई है कि यह डेट गलती से उसमें लिखी गई है। ...(व्यवधान)...

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय मुख्य मंत्री जी, तीन चैक हैं।

मुख्य मंत्रीः दो चैक की मेरे पास जानकारी आई है। **तीसरे को भी वैरीफाई कर लेंगे।** इसमें छोटी अमाउंट 10 हजार या 15 हजार रुपये की बताई है। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि यह बड़ा भारी मसला हो गया है। सिम्पली यह एक क्लैरीकल मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है, जिसको डिप्टी कमिश्नर ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि इसको इस रूप में लेना चाहिए, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। एम0एल0ऐज़0 इंस्टिट्यूशन का मज़ाक करना, एम0एल0ऐज़0 इंस्टिट्यूशन के खिलाफ इस प्रकार की कोई बात हुई है, ऐसी बात मुझे लगती नहीं है। **इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसको हम ठीक करने के लिए कहेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी बातें न हों और गम्भीरता से इस विषय को लें।**

13.2.2019/1210/केएस/वाईके/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे, जो इन्होंने विधायक निधि के बारे में कहा, विधायक निधि के लिए जो एक व्यवस्था है, उसके अनुसार सभी जगह काम हो रहा है लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके वहां पर 34 स्कीमों में अनस्पैंट मनी पड़ा है। मेरे अपने ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र में और सभी विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में विधायक निधि का अनस्पैंट मनी इस कारण रहता है कि जब हमने काम करना होता है, कई बार लैंड का इशू आता है, कहीं कोई और इशू आ जाता है, कहीं डिस्प्यूट आ जाता है जिसके कारण अनस्पैंट मनी को एग्ज़िक्यूट करने में दिक्कत आ जाती है, पैसा अनस्पैंट रह जाता है। आपने उसको सबस्टिट्यूट करने की बात कही है क्योंकि वहां पर उस विधान सभा क्षेत्र में पहले और विधायक थे, अब और हैं । स्वभाविक रूप से इनकी मन्शा होगी कि जो अनस्पैंट मनी है, पहले जो विधायक थे, उनकी प्राथमिकता के हिसाब से उन्होंने दिया होगा, अब उन सबको बदलना है लेकिन मुझे लगता है कि यह भी बहुत अच्छी सोच नहीं है। मैं मानता हूं कि

अधिकार है। आज की तारीख में जो एम.एल.ए. है, वह उसमें चेंज कर सकता है लेकिन इसका अभिप्राय यह भी नहीं होना चाहिए कि आप सभी को बदलने लग जाए। ...(व्यवधान)... अगर 34 स्कीमों में अनस्पैंट मनी पड़ा है तो उसकी वजह तो जाननी पड़ेगी। कई जगह उसमें जमीन नहीं मिली है, ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं। हम वैरिफाई करेंगे। ...(व्यवधान)... आप सुनना ही नहीं चाहते।

अध्यक्षः हषवर्धन जी, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दो । ये उत्तर दे रहे हैं, आप इनको बोलने तो दो। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी जो मुझे जानकारी मिली है, जो दो चैक हैं, करैक्शन के साथ बैनिफिशरी को दे दिए हैं ...(व्यवधान)... तो क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि ये दो चैक हैं और तीसरे का पता कर रहे हैं। दो चैक की करैक्शन करके बैनिफिशरी को दे दिए हैं, यह हम कह रहे हैं। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि ये इसको वैरिफाई भी कराएंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने वैरिफाई करवाने की बात भी कह दी है। ...(व्यवधान)...एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं, अभी कन्फर्मेशन आ गई है कि 2 चैकों को ठीक करके बैनिफिशरी को एस.डी.एम. ने दे दिया है। तीसरे का आप ज़िक्र कर रहे हैं ...(व्यवधान)... इसमें क्या है, तीसरे का पता करेंगे।

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दो। इनके बाद आप बोल लेना।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई पहली बार चुना हुआ सदस्य इस माननीय सदन में इस तरह की बात करें, समझ में आता है लेकिन हर्षवर्धन चौहान जी तो कितने सालों से इस माननीय सदन में एक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरा आपसे

निवेदन है कि इन सारी चीजों को इस तरह से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कहीं भी विधायक निधि की बात है या ऐच्छिक निधि की बात है, विधायक जो लिखकर देगा, जो विधायक की प्राथमिकता होगी, उसके अधिकार क्षेत्र का विषय होगा, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होगी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10 तारीख को इन्होंने ऑनलाइन फूड पार्क का उद्घाटन किया। उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय वीरभद्र सिंह जी ने रखा था और उद्घाटन हरसिमरत कौर जी और इन्होंने ऑन- लाइन किया। अध्यक्ष महोदय, कार्ड छापे गए और केन्द्र के तौर-तरीकों के मुताबिक उसमें एम.एल.ए. का नाम मैंशन किया गया। 9 तारीख़ को वे कार्ड रिप्लेस किए गए। कम्पनी पर प्रैशर डाला गया कि इसमें एम.एल.ए. का नाम हटाया जाए । एम.एल.ए. का नाम हटाया गया और नया कार्ड छापा गया।

13.2.2109/1215/av/yk/1

यह बहुत गलत परम्परा बन रही है कि एक प्राइवेट कम्पनी जिसने फूड पार्क बनाया और उन्होंने कार्ड जारी कर दिया जो कि पब्लिक डोमेन में आ गये। लेकिन आप एक दिन पहले कार्ड से एम0एल0ए0 का नाम हटवाकर नये कार्ड पब्लिक डोमेन में देते हैं तो इस तरह से यह एम0एल0ए0 इंस्टिच्यूशन कभी मजबूत नहीं होगा। ...(व्यवधान)... आपने छपा हुआ कार्ड बदल दिया; यह क्या तौर-तरीका है? माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि कार्ड किसने बदला है? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य हर्षवर्धन चौहान जी, आप बोलिए।

श्री हर्षवर्धन चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो प्रिविलैज का नोटिस दिया है और अभी जो मुख्य मंत्री जी ने चैक्स के बारे में कहा है तो मुख्य मंत्री जी को फैक्ट्स की

जानकारी कैसे हैं? ...(व्यवधान)... मैंने चैक्स की तीनों कॉपियां माननीय अध्यक्ष महोदय को दे दी है। ...(व्यवधान)... मैंने तीनों कॉपीयां दे दी है। दूसरी मुख्य मंत्री जी ने जो विधायक निधि की बात कही है तो मुझे असैम्बली क्वैश्चन के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि अभी 34 लाख रुपये की राशि अनस्पैंट पड़ी है और उसमें राशि के अनस्पैंट रहने के कारण भी बताए गए थे। मैंने कई बार रिक्वैस्ट किया कि इस राशि को किसी नई स्कीम में यूज़ किया जाए। वहां आपकी पार्टी के पूर्व विधायक की पुरानी स्कीम्ज में मैंने ऐडिशनल पैसा दिया है। मेरी कभी भी यह मन्शा नहीं रही कि मैं पुरानी स्कीमों या पुरानी सैंक्शन्ज को रोकूं या चेंज करूं। जहां पर विधायक निधि से काम चल रहे हैं और कहीं काम बचा हुआ है तो मैंने वहां विधायक निधि से पहले भी पैसा दिया है और आगे भी दूंगा। मुख्य मंत्री जी, आप ऐसी सोच मत रखिए। वे आपके मित्र हैं, मैं यह जानता हूं। ...(व्यवधान)...मगर प्रश्न यह है कि यह एम0एल0ए0 इंस्टिच्यूशन से सम्बंधित घटना है और यह घटना केवल मेरे साथ नहीं घटी है बल्कि दूसरे एम0एल0एज0 की भी यही शिकायत है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों इसलिए इस बारे में आप कड़ी कार्रवाई करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप इस मैटर को प्रिविलैज कमेटी को दें ताकि हमें हकीकत का पता चले कि फॉल्ट किस स्तर पर है। अभी मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो आपको क्या पता, आपने कौन-सी फाइल या सैंक्शन देखी है? इसलिए आप इसको प्रिविलैज कमेटी को रैफर करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री वीरभद्र सिंह जी।

श्री वीरभद्र सिंह (अर्की) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीछे रोहड़ू में जाकर ऐसे कार्यों का उद्घाटन किया है जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। रोहड़ू में सीमा डिग्री कॉलेज का एक नया ब्लॉक बना और यह एक मल्टिस्टोरी बिल्डिंग है। वहां पर जो उद्घाटन पट्टिका लगी है उसमें से वहां के स्थानीय विधायक मोहन लाल ब्राक्टा का नाम गायब है। इसी तरह से वहां पब्बर नदी पर एक नया पुल बना उसमें भी स्थानीय विधायक का नाम गायब था और यह परम्परा

ठीक नहीं है। आपके नेतृत्व के मुताबिक ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। ...(व्यवधान)... यह आदत पड़ गई है कि जो ...(व्यवधान)... बीच में क्यों बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... इस गड़बड़ घोटाले में आप सब शामिल हैं और अभी मैं मुख्य मंत्री जी से बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में एक पैसा भी नहीं लगा। पहले जो ड्राफ्ट गया था उसको बदलकर वहां के स्थानीय एम0एल0ए0 जिनके सौजन्य से ये काम हुए हैं उनको आपने बाहर कर दिया जो कि आपको शोभा नहीं देता। This is a very cheap politics. आप उसकी दुरुस्ती करवाईए।

13/02/2019/1220 /टी0सी0वी0/डी0सी0/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। इन व्यवस्थाओं का पतन कहां से शुरू हुआ, ये दौर अभी से शुरू नहीं हुआ है। हम तो फिर भी धीरे-धीरे उसको जितना मैंटेन किया जा सकता है, करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बहुत लम्बे समय तक इस सदन में विधायक और मुख्य मंत्री के रूप में काम किया है। हम जब उस तरफ (विपक्ष) थे तो हम भी इस पीड़ा को वयक्त करते थे। लेकिन उस दौर में तो वह पीड़ा सुनी ही नहीं जाती थी। सरकार एक व्यवस्थानुसार चलती है। जिन परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान हम कर रहे हैं, उन सभी के उद्घाटन हमारी सरकार के दौरान होंगे यह संभव नहीं है। जिन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान या शुरूआत आपने अपने समय में की होगी, वह भी आपके समय में ही पूरी नहीं हुई होगी तो स्वाभाविक रूप से उन परियोजनाओं का उद्घाटन उनके पूरा होने पर ही होगा। आप जो कह रहे हैं कि जिन स्कीमों/योजनाओं में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा, उनमें वहां के विधायक का नाम लिखना चाहिए। ऐसी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत-सारी स्कीमें हैं। जब मैं मंत्री था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ रुपये की लागत से बी0डी0ओ0 का ऑफिर बनाया गया। इसके लिए बजट का प्रावधान और इसका शिलान्यास हमने किया। लेकिन आप इसका उदघाटन करने के लिए आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में यह भवन बनकर तैयार नहीं हो पाया था। हमने भी

इच्छा व्यक्त की थी कि आप उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, हम भी वहां पर होंगे तो हमारा भी उसमें नाम लिखा जाए। लेकिन हमारा पत्थर (शिलान्यास) उठाकर सीढ़ियों के पीछे लगा दिया और जिसकी हमने जमानत जब्त की थी, उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखकर उसके सामने लगा दिया गया।

दूसरा उदाहरण डिग्री कॉलेज सिराज का है। आपने उसकी नोटिफिकेशन की थी। हमारी सरकार बनी हमने उसके लिए बजट का प्रावधान किया और 7.50 करोड़ रुपये की लागत से इसके भवन को तैयार किया। उस समय स्वर्गीय श्री ईश्वर दास धीमान जी शिक्षा मंत्री थे। जब भवन बनकर तैयार हुआ तो आप पिछली सरकार के दौरान उद्घाटन करने के लिए आए। मेरे और धीमान जी के शिलान्यास के पत्थर को सुबह तक भी ग्राउंड में रखा गया। फिर मैंने जिलाधीश से बात की कि जो उद्घाटन किया जा रहा है उसमें हमारा नाम तो नहीं है, लेकिन वह पत्थर उस ग्राउंड में जहां शिलान्यास किया गया था, वहीं रखना उचित है? उसके पश्चात् आनन-फानन में उस पत्थर को सीढ़ियों के नीचे लगा दिया गया। ऐसी बहुत-सारी बातें है। लेकिन आपने सुझाव दिया है और हम इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। माननीय विधायकों का सम्मान करना, यह हम सबकी (पक्ष/विपक्ष) जिम्मेवारी है। इस बारे में बहुत-सारे माननीय सदस्यों ने लिखकर भी दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने विधायक प्राथमिकता की स्कीम का उद्घाटन भी उनसे करवा दिया जिसकी हमने जमानत जब्त की हुई थी। मेरे गांव का पुल टूट गया, हमने 2.00 करोड़ रुपये की लागत से उस पुल का काम शुरू किया और काम पूरा होने के बाद विधायक प्राथमिकता की स्कीम में भी हमारे नाम का ज़िक्र नहीं है।

13-02-2019/1225/NS/AG/1

पहले भी ऐसी बातें हुई हैं और अब इस परंपरा को ठीक करने की बात है और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। यह खुलेपन का अहसास आपको (विपक्ष) अभी महसूस क्यों हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता जी ने जो बात कही है कि इनका कार्ड छपा था और छपने के बाद इस कार्ड को बदला गया। यह हमारी जानकारी में नहीं है। मैं

जानकारी हासिल करूंगा। ठीक है, यह एक इंडस्ट्री थी और इस इंडस्ट्री को प्राईवेट सैक्टर में लगा रहे हैं तथा उन्होंने ही कार्ड बनाया था। केंद्रीय मंत्री ने आना था और मुझे भी जाना था। लेकिन हम दोनों ही वहां पर नहीं पहुंचे और विडियो कांफ्रैसिंग के माध्यम से उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद कार्ड के बारे में कि कार्ड छपा, यह बहुत छोटी सी बात है और मुझे लगता है कि इस बात पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में, हम इन सारी बातों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और हमें इसमें आप लोगों (विपक्ष) का सहयोग चाहिए। हम तो शुरूआत करने के लिए करते हैं लेकिन आपकी सरकार (विपक्ष) आने के बाद बदल दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पत्थर तोड़ने की बात है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8-9 स्थानों पर पत्थर तोड़ करके और यहां तक कि हमारे लगे हुए पत्थर मारतोड़ (घण) से तोड़े गए। एक जगह पर तो हद ही हो गई। एक जगह पर पुल टूट गया और हमने बालीचौकी के पास वैली ब्रिज़ लगभग 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया तथा जल्दी-जल्दी बनाया क्योंकि यह गांव के लिए एकमात्र रास्ता था। यह मामला पुलिस थाने में दर्ज़ था, जिस दिन उद्घाटन हुआ, वहां पर पत्थर को तोड़ने की कोशिश की गई, जब पत्थर नहीं टूटा तो ट्रक लाया गया और ट्रक का डाला पत्थर पर मारा गया फिर इसको तोड़ करके खड्ड में फैंक दिया गया। ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि ये सारी बातें ठीक नहीं हैं। ---(व्यवधान)--- इसलिए यह उस तरफ (विपक्ष) जो पीढ़ा हो रही है, यह हमें भी ऐसे ही होती थी, जब कहीं पर ऐसा होता था। लेकिन हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः आप बैठिए। ---(व्यवधान)---

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमीश्नर की तरफ से दो चैक दुरूस्त करके लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। आपने यहां पर तीन लोगों की बात कही है तो हमने तीसरे के बारे में पता करने के लिए कहा है। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह क्लैरिकल मिस्टेक (टाईपिंग) है तो मुझे लगता है कि इस विषय को ज्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः मुझे बोलने तो दो, आप चुप रहिए। आपने मुझे पत्र दिया है। उसकी एक प्रक्रिया है। सचिव, विधान सभा को यह पत्र प्रेषित कर दिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम

आपको निर्णय देंगे कि यह विशेषाधिकार समिति में जाना है या नहीं, इसका जवाब आएगा तो हम आपसे चर्चा करेंगे। ---(व्यवधान)--- इसका निर्णय पीठासीन से नहीं दिया जा सकता है। ---(व्यवधान)--- नहीं। Never. ---(व्यवधान)--- आपके तथ्य आ गए हैं, आप बैठिए। विधान सभा सत्र चला हुआ है, अध्यक्ष जो कह रहा है कि आपका पत्र आ गया है और इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होगी तथा इसके बाद आप क्या अपेक्षा करते हैं? ---(व्यवधान)--- आपको अभी ऑर्डर चाहिए। How it can be? ---(व्यवधान)--- माननीय मुख्यमंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे। ---(व्यवधान)--- ठीक है। ---(व्यवधान)--- जो नियम है, आपने पत्र दिया और आप लोग चाहते हैं कि इस पत्र का निर्णय मैं यहीं पर दूं, क्यों? It is not binding on me. ---(व्यवधान)--- उसका निर्णय मुझे करना है और

13.02.2019/1230/RKS/DC-1

...(व्यवधान)... मैंने यह कागज़ सचिव, विधान सभा को प्रेषित कर दिए हैं।...(व्यवधान)... आज निर्णय कैसे होगा? क्या आप अध्यक्ष को निर्णय थोपेंगे? आपने जो अभी पत्र दिया है, क्या उसके निर्णय के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा? ...(व्यवधान)... जो अपील आपने की है क्या उस अपील की कार्रवाई के लिए समय नहीं देंगे?...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान कागज़ात लेने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की चेयर के पास गए।)

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है उसका रुल्ज के मुताबिक निर्णय होगा। यह मामला आपके पास विचाराधीन है और समय पर इसका निर्णय दिया जाएगा। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन पर चढ़ रहे हैं जोकि माननीय अध्यक्ष महोदय की कुर्सी की अवमानना है। ...(व्यवधान)... प्रिविजेल तो आपके खिलाफ होना चाहिए।...(व्यवधान)... जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया कि यह मामला विचारधीन है।...(व्यवधान)... आपने जो पत्र दिया है उस पर विचार किया जाएगा। ...(व्यवधान)...आप रूल पढ़िए। क्या आपके कहने पर विचार

करेंगे? आपने प्रिविलेज उठाया है और इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। आपके कहने पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दे दी है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... प्रिविलेज आपके खिलाफ आना चाहिए।

(सत्तापक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

अध्यक्षः कृपया बैठिए, माननीय मंत्री जी बैठिए। कृपया बैठ जाइए।

माननीय सदन में बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य विराज़मान हैं। विधान सभा अध्यक्ष को लगातार विभिन्न विषयों के नोटिस दिए जाते हैं और अध्यक्ष उन सभी विषयों पर नियमानुसार निर्णय देते हैं। माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान ने अभी-अभी पत्र दिया, उस पर चर्चा हो गई, वाद-विवाद हो गया परंतु अध्यक्ष का निर्णय उसी समय आ जाए यह प्रकिया नहीं है। मैंने यह निर्णय दिया है कि जो पत्र मेरे पास आया है उसे पढ़ने के उपरांत तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी और माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य को इस पर एजिटेट नहीं होना चाहिए। जब विषय अध्यक्ष के विचाराधीन है तो सदन की आगामी कार्यवाही को बंद नहीं किया जा सकता। हम लगातार पिछले 25 मिनट से इस कार्रवाई पर लगे हैं। मैं पूरी तरह से यह व्यवस्था दे रहा हूं कि हम आगामी कार्रवाई जारी रख रहे हैं और जो पत्र हमारे पास आया है उस पर नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय विधायक को सूचित कर दिया जाएगा।

13.02.2019/1235/बी0एस0/डी0सी0-1

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)बी(2)-9/1999-एल दिनांक 30.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2019 को प्रकाशित हुए की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18;

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और

i. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18;

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या: 2.1 से 2.13 की समीक्षा पर आधारित तथा सावड़ा कुडडु हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के सभा पटल पर रखता हूं।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय मुख्य मंत्री जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019(2019 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कि हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित हुआ।

13.02.2019/1240/DT/HK-1

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदन आज जिस तरह से विपक्ष की ओर से उठाए गए मामलों को और उसके साथ-साथ उनके व्यवहार के प्रति बहुत चिन्ता प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, जब हमने स्वीकर कर लिया है की गलती हुई है, डी0सी0 का सन्देश आ गया कि दो चैक की कॉरेक्शन करके लाभार्थियों को भेज दी गई है, तीसरे चैक की पड़ताल भी जारी है। मुझे लगता है कि इससे आगे इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कलैरिकल मिसटेक हुई है । इस विषय पर नोटिस देने का अधिकार है और एक माननीय सदस्य की ओर से प्रिबीलेज मोशन मूव करने को कहा गया है। उसके बाद आपने एक व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य का नोटिस आपको प्राप्त हो गया है और उस पर विचार करेंगे उसके बाद हम निर्णय करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष माननीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि निर्णय इसी वक्त करो और अभी करो। यह आप से पहले भी परंपरा नहीं रही है। आपके पास जिस भी रूप में कोई नोटिस आता है तो आप नियम के अनुसार उसको अध्ययन करते हैं। अध्यन करने के बाद उस पर निर्णय करते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई करनी है और उससे आगे बढ़ कर अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य उठ करके आपकी कुर्सी के पास आ करके आपको इस तरह उंगली से अंकित करना और सचिव विधान सभा के पास जा कर कागज वापिस लेने की बात कहना, इस तरह की घटना आज से पहले कभी नहीं हुई। यह इतिहस बना करके चले गए। अध्यक्ष महोदय,इस माननीय सदन की एक गरीमा है कि जब कोई कागज

ले कर दिया जाता है तो वह इस सदन की संपति बन जाती है और उसको देने के बाद वापिस मांगना यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं एक माननीय सदस्य का व्यवहार देख रहा था, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वह खिलौने की दुकान से गुजरता है और वह खिलौने की जिद में दुकान के पास लेट जाता है। ऐसी स्थिति सचमुच चिंता का विषय है। जिन सारे विषयों को लेकन जो माननीय सदस्य की ओर से आग्रह आया है, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी अपनी बात कही है हम इन सारी बातों का जिक्र पहले भी करते रहे हैं। सारे विषयों पर निर्णय हो । यह मामला हमारे विचाराधीन है और इस पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन हम यह कहते रहे कि विधायक का नाम विधायक प्राथमिकता में तो डाला जाए। विधायक संस्थान मजबूत हो इस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस पर सबका सहयोग होना चाहिए। कुछ चीजों पर हमको भी परहेज करना पड़ेगा और कुछ चीजों पर उनको भी परहेज करना पड़ेगा तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो इस सदन में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ वह चिंताजनक भी है और वह निंदनीय भी है। हर रोज अखबार में खबर छपे उसका माध्यम ढुंढने की कोशिश की जाती है और मुझे लगता है कि यह प्रयास एक दिन की खबर बनाने के लिए ही किए जाते हैं। जो इस प्रकार की घटना इस माननीय सदन में घटित होती है वह लंबे समय तक याद रहती है कि किस आदमी का व्यवहार कैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सारी बातों का जिक्र करते हुए सारी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए इस माननीय सदन को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। सबके समक्ष सारी बातों को रखने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद हमारे मित्र अंदर-बाहर के क्रम से ग्रसित हो गए है। अच्छा रहेगा अगर आप इस पर सुधार करें।

13-02-2019/1245/एच.के./एन.जी./1

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमान सामान्य चर्चा एवं समापन

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2019-2020 बजट अनुमानो पर सामान्य चर्चा होगी । आज ही माननीय मुख्यमन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे । मेरे पास जो बोलने वालों की सूची

कांग्रेस विधायक दल से और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से प्राप्त हुई है उसमें कुल 11 नाम शामिल हैं । अगर हम सभी को बोलने का अवसर देंगे तो यह सायंकाल तक चलेगा। मेरा दोनो दलों से अनुरोध है कि वार्ता मैं शुरू करवा रहा हूं परन्तु वह इस सूची में विचार करके इसके अन्दर जो सुधार करना है वह मुझे करके दे दीजिए । अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी ।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 का बजट माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने 9 फरवरी, 2019 को इस माननीय सदन में पेश किया उसकी चर्चा में भाग लेने के लि आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह चर्चा दो दिन से जारी है और इसके जो मुख्य बिन्दु हैं उसके उपर हमारे दल की ओर से माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने इसमें जो फाईनैंशल शोर्ट-कमिंगस नजर आ रही हैं उस पर लम्बी चर्चा की है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बजट को शुरूआती तौर पर देखे तो इन्होंने 2019-20 के लिए ऐस्टीमेटड एक्सपैन्डीचर जो है it is estimated to be Rs. 44,388 crores and the revenue deficit for the financial year is targeted at 2342 crores, और साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि फिसकल डैफिसिट का टारगेट जो है वह 7352 करोड है which is 4.4% of GSDP. यह चिन्ता का विषय है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप टोटल रिसिप्ट देंखे तो इन्होंने एस्टीमेट किया है excluding borrowings जो इन्होनें ऐस्टिमेट लगाया है i.e 3524 crores. अब अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐक्पैन्डीचर और रिसिप्ट का डिफरैंस देखें तो it is almost 10,000 crores. जबकि आपने 2018-19 का बजट ऐस्टीमेट सदन में रखा तो उसमें में बोरोईंगस के लिए रखा था 6505 करोड की बोरोईंग करेंगे मगर आपने 7944 करोड बोरो किया that is almost 8,000 crores. अब आपने रखा है 7081 करोड from borrowings. How does that meet your gap? अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो बोरोईंग जो हैं it will go over 10,000 crores by your own documents.

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारी चर्चा हुई, मेरे छोटे भाई माननीय श्री राकेश पठानिया जी बात कर रहे थे फोरेन फडिंग की और बोल रहे थे कि हमें उसका वैलकम करना चाहिए । फोरेन फन्डिग का वैलकम करना चाहिए ऐसा आपने कहा । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी के साथ सहमत हूं कि फोरेन फन्डिग आई नहीं है, फोरेन फन्डिग को प्रस्तवित करने के लिए भारत सरकार से केवल अनुमति मिली है। How can that be counted as a Budget provision? यह तो बिलकुल ऐसे ही है जैसे नैशनल हाईवेज का था । माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की कि मुकेश अग्निहोत्री जी पिछले साल के बजट का जिक्र कर रहे थे, मगर श्री राकेश पठानिया जी तो उससे भी पीछे चले गए । यह श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो एक बजट पेश किया गया था उसको लेकर आए थे और कहने लगे की नैशनल हाईवेज का श्री वीरभद्र सिंह जी ने भारत सरकार का धन्यवाद किया, क्या हमने कोई गलती की ? हमने गलती की, क्योंकि हमे मालूम नहीं था की यह एक जुमला है । अगर हमें यह मालूम होता की यह जुमला है तो हम क्यों उसका धन्यवाद करते । तो आप भी एक ऐसा ही धन्यवाद मांग रहे हैं । यह जो आप 10 हजार रूपये की चर्चा कर रहे है neither this scheme has been formulated, nor it has gone for funding. इसकी तो कोई इन प्रिंसीपल भी कोई अप्रूवल नहीं है और

13/02/2019/1250/RG/YK/1

उसके लिए भी कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद कर दो। हम नेशनल हाइवे के लिए धन्यवाद करके तो आज तक पछता रहे हैं और अब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे भी अपने छोटे भाई के लिए चिन्तित हूं, मुख्य मंत्री जी आप इनका ध्यान रखिए, इनका वजन घटता जा रहा है। इनका वजन बहुत घट गया है और इनके कपड़े भी ढीले होते जा रहे हैं इसलिए इनका जो करना है, जल्दी करा दीजिए। मैं इनके बारे में चिन्तित हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बजट को देखें, इससे पहले कि हमारे मित्र यह कहें कि हमने किसी बात के लिए इनका धन्यवाद नहीं किया, तो मुख्य मंत्री महोदय, carrying on the tradition आपने एम.एल.ए. के इन्स्टीटियुशन को स्ट्रेन्थन करने के लिए थोड़ी सी जो आपने बढ़ौत्तरी की है और जो विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर सात लाख रुपये से आठ लाख रुपये किया है, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और जो आपने नाबार्ड की लिमिट को बढ़ाया, वह भी सराहनीय है। लेकिन ऐक्चुअल में जो एम.एल.ए. का इन्स्टीटियुशन है, उसको आप कब प्रोटैक्ट करेंगे? आज हमारे सदस्य जो बात उठा रहे थे, it is not a question कि डिप्टी कमिश्नर ने चैक करेक्ट कर दिया, it is a question that विधायकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? विधायकों की बात को ब्यूरोक्रेसी या ऐडमिनिस्ट्रेशन कितनी गंभीरता से ले रहा है?

(कर्नल श्री इन्द्र सिंह जी, सभापति महोदय पदासीन हुए)

आप इस इन्स्टीटियुशन को जब भी स्ट्रैन्थन करेंगे, कल श्री बरागटा जी भी कह रहे थे और मैं इस बात की शुरू से हिमायती रही हूं कि ये सारे जितने अधिकारी हैं, यह सारा कोई भी सेक्टर है, जब इनकी बारी आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो हम विधायक ही हैं जो हम एक-दूसरे का साथ नहीं देते और हम पार्टीज़ में बंट जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि एम.एल.ए. के इन्स्टीटियुशन को आप डिग्रेड मत होने दीजिए। जो नेता, प्रतिपक्ष के साथ कार्ड छापने में हुआ, it is beyond a certain limit, पत्थर पर नाम नहीं लिखा, वह हो सकता है। हो सकता है कि हमारे समय में भी हुआ हो और आपके समय में भी हुआ। मगर एक कार्ड छापकर और डिस्ट्रीब्युट करके, उसको चेन्ज करना, ठीक नहीं है। मैं समझती हूं कि उसको छापते ही नहीं, आप उनको पहले ही कह देते। लेकिन यह भारत सरकार के नॉर्म्ज हैं कि जो संबंधित क्षेत्र का विधायक होगा, वह चाहे किसी भी पार्टी का होगा, उसका नाम छपता है। तो फिर क्यों चेन्ज कराया गया?

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट है क्योंकि मुझसे पहले इस पर काफी सदस्य बोल चुके हैं और बहुत सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर हम हैल्थ सेक्टर की बात करें तो मुझे मैडिकल कॉलेज, चम्बा के बारे में एक बात फिर से इस सदन में बोलना अति आवश्यक है। उसका कारण यह है कि चम्बा मैडिकल कॉलेज अखण्ड चण्डी पैलेस में चल रहा है। चम्बा शहर भी एक हैरिटेज टॉऊन है और अखण्ड चण्डी पैलेस भी एक हैरिटेज बिल्डिंग है। उस हैरिटेज बिल्डिंग की रेस्टोरेशन के लिए ए.डी.बी. (Asian Development Bank) से पैसा आया हुआ है। यह फैसला हुआ था कि मैडिकल कॉलेज एक साल या डेढ़ साल वहां चलेगा और उसके बाद उसको सिरोल शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैडिकल कॉलेज शिफ्ट नहीं हुआ और मैडिकल कॉलेज की आधारशिला भी नहीं रखी गई जबकि पैसा उपलब्ध है और जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। सबसे दुःख की बात यह है कि अखण्ड चण्डी पैलेस के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। वह एक हैरिटेज बिल्डिंग है। मैंने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन किया था कि चम्बा की जो हैरिटेज प्रॉपरटीज़ हैं, उनको मेन्टेन किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए और जो यह मैडिकल कॉलेज चम्बा का है, इसकी जो दुर्दशा है, इसमें एक प्रश्न भी लगा था, मैं उस समय सदन में नहीं थी लेकिन मेरे बिहाफ पर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने वह सदन में उठाया था। उसकी इतनी दुर्दशा है कि अगर आपने इस बारे में जल्दी कदम नहीं उठाए तो एम.सी.आई. उसको de-recognise कर देगी। लेकिन आपने बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया। हम चाहते हैं कि इस मैडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्दी हो, इसकी बिल्डिंग जल्दी बने और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि क्योंकि यह सिरोल वाला भेड़ू फार्म वह इसके लिए ट्रांसफर हुआ है, कुछ बिल्डिंग वहां उपलब्ध हैं और कुछ बिल्डिंग जो आप prefab बिल्डिंग वहां तुरन्त सैट अप कर सकते हैं। जो आपके पास क्लास रूम्ज के लिए पैसा उपलब्ध है। क्योंकि वहां बिल्डिंग्ज पहले से ही उपलब्ध हैं। वहां बहुत थोड़ा काम है। अगर आपकी इच्छाशक्ति हो तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।

माननीय सभापति जी, सीमेंट प्लांट की बात आती है, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और अब फरवरी निकल गया। अब पता नहीं इसमें और कितना समय निकलेगा। लेकिन

यह चम्बा का सीमेंट प्लांट नहीं लगने वाला। क्योंकि इसमें शर्तें ऐसी हैं। यह चम्बा के लोगों की भावनाओं के साथ खेल करने का एक मात्र जरिया है।

13/02/2019/1255/MS/yk/1

जब लोकसभा का चुनाव आता है तो चम्बा का सीमेंट प्लांट निकलकर आ जाता है। सभापति महोदय, यह जो बहुत सारी रियायतें दी हैं और जिसका धन्यवाद करने के लिए ये कह रहे हैं कि किसी के 200/-रुपये बढ़ा दिए, किसी के 400/-रुपये बढ़ा दिए। उसमें मेरा यह कहना है कि ये पैसे आपने इसलिए नहीं बढ़ाए कि इसका कोई और कारण था बल्कि आपने इसलिए बढ़ाए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और यह आपकी मजबूरी है। आप टैक्स फ्री बजट दिखाना चाहते थे।

सभापति महोदय, यहां कहा गया कि आपने भी उधार लिया था और अगर हमने भी लिया तो इसमें क्या बुराई है। बात यह नहीं है बल्कि बात यह है कि आपने अपने विज़न डॉक्यूमैंट में कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी we will stop borrowings ...(व्यवधान)... यह आपके विज़न डॉक्यूमैंट में है। लगता है मुख्य मंत्री जी आपने अपना विज़न डॉक्यूमैंट नहीं पढ़ा है। उसको लिखते वक्त आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं थे या लिखते वक्त आपको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि अगर राजेन्द्र राणा जी आज यहां नहीं होते तो आज उस कुर्सी (मुख्य मंत्री जी की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए)पर कोई और होता। आप राजेन्द्र राणा जी का धन्यवाद करो और इनकी फोटो अपने दफ्तर में लगाओ। सभापति महोदय, ये जिन स्कीमों की बात कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। जो अभी तीन प्रदेशों में चुनाव हुए, वहां पर डॉक्यूमैंट्री फिल्म, छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म और ट्रेलर इनको नज़र आ गया है। देश का ट्रेलर यानी जो फुल फिल्म है, वह थोड़े दिनों में आने वाली है। इसलिए छोटी-छोटी रियायतें देकर ये लोगों को लुभाना चाहते हैं मगर बगैर पॉलिसी, ...(व्यवधान)...

मैं पहला शो जरूर देखूंगी और आपको साथ ले जाऊंगी क्योंकि आपको हमारे पास की जरुरत होगी। जब-जब आपको हमारे पास की जरुरत होगी तो सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इनको मैं अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। मैं सदन में इस बात को कह रही हूं।

सभापति महोदय, कल हमारे बहुत सारे नये माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा में भाग लिया और सब बहुत अच्छा बोले। श्री जवाहर ठाकुर जी भी बोले और पक्ष की तरफ से एक अन्य माननीय सदस्या भी बोलीं जोकि हमारी बहु भी है और बेटी भी है। आप बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलीं इसलिए आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं हालांकि आप बहुत अच्छे से और विश्वास के साथ बोली हैं।
सभापति महोदय, श्री राजेश ठाकुर जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। वे कल बजट भाषण पर जब बोल रहे थे अगर मैं चाहती तो उसी समय खड़े होकर बोल सकती थी। वे पहली बार सदन में आए हैं इसलिए सदन की और सदन के माननीय सदस्यों की मर्यादा का ध्यान किस तरह से रखा जाता है, यह उनको पता नहीं है। अपने भाषण में वे हमारे विपक्ष के नेता का जिक्र कर रहे थे। पहली बात यह है कि विपक्ष के नेता उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इनके बारे में कहा कि पत्रकारिता करते-करते ये राजनीति में आ गए हैं इसलिए ये उनका मुकाबला क्या करेंगे जो पढ़-लिखकर आई0ए0एस0 बने हैं।

कर्नल इन्द्र सिंह(सभापति)ः ये पहली बार चुनकर सदन में आए हैं।

श्रीमती आशा कुमारीः सभापति महोदय, मैंने कल इसीलिए कुछ नहीं कहा लेकिन आज मैं जरूर कहूंगी कि एक तो पत्रकारिता से संबंधित जितने लोग हैं यह उनका अपमान है और दूसरी बात, यहां जितने लोग बैठे हैं including Sh. Mukesh Aganihotri Ji, Sh. Jai Ram Thakur Ji, yourself and myself हम यहां किसी की मोहल्लत के मोहताज़ नहीं हैं। हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे बारे में अगर ऐसा कोई कहेगा तो he should take back his words पढ़-लिखकर का क्या मतलब है? क्या हम लोग अनपढ़ हैं? जो बाकी लोग सदन में बैठे हैं क्या वे अनपढ़ हैं? इस तरह की भाषा किसी के लिए यूज करना और वह भी विपक्ष के नेता के लिए यूज करना सही नहीं है। आश्चर्यजनक! उन्होंने एक बात और कही कि ये पानी पर रॉयल्टी के लिए गए थे। क्या उनको यह पता नहीं है कि पानी पर रॉयल्टी नहीं होती है बल्कि हाइड्रो इलैक्ट्रिक जनरेशन पर रॉयल्टी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि पौंग डैम के बारे में उस वक्त वीरभद्र सिंह जी क्या कर रहे थे। तो उनको मैं बता दूं कि उस वक्त वीरभद्र सिंह जी सैंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ रहे थे। पौंग डैम वर्ष 1961 में बना है। ज्ञान न हो तो न बोलना ही बेहतर होता है और अज्ञानी की

तरह यहां बात न रखी जाए। किसी के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना, पत्रकारों के बारे में इस तरह की बात करना और हमारे विधायकों के लिए इस तरह की बात करना। think, it is utterly shameful. और भविष्य में मैं उम्मीद करती हूं कि मुख्य मंत्री जी इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं होगा।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से मैंने यह बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कही लेकिन शायद मुख्य मंत्री जी को यह बात पसन्द नहीं आई। मुख्य मंत्री जी आपका जंजैहली बहुत खूबसूरत है इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि चम्बा में कोई खूबसूरती नहीं है। हमारा ऐतराज़ है कि अगर आपने चम्बा और डलहौजी में जंजैहली का बोर्ड लगाया है तो जंजैहली में भी एक चम्बा का बोर्ड लगा देते।

13.2.2019/1300/जेके/एजी/1

परन्तु आप जो जहां का है, वहां का लगाएं। माननीय सभापति महोदय, जब से रोहतांग में ओवर बर्डनिंग हुई है, the other passes which are available for crossing over in snow चम्बा में एक साचपास है और एक पदरी जोत है। दोनों जगह पर भारी संख्या में पर्यटक जाते हैं। इनको डवैल्प करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपने पौंग डैम बोर्ड बनाया है। क्या आप इस तरह से गोबिन्दसागर और चमेरा के बारे में भी सोचेंगे? मैं साच-पास की बात नहीं कर रही हूं ,चमेरा डैम की बात कर रही हूं, जहां पर आप नौका विहार कर रहे थे, मैं वहां की चर्चा कर रही हूं। आप उसको भी डवैल्प करें। चम्बा में अब सीमेंट प्लांट नहीं लगने वाला है। The only other avenue in Chamba for youth for employment is tourism. इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि चम्बा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। वैसे यह बजट से सम्बन्धित नहीं है परन्तु आज के न्यूज़ पेपर में मुख्य मंत्री जी, आपने भी यह हैडिंग देखी होगी और यह पंजाब केसरी की लीड स्टोरी है। "भरमौर में चुराह की दो पंचायतों में राशन खत्म" । मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूं। यह ट्राइबल एरिया है। आप तो यही कहेंगे कि यह कोई कांग्रेसी होगा, जिसने ये छाप दिया है।

यह हमारा न्यूज पेपर नहीं है। यह पंजाब केसरी है। असली बात यह है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। जो टेपा पंचायत चुराह में पड़ती है, उससे मैं वाकिफ़ हूं क्योंकि मेरा पुराना इलाका उधर लगता है आइल पंचायत में 6-6, 7-7 फुट बर्फ पड़ी हुई है। राशन की कमी है। क्या वहां पर भी आप हेलिकॉप्टर वगैरह भेज कर यह प्रबन्ध करवाएंगे, क्योंकि वे रास्ते खुलने वाले नहीं है? वे रास्ते कई दिनों तक नहीं खुलेंगे। अगर राशन की इस तरह से अव्यवस्था है और पांगी में चस्कबटोरी है, वहां पर ग्लेशियर आया है। वहां पर 40-50 लोग फंसे हुए हैं। वहां पर भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप यह दूसरी जगहों में कर सकते हैं तो चम्बा का भी ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूं।

सभापति महोदय, यहां पर ड्रग्ज़ को ले कर बहुत चर्चा हुई। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आपने पंजाब, हरियाणा और नॉर्दन रीज़न के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की। ड्रग बिल्कुल एक राक्षस का रूप ले लेता है। यह पंजाब में देखा गया है। वहां से हमें सीख लेनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी पंजाब की तर्ज़ पर एक स्पैशल टॉस्क फोर्स बनाएं। एस.टी.एफ.,जो कि सिर्फ ड्रग्ज़ से डील करें, अवेयरनैस से डील करें। आप जानते होंगे कि पंजाब में एक कार्यक्रम चला है - I am your buddy. उस कार्यक्रम के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को ड्रग्ज़ के बारे में शिक्षित किया जा रहा है कि ड्रग्ज़ से क्यों दूर रहना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, आप चाहेंगे तो उसकी रूपरेखा मैं आपको भिजवा दूंगी। It is called "I am your buddy" program. Drug Abuse Prevention Operation (DAPO) के तहत यह चल रहा है और यह एस.टी.एफ. चला रही है। STF is headed by DG Police. डी.जी.पी. रैंक या ए.डी.जी.पी. रैंक का ऑफिसर उसको हैड कर रहा है। वह मेन पुलिस से अलग है। वह सिर्फ ड्रग्ज़ के मामले डील करती है। जो बाकी केसिज़ वगैरह है, आप देखिए कि पिछले कल तुनुहट्टी में साढ़े तेरह किलो चरस के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया । Fortunately or unfortunately वह व्यक्ति मेरे ही चुनाव क्षेत्र से है। साढ़े तेरह किलो चरस बोनट में बांध कर ले जा रहा था, यह अखबार में मैंने सुबह देखा।

अगर हमारे लोग इस नौबत तक आ चुके हैं, तो prevention is as necessary, curative is as necessary and educative is as necessary as catching these people.

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसका हम समर्थन कर सके मगर आजकल मैं इनके एक नेता का जरूर समर्थन करती हूं। जो आजकल केन्द्र सरकार में सर्फेस ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो बात कही है, उसको भी जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि जो सरकारें या जो व्यक्ति झूठे सपने दिखाएगा, उसको पकड़ कर लोग जूते भी मारेंगे। यह आपके नेता नीतिन गडकरी जी की स्टेटमैंट है जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और आज केन्द्र में मंत्री हैं। ऐसे लोगों से आप कुछ सीखें और इस तरह की बातें बजट में न रखें जिनका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।

13-02-2019/1305/SS-AG/1

सभापति महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हमें उसको देखने की ज़रूरत है। अगर आप साहिवाल गाय की एम्ब्रीयो लाने की बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर बतायें कि उसे कहां से लाने का इरादा है क्योंकि साहिवाल गाय ओरिजनली पाकिस्तान से है। It is not from India. It is not indigenous to India. इसका सबसे बढ़िया ब्रीडिंग फार्म जालंधर के नज़दीक है। जालंधर के साथ ही वह साहिवाल गाय ब्रीड करते हैं। वह एक डेरा है और मैंने उनसे पूछा तो वे बोले कि हमको पाकिस्तान से लानी पड़ती है because this is not indigenous to India. पेशावर, पाकिस्तान से लानी पड़ती है। Sahiwal cow is not indigenous to India. अगर सभापति महोदय हमको सीरियसली यह बात करनी है। ...(व्यवधान)... देखिये मंत्री जी, आप डिस्टर्ब मत करिये। अगर आप अखंड भारत बीच में लाना चाहेंगे तो मैं फिर गडकरी पर आ जाऊंगी। उन्होंने फिर कहा है कि जो आदमी मेरे इलाके में इस तरह की बात करेगा तो मैं उसको यहां से भगा-भगाकर पीटकर निकालूंगा। यह मैंने नहीं बल्कि गडकरी जी ने कहा है।

सभापति महोदय, यह जो बजट है इसमें जिस तरह से बातें रखी गई हैं मुझे एक ही बात कहनी है कि आजकल की सियासत ऐसी है कि खुद ही हम कुछ करते हैं और फिर

खुद ही उस पर दुख मनाते हैं। उसके बारे में मैं खत्म करने से पहले आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। वैसे शेरों-सायरी सुनाने का दौरा उस समय था जब यहां पर उस तरह के लोग थे। लेकिन अब तो पढ़कर बात की जाती है।

"इस दौरे सियासत का इतना ही फसाना है;
खुद ही बस्ती को आग लगानी है और खुद ही मातम मनाना है।"

यह आपका हाल है। मैं इस बजट भाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने चम्बा की एक बड़ी सैंसेशनल खबर का यहां ज़िक्र किया। मैंने इस सारे विषय में कल सुबह, शाम को और आज भी सारे अधिकारियों से बात की है। देर रात कल चम्बा के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है। राशन की कमी के कारण भुखमरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बार पिछले साल के मुकाबले में चम्बा में ज्यादा बर्फ पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि पांगी का एक गांव जहां ग्लेशियर आया है उसके कारण तीन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन तीनों ही मकानों में जो वहां पर राशन था, वह भी मकानों के साथ नष्ट हुआ है। लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उन लोगों ने पहले ही घर छोड़ दिया था। वे पड़ोस के साथ वाले गांव में लोगों के साथ रह रहे हैं। राशन की व्यवस्था उनके साथ सांझे तौर पर कर रहे हैं।

दूसरी बात, हमने वहां पर पिछले कल एक टीम भेजी। वह टीम गांव तक पहुंच कर आई। गांव के लोगों से मिलकर आई और मिल करके वापिस प्रशासन को रिपोर्ट दी। राशन खत्म होने की अभी तक इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। लेकिन रास्ते में बर्फ ज्यादा पड़ी है। आना-जाना, उनको वहां से निकालना कठिन काम है लेकिन सब लोग सुरक्षित हैं। हमने इस बात को भी तय किया है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, अगर वहां पर अतिरिक्त राशन पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी तो हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस तैयारी में भी पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तैद हैं।

उसके बाद इन्होंने दूसरी जगह की बात कही। इस प्रकार की चम्बा के किसी भी गांव से खबर नहीं है कि राशन खत्म हो गया है। सभापति महोदय, आमतौर पर जो हमारे हाइट पर गांव होते हैं, जहां पर बर्फ पड़ने की सम्भावना होती है,

13.2.2019/1310/केएस/डीसी/1

वहां लोग पहले ही सजग रहते हैं और सर्दी के मौसम के लिए चार-पांच महीने का राशन पहले ही स्टोर कर लेते हैं। वहां पर अभी उचित मात्रा में राशन उपलब्ध है लेकिन अगर आपके पास कोई स्पैसिफिक इन्फोर्मेशन है, यह तो सिर्फ खबर है, मैं प्रैस रिपोर्टज़ की बहुत रिस्पैक्ट करता हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैंने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी गांव से इस प्रकार की खबर आती है कि राशन खत्म हो गया है और उसके कारण भूखमरी जैसी परिस्थिति हो गई है तो हम सरकार की ओर से सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में जिस भी माध्यम से राशन पहुंचाना पड़े, पहुंचाएंगे। दिक्कत थोड़ी सी जरूर हुई है, हमने बड़ा भंगाल में भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। वहां पर राशन भी पहुंचाया और जो वहां पर लोग फंसे थे, उनको वहां से उठाकर भी लाया है।

माननीय सभापति महोदय, जहां पर यह ग्लेशियर आया, वहां के गांव के लोगों से हमने आग्रह किया था, हमने पिछले कल वहां पर एक टीम भेजी थी उनके माध्यम से आग्रह किया था, मैंने कहा था कि उनको वहां से निकालो, शिफ्ट करो लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास पशुधन भी है इसलिए वहां से जाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर पशुधन भी सुरक्षित है और उनके लिए चारे की व्यवस्था वहां पर लोगों ने पहले ही कर रखी है। अगर उसमें और भी कुछ करने की आवश्यकता होगी, सरकार पूरा सहयोग करेगी।

सभापतिः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

13.2.2019/1420/av/hk/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन इससे पहले कि माननीय सदस्य अपनी बात रखें माननीय वन मंत्री जी एक स्टेटमैंट देंगे।

माननीय वन मंत्री द्वारा वक्तव्य

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांवटा साहिब में डिप्टी रेंजर व फोरैस्ट गार्ड को माफिया द्वारा गाड़ी से कुचलने का प्रयास दिनांक 12.2.2019 को सुबह 2 बजे रघुबीर सरन (डिप्टी रेंजर), बहराल ब्लॉक, माजरा रेंज को यू0पी0एफ0 सतीवाला, माजरा वन परिक्षेत्र, पांवटा साहिब वन मण्डल में स्थित खैर के वन की तरफ जाते हुए एक वाहन दिखाई पड़ने की सूचना मिली। खैर वन में कटान रोकने की मन्शा से डिप्टी रेंजर व फोरैस्ट गार्ड अमरीक सिंह, बीट सतीवाला अपने निजी वाहन से यू0पी0एफ0 सतीवाला की तरफ रवाना हुए जहां सतीवाला गांव के नजदीक उन्हें वन क्षेत्र की तरफ से तेज गति से आती हुई एक पिक-अप गाड़ी दिखाई पड़ी। इस पिक-अप गाड़ी को रोकने के उद्देश्य से फोरैस्ट गार्ड ने अपना निजी वाहन सड़क के बीच पार्क किया। पिक-अप के नजदीक पहुंचने पर जैसे ही फोरैस्ट गार्ड ने नीचे उतर कर पिक-अप जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एच0आर0 58ए0-1732 है, को रोकने का इशारा किया परंतु पिक-अप चालक ने तेज रफ्तार से वाहन फोरैस्ट गार्ड के निजी वाहन से भिड़ा दिया जिससे फोरैस्ट गार्ड घायल हो गया व उसके निजी वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पिक-अप अनियंत्रित होकर वहां नजदीक खेत में उतर गई। उसमें सवार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद फोरैस्ट गार्ड को पांवटा साहिब स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें पैर में चोट ज्यादा होने पर अगली सुबह यमुना नगर स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया जिन्होंने थाना पांवटा साहिब में

अभियोग (एफ0आई0आर0) संख्या 54/19, दिनांक 12.2.2019 जेरे धारा 353, 332, 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

इस घटना में आगे की कार्रवाई पुलिस व वन विभाग द्वारा की जा रही है। अभी तक की जांच में पुलिस द्वारा एक संदिग्ध मुलजिम की पहचान कर ली गई है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है तथा दोषी को पकड़ने हेतु पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वन विभाग द्वारा नजदीकी वन क्षेत्र यू0पी0एफ0 सतीवाला में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जंगल में निरीक्षण करने पर अभी तक खैर के दो पेड़ कटे पाए गए जिनका बाज़ार मूल्य लगभग 65000 रुपये है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका हार्दिक आभार।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि अपनी बात रखने के लिए थोड़ा-थोड़ा समय लें क्योंकि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिप्लाई भी देना है।

13/02/2019/1425 /टी0सी0वी0/एच0के0/1

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 फरवरी, 2019 को जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं भी उसके ऊपर बोलेने के लिए खड़ा हुआ है। यह बजट किसानों, कर्मचारियों और गरीबों का बजट है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो-जो सुविधाएं दी है, उनका तीन घंटे तक विस्तार से यहां सदन में उल्लेख किया। इस पर मेरे मित्रों ने भी अपने-अपने विचार बड़े विस्तृत रूप में रखें। मेरा ख्याल है, किसी को यह बात गले न उतरे, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने ईमानदारी की एक छाप छोड़ी है। इसी तरह से हमने भी शांता कुमार जी, ठाकुर राम लाल जी, श्री वीरभद्र सिंह जी और

माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। जब हम मिलने के लिए आते थे तो दो-दो घंटे बैठना पड़ता था फिर भी हमारी बारी नहीं आती थी और हम घर वापिस चले जाते थे। उस समय अगर कोई आदमी मुख्य मंत्री से मिल लेता था, हाथ मिला लेता था तो गरीब आदमी 3-4 दिन तक उस हाथ को साफ ही नहीं करता था। यहां पर भी एक ऐसी ही बात हुई और कहा गया कि स्वाइन फ्लू चला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया कहा कि I am suffering from Swine Flu. लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के पास तो सैंकड़ो लोग आ रहे हैं। पिछले दिनों यहां पर एक व्यक्ति आया और मैंने कहा कि यहां पर तो चुने हुए प्रतिनिधि आते है, आप पीछे जाइये। लेकिन वह मुख्य मंत्री के साथ ही चला हुआ था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री में इस प्रकार की सादगी है। आज एक गरीब परिवार से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। लेकिन अगर किसी को दिन में भी न दिखाई दे तो उसमें सूर्य की किरणों का क्या दोष है। मैं एक शेर प्रस्तुत करना चाहता हूं, वैसे मैं शायर तो नहीं हूं। लेकिन हमारे मित्र श्री अग्निहोत्री जी ने ये हमें भी सीखा दिया है।

"भला-बुरा न होता है कोई रूप से,
नज़र का भेद ही गुण दोष बताता है,
कोई कमल की कली देखता है किचड़ में,
किसी को चांद में भी दाग नज़र आता है॥ "

अध्यक्षः आपके कहने का मतलब है कि मैं शायर तो नहीं, पर जब से श्री मुकेश जी को देखा है, शायरी आ गई।

श्री रमेश चंद ध्वालाः वैसे मैं चुटकले तो सुनाता हूं लेकिन आज कुछ-न-कुछ शायरी भी करूंगा। इसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जैसे

गाड़ी का स्टेयरिंग, ब्रेक, सीट और शीशे का बराबर महत्व है और तब जा करके गाड़ी चलती है। इसलिए सभी वर्गों को कुछ-न-कुछ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैडम जी कह रही थी कि नये लड़के हैं और पहली बार चुन करके आए हैं, कुछ-न-कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पुराने विधायकों की भाषा पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में शिलान्यास और उद्घाटनों की पट्टिकायों को तोड़ने की बात आई है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में यही काम हुआ है। अब वहां पर 5-7 लाख रुपये लगेंगे तो काम पूरा होगा। पहले वहां पर काम पूरा नहीं हुआ और उद्घाटन कर दिए गए हैं तथा एक उद्घाटन नहीं बल्कि कई उद्घाटन किए गए हैं। मैंने वर्ष 2008 में एक पुल बनाया और उसका उद्घाटन वर्ष 2016 में हुआ। मैंने एक कम्युनिटी सैंटर के लिए वर्ष 2003 में लगभग 75,000 रुपये दिए और इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में हुआ। हमारे मित्र यहां से चले गए हैं और ये कह रहे थे कि जो भी स्कीमें चली हुई हैं, उनके नाम बदले गए हैं और ये स्कीमें हमने चलाई हैं। मुझे इस पर एक चुटकला याद आ रहा है। एक हरियाणा का जाट था और वह बस में बैठा हुआ था। बस में बड़ी भीड़ थी और उसको प्यास लगी तो वह सीट पर रूमाल रख कर बाहर पानी पीने चला गया। जब वह पानी पी कर वापिस आया तो कोई दूसरा जाट सीट पर बैठ गया था तो उसने बोला कि यह सीट मेरी है। दूसरा जाट बोला यह सीट तेरी कैसे हो सकती है? इस पर पहले वाले जाट ने बोला कि मैं इस सीट पर रूमाल रख कर गया था। तब दूसरा जाट बोला कि रूमाल रखने से क्या यह सीट तेरी हो जाएगी? पहले वाला जाट बोला हां, मैंने इस सीट पर रूमाल रखा था तो यह सीट मेरी है। इस पर दूसरा जाट बोला कि कल अगर मैं रूमाल तेरी लुगाई पर रख दूं तो क्या लुगाई मेरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का मतलब है कि जनता सब कुछ जानती है और पत्थर लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता जानती है कि किसने क्या-क्या किया है? मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि हमें इन छोटी-छोटी बातों पर नहीं उलझना चाहिए।

माननीय सदस्या ने कहा है कि "विधायक क्षेत्र विकास निधि" में वृद्धि की है और हम उसका स्वागत करते हैं और यहां पर इन्होंने दो-तीन बातों का और जिक्र किया है। आपको बहुत सारी योजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी, लेकिन ऐसी चर्चा करना कि कुछ नहीं हुआ। यह तो वही बात है और मैंने पहले भी सुनाई है कि एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया

मकान बनाया और उसने गृह प्रवेश के लिए सारे लोग बुलाए लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बुलाया। क्योंकि पड़ोसी अनाप-शनाप बोलता है, इसलिए मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा कि आपका पड़ोसी है, चलो आप बुला लो। उसने पड़ोसी को बुला लिया। जब पड़ोसी आया तो सारे लोगों ने उसके मकान की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि देखो, इसने बहुत अच्छी खिड़कियां बनाई हैं और फ्लोरिंग अच्छी की है और दरवाजे और अलमारियां बहुत अच्छी बनाई हैं। जब पड़ोसी के बोलने की बारी आई तो उसने बोला कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दरवाजे छोटे हैं। तब लोगों ने बोला कि दरवाजे बड़े कर देंगे। इस पर पड़ोसी ने बोला कि दरवाजे बड़े करो या न करो, यह आपकी मर्जी है, अगर अर्थी निकालनी हो तो दिक्कत होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिन्होंने बुरा ही बोलना है तो हम उनका क्या कर सकते हैं? दूसरी बात यहां पर यह बोली गई कि कर्ज ले करके सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री रिसोर्सिज़ भी मोबिलाइज कर रहे हैं। मैं तो हर बार यहां पर इस मुद्दे को रखता हूं कि जिला कांगड़ा में खैर के पेड़ इतने ज्यादा हैं कि हम सारे हिमाचल प्रदेश का कर्ज़ अदा कर सकते हैं। अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी के सब-डिवीजन से इसकी शुरूआत हुई है। वहां पर पहले ग्रीन फैलिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ था।

13.02.2019/1435/RKS/YK-1

आय के स्रोत के लिए जरूरी नहीं है कि हम ऋण ही लेंगे। यह बात इस तरह है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था और एक बहुत अमीर था। गरीब व्यक्ति पंडित जी के पास गया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। मुझे कुछ ऐसी चीज दो जिससे मैं अमीर बन जाऊं। पंडित जी ने कहा कि अमीर व्यक्ति ने शंखनाद की पूजा की है इसलिए यह इतना अमीर बना है। गरीब व्यक्ति शंखनाद की पूजा करने के लिए हरिद्वार चला गया और वहां पर बहुत दिनों तक तपस्या करता रहा। शंखनाद ने उसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। शंखनाद ने कहा आपको एक लाख, दो लाख, तीन लाख, दस लाख, पन्द्रह लाख या कितने पैसे चाहिए। गरीब व्यक्ति ने कहा कि आप कहते ही रहेंगे या कुछ देंगे भी। शंखनाद ने कहा कि मैंन क्या देना मैं तो पहले ही गपोड़शंख हूं। इस तरह

विपक्ष के साथियों ने भी गपोड़शंख वाला काम किया है। आज प्राइमरी स्कूलों में कॉलेज चले हुए हैं और अब उन कॉलेजों को बंद नहीं किया जा सकता। उन कॉलेजों को बंद करना हमारे लिए मुसीबत है। अगर हम बंद करेंगे तो आप कहेंगे कि इन्होंने बंद कर दिए। उन कॉलेजों को चलाना माननीय मुख्य मंत्री जी की मजबूरी है। एक मिडिल स्कूल में तीन-तीन बच्चे हैं और यहां तक कि कई स्कूलों में एक ही बच्चा पढ़ रहा है। मैंने कई बार विधान सभा में कहा कि education is the backbone of every country. लेकिन यहां पर तो बैकबोन ही तोड़ दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं-

भ्रष्टाचार है, सब जो कहते हैं नोटबंदी एक घोटाला है, भ्रष्टाचार है, सब जो कहते हैं नोटबंदी एक घोटाला है।

असल में तकलीफ उनको है जिनका दामन काला है और चौकीदार को चोर कहने वालो मोदी तो इस देश की दौलत का असली रखवाला है॥

क्या आपने आज दिन तक किसी घपले या घोटाले का नाम सूना है? आपके लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन जो चार पुश्तों से राजनीति में है उनकी पूंछ को आप छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन पर बहुत इलज़ाम लग रहे हैं। ई.डी. वाले पता नहीं उन्हें क्या-क्या कह रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वे रोडपति थे, आज वे करोड़पति हैं। इस तरह बहुत इलज़ाम लग रहे हैं। यह बजट बहुत अच्छा है और इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मैं एक बात कहने जा रहा हूं और इसका बजट बुक में उल्लेख किया गया है। 'कुल राजस्व प्राप्तियां 33,744 करोड़ रुपये है'। 'कुल राजस्व ब्याज 36,099 करोड़ रुपये और कुल राजस्व घाटा 2342 करोड़ रुपये है'। 'शुद्ध ऋण 5,068 करोड़ रुपये रहने का

अनुमान है'। 'पूर्व वर्षों में राजकोषीय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.14 तथा 5.16 प्रतिशत रहा'

13.02.2019/1440/बी0एस0/ए0जी0-1

जबकि वर्तमान में इस घाटे को कम करने का प्रयास किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 4.35 प्रतिशत होगा जो कि पिछले वर्षों की अपेक्षा कम है । लेकिन मैं रिसोर्सिज की बात कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जितने पर्यटक आते हैं वे यहां आ करके गंदगी फैलाते हैं। मैं समझता हूं कि उनसे बैरियर पर सफाई की व्यवस्था के लिए 50 रुपये अवश्य लिए जाने चाहिए । इससे हमारे प्रदेश में करोड़ों रुपये इकट्ठा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सुझाव आपके माध्यम से माननीय सदन में रखना चाहता हूं। इसके अलावा इंकम रिसोर्जिज जनरेट करने पड़ेगे। कल माननीय सदस्य ने जो कहां कहा, यह ठीक है माननीय शांता कुमार जी ने प्रयास किए, हाइडल प्रोजैक्ट्स के माध्यम से आज करोड़ों रुपये हमारे प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में और आय का साधन नहीं है। परंतु ऐसे रिसोर्सिज अगर हम पैदा नहीं करेंगे तो जितनी लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी प्रकार के कार्य होने चाहिए वह कार्य नहीं हो जाएंगे। आज स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, स्कूलों की बिल्डिंगों में कई स्थानों पर बच्चे ही नहीं हैं और जहां बच्चे हैं वहां पाठशाला के कमरे नहीं हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : महोदय, मैं बैठ रहा हूं। मेरे पास बहुत शेर थे परंतु जाते-जाते केवल एक ही पढ़ पाउंगा। यदि कोई ऑन लाइन टैंडर लेता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कई स्थानों पर ऑफ लाइन ही टैंडर आबंटित कर दिए गए हैं। ऐसी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कोई भी आदमी यदि एक रुपये का आरोप लगा देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन यह जो कह रहे हैं

कि हमारा संवाद और समन्वय वह जरूरी होना चाहिए। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बार- बार घंटी बजा दी है। अंत मैं अवश्य यह कहना चाहता हूं कि-

जीवन जीने के लिए तो सब लोग जिया करते हैं
लाभ जीवन का नहीं, परंतु फिर भी जिया करते हैं॥
मौत से पहले मर जाते हैं हजरों,
पर मरना उनका है, जो मर कर भी जिंदा दिखाई देते हैं।

इसलिए समाज में ऐसी छाप छोड़ करके जाएं ताकि यह समाज के लोग सदा-सदा के लिए याद रखें। इसके साथ ही मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं। जय हिन्द॥

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया 10 मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री नन्द लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय, ने वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान जो प्रस्तुत किया है। उप पर जो चर्चा चल रही है उसमें चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है । बजट निर्धारित करता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में क्या-क्या कार्य होने हैं। It is basically a statement of revenue expenditure and revenue receipts. यह हम सब को मालूम है। रेवेन्यू सीट में इसके साथ जो एंटीस्पेटिड रेवेन्यू होता है वह भी जोड़ा जाता है और एक्पेंडिचर है उसे प्रायोराटाईज करना सरकार का काम है। That is prioritization. उसका वेस्ट मेनेजमैंट है फाइनैंसियल मेनेजमैंट होता है। उस तरह से इसको किया जाता है। इस बजट में हम देख रहे हैं कि बोरोइंग वह एक मात्र सहारा है। उसके सहारे यह बजट चल रहा है। हमारी जो

रिसीट साइड है उसमें रिसोर्जिज जनरेशन का कोई नाम नहीं आ रही है। पिछले साल जो हमने देखा है उन कमियों को पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्जिज हैं, रिसीट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे पावर सैक्टर की बात की जाए तो पावर सैक्टर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सैक्टर है। जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप खुद इस बजट में लिख रहे हैं कि एक साल के अंदर कितना इसको स्लोडाउन किया है। पावर सैक्टर लिट्रली फेल हो चुका है। पावर जनरेशन की तो बात अलग है । इस बजट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको पावर सैक्टर को इंप्रूव करके हम अपना पावर जनरेशन बढ़ा सके ।

13.02.2019/1445/DT/AG-1

इसी तरह से टूरिज्म कितना बड़ा सैक्टर है, बहुत ज्यादा पोसिबिलिटी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए टूरिज्म में है । इसमें भी हमने देखा जो अभी इण्डिया टूडे ने सर्वे किया है उसके अनुसार जहां इसमें हमारा सैकिण्ड पोजिशन होती थी और अब हम 20 वें स्थान पर है। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म को लेकर इस बजट में कुछ देखने को नही मिल रहा है सिवाय ईको टूरिज्म के । इसमें भी तीन से चार कमरे बना देने से नहीं होगा। यहां कोई ऐसी कंकरीट पॉलिसी लानी होगी जिससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिले और हमारा रेवन्यू भी बढ़े। आज फोरन टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने की बात हो रही है । एग्जिस्टिंग जो हमारा टूरिस्ट को एट्रेक्ट करने के लिए सिस्टम है वह cleanliness है, better road connectivity है, हाइजिनिकली ठीक होनी चाहिए और लॉ एण्ड आर्डर ठीक होना चाहिए। लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए ताकि टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सके। सबसे जरूरी चीज है इसमें रोड़ कंनैक्टीविटी है। अभी इस बजट में रेल की कोई बात नहीं है mode of transport में rail is very important. और आपका जो एयरपोर्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ! अभी यहां इन्टर नैशनल एयर पोर्ट की भी बात की । यह बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है । मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के दिन में गग्गल एयर पोर्ट है, जुब्बडहट्टी एयर पोर्ट है इन दोनों एयर पोर्टों को हम एक साल के

अन्दर इनके रनवे को बढ़ा सके जिससे बड़े जहाज यहां आ सके और टूरिस्ट आट्रेक्ट हो सके । तो इस बजट में इस पर भी कोई चर्चा नहीं है वैसे लिखा है कि अंन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट यहां पर बनाया जाएगा यह अच्छी सोच है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा जो हमारे एग्जिस्टिंग एयर पोर्ट है इनको दुरूस्त किया जाए ताकि जो दूसरे बड़े जहाज हैं वह लैंड कर पाएं । इसी तरह से रोपवे ट्रोली की बात करें तो यह टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2016-17 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने तीन रोपवे ट्रोलिज़ का बजट के अन्दर प्रावधान किया जिसमें हमारे सराहण में एक रोपवे ट्रोली लगनी है, बशलकंढा में रोपवे लगनी है,

मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं । बशलकंढ़ा का जो टौप है उसमें कई किलोमीटर का एक स्ट्रैच है उस पर और भी कुछ सोचा जा सकता है तो इस रोपवे ट्रोली के लिए कोई बजट नहीं डाला गया ।इस बार भी नही और पिछले बजट में भी नहीं । मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि यह इतनी इम्पोरटैंट जगह है। टूरिस्ट स्पोट है अगर उस जगह में हम इस रोपवे को डाल दे क्योंकि पिछली सरकार ने भी इसके बारे में सोचा था । मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं इस पर भी गौर की जाए और इस रोपवे ट्रोली को भी इंक्लूड किया जाए जिससे कि इस एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। केन्द्र सरकार से भी इस दिशा में उम्मीद नहीं है जिससे कोई रहत मिलेगी, जिससे आपके रेवन्यू में बढ़ावा हो सके और आप बात करते है विजन डॉक्यूमैंट की इसमें अभी तक कुछ नहीं आया। एक दिशा होती what all we have to do in a particular financial year. कोई डारेक्शन नही है उस पर आपने कोई बात नहीं की और इसलिए अगर इसको I should not say that it is directionless. मगर कोई दिशा नही है तो इसको डरैक्शन लैश कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नही है ।

अध्यक्ष महोदय,जैसे मैंने कहा है वित्तीय मेनैजमेंट होता है। वर्ष 2016 -17 का बजट, वर्ष 2017-18 का जो बजट है, इसमें अगर आप देखें तो वित्तीय मेनैजमेंट में तत्कालीन

मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का कोई मुकाबला नही है । वर्ष 2016-17 का अगर बजट देखो आप उस बजट के अन्दर आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं in those five years जो प्रदेश के अन्दर रोड़ क्नैकटीविटी की बात है, पुलों की बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना यह सारी बातें वर्ष 2016-17 के बजट में हुई जो हिमाचल प्रदेश में basic facilities/amenities लोगों को मिलती है that was the maximum. वह सारा फाइनैंशियल मैनेजमेंट था। अब शिमला में देख लीजिए स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है ।स्वास्थ्य विभाग के अन्दर आप खुद जानते है। अध्यक्ष महोदय ,

13-02-2019/1450/डी.सी./एन.जी./1

शिमला के अन्दर जैसे आईजीएमसी है, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है और दूसरे जो अस्पताल हैं उसमें जो एक्सटैंशन है, construction of new OPD block and new Deen Dayal Upadhyaya hospital, यह राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी । काम चल रहा है। Government is in continuity, जो प्रोजैक्ट शुरू किए हैं वो आपको आगे बढाने हैं और उसमें कोई एहसान नहीं है । It is a obligation and you have to do it. इस तरह के फाईनैनशियल मैनेजमैंट की वजह से उन्होने बहुत अच्छे काम किए हैं । इस बजट में इस तरह की सोच हमें दिखाई नहीं है जिससे ओवरआल डैवलपमैंट पुरे प्रदेश की हो पाए । अब नैश्नल इकोनोमी की बात करे तो इस पर एक बडा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि एक बहुत लीडिंग इकानोमी है । In 2017-18 GDP growth was 6.7 and now in 2018-19 is 7.2%, inflation rate 2.9%. हम ये जो बजट ऐस्टीमेट देख रहे हैं, यह डेफिसिट देख रहे हैं, इन्फलेशन देख रहे हैं, basically it is jugglery of figures. मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक पैरा लिखा हुआ है 'prices under control' । मैं अपको बताना चाहूंगा की 2018 के अन्दर पैट्रोलियम प्रोडक्ट में जिस हिसाब से उसकी किमत बढी है, it is a record in itself. पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढने से हर चीज में महंगाई आएगी यह ओटोमेटिक है, क्योंकि उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन अंगेजड है, कई और चीजें अंगेजड है । तो आपका यह कहना की प्राईसिस को बडा कन्ट्रोल में रखा यह भी कोई तर्कसंगत बात नहीं लगती हमको । वैसे ही जीएसटी है और दूसरी चीजें हैं, कभी छोटा किया जा रहा है,

कभी बडा किया जा रहा है, इसमें बहुत से प्रैक्टीकल हो रहे हैं, इसके कारण हमारे छोटे-छोटे व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ । कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्राईसिस पर कन्ट्रोल करने की बात आपने कही है यह हमको तर्क संगत नहीं लगती । आपने जो एक विजन बना रखा है कि doubling the farmers income, इसमें अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा अभी केन्द्र की सरकार ने मात्र 6 हजार रूपये एक साल के लिए एक किसान को मिलना है । कितने किसान हमारे कर्ज की वजह से और उसे वापिस ना लौटाने की वजह से मर गए हैं । उसकी एवज में इस बजट में कोई भी थोडी सी भी राहत की बात नहीं की गई है और यह बहुत ही दुःख की बात है । यह सिर्फ एक नारा है कि doubling the income और यह पता नहीं कौन सा जुमला है । इसमें एक चीज और आई है legacy of acute shortage of financial resources. मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि जब आप टेकओवर करते हैं once you are in power, it becomes your responsibility to take over everything. ये कब तक इस तरह कि मानसिकता रहेगी कि यह पिछली सरकार ने किया है । Now you are in Government और continuity में जो सरकार है उसे यह मानसिकता जरूर बदलनी पडेगी । क्योंकि ऐसा चलता रहेगा और जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा हमारे यहां कोई काम नहीं होगा । I have to pass the buck to the other side. उस वक्त ऐसा हुआ था और हम यह करना चाहेंगे और हमे यह मानसिकता बदलनी होगी क्योंकि इसमें इफैक्टिव इम्पलीमैंट नहीं हो पा रहा है । अभी सरकार का जो फोकस है इस बजट में that is on agriculture और फोकस क्या है that I don't know because हमारा agriculture produce has gone down in 2018. हार्टीकल्चर इतना बडा सैक्टर है उसका जो प्रोडयूज है 5.56 लाख मिट्रिक टन से it has gone down to 4.5 metric tons, straightway 1.5 लाख मिट्रिक टन का नुकसान हुआ है, उस पर कोई कम्पलीट पोलिसी लानी होगी सरकार को । सिर्फ नूतन पाली होउस/ग्रीन हाउस बना दिया जिसका नाम पहले दीनदयाल उपाध्याय था और जिसमें छोटी सी सबसिडी का अनाउन्स किया है । यह अच्छी बात है और इसके लिए भी हमें कम्पलीट पोलिसी लाने की जरूरत है और अपनी प्राथमिकता बदलने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि फूड स्कियोरिटी की एक बात इसमें आई है, अच्छी बात है । उज्जवला योजना है इसमें कई लोगों को लाभ मिला है ।

अध्यक्ष : श्री नन्द लाल जी प्लीज जल्दी किजीए ।

Sh. Nand Lal : Sir, I will take a minute more. इसमें बडे लोगों को गैस मिली और इन्स्ट्रूमैंट भी मिले । क्या आपको यह मालूम है कि पहाडों में पूरे विंटर के अन्दर हम लोक लकडी जलाते हैं, ये वहां पर जो गैस का कनैक्शन है यह सेफ नहीं रहता । हर घर में लकडी का एक चुल्हा जलता है । लकडी लाते हैं लोग कैसे लाते हैं, लीगल लाते है, इललीगल लाते है, I can't say anything लेकिन

13/02/2019/1455/RG/DC/1

हमें पर्यावरण नियंत्रण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर सोचने की जरूरत है कि पहाड़ के लोगों को तो आग जलानी ही है। वे गैस से गर्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस पर भी सोचने की जरूरत है। इसलिए जो आपने यह उज्ज्वला योजना शुरू की है। इसके साथ-साथ इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। But at the same time, इस पर भी लोगों को एक सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उस पर कुछ कर पाएं। --(घण्टी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को काफी चीजें हैं लेकिन यहां समय की कमी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वाटर सप्लाई स्कीम की जो बात हो रही है, इसमें भी हमारे इर्रीगेशन की यहां ऐसी स्कीमें हैं। अभी जो सरकार का फोकस है, that is on conservation of water और यह बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जो वाटर लिफ्ट कर रहे हैं तो लिफ्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। हमारे यहां जो छोटे-मोटे नाले हैं, उनको इस तरह टैप किया जाए so that the water could be utilized for irrigation or drinking purpose. इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सर्वे किया जाए और पानी को यूज करने या कंजर्व करने के लिए कोई सिस्टम अडॉप्ट किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नन्द लाल : माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मुझे यह कहना है कि जहां तक पानी की बात है तो हमारे यहां दो बड़ी स्कीमें हैं कुरपन खड्ड से ननखड़ी वैली में पानी जा रहा है, एक सैरी खड्डा से बाराबीश और डांसा एरिया है। उस स्कीम में जब हम पूछते हैं कि क्या है?

The work of these schemes is almost finished, 85 से 90 प्रतिशत तक काम हो चुका है। सिर्फ बजट की वजह से इन दोनों का काम नहीं हुआ। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि उसमें जो भी फण्ड्ज की जरूरत है, वे दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में थोड़ी बात और कहना चाहूंगा। शिक्षा में बहुत से लोग कहते हैं कि इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूल में दो-तीन बच्चे थे। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि जो राइट टू ऐजुकेशन है, यदि उसको अप्लाई करना है तो सब जगह स्कूल-कॉलेज चाहिए और उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि in the last one year कि इतने लाखों बच्चों को आप यूनिफॉर्म नहीं दे सके। यह बड़े शर्म की बात है। एक और बात यह कि जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कॉलरशिप का प्रावधान है, अगर कोई घोटाला हुआ है तो you investigate that but fact is कि एक साल से उनको इस सुविधा से महरूम किया जा रहा है।

अध्यक्ष : अब मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। कृपया अब आप समाप्त करिए।

श्री नन्द लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो ऐस्टीमेट्स यहां प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें कुल मिलाकर आपके पास एक सौ रुपये में 39.56 प्रतिशत पैसे हैं। अब इन 39 रुपये में आप हिमाचल प्रदेश में विकास की क्या गतिविधियां करते हैं, यह हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे। कृपया आठ मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिए। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर भी देना है।

श्री बलबीर सिंह(चिन्तपुरनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट को यहां प्रस्तुत करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय का जहां धन्यवाद करता हूं वहीं सराहना भी करता हूं। मैं मानता हूं कि इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय ने गांव के गरीब, मजदूर और रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले दैनिक मजदूरी करने

वाले व्यक्ति की चिन्ता करके एक बहुत ही अच्छा बजट यहां प्रस्तुत किया है। मैं पुनः इसकी बहुत-बहुत सराहना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नेता, प्रतिपक्ष की बात है, तो वे काफी बोले। आपने उनको बोलने के लिए 45 मिनट दिए थे और यह उनका अधिकार भी था। लेकिन मैं मानता हूं कि वे वर्तमान की बात न करके केवल मात्र वर्ष 2022 तक टिके रहे। वे बार-बार कहते रहे कि वर्ष 2022 में आप इस प्रदेश को कंगाली के कगार पर खड़ा कर देंगे और उन्होंने वर्तमान की चिन्ता कतई नहीं की। उन्होंने बजट को कतई नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि यह सरकार तो कागज़ी संसार पर घूम रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके समय में क्या कागज़ किसी दूसरे प्रकार के थे।? क्या बजट बुक ऐसे नहीं बना करती थी? इसलिए हमारे लिए कागज़ी संसार की संज्ञा देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आपके पास नगर निगम शिमला से लेकर और प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपका साम्राज्य है तो सब कुछ बदल क्यों नहीं दिया जाता?

13/02/2019/1500/MS/yk/1

मैं इनको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद आपका भी पूरे भारत में एकछत्र साम्राज्य रहा है परन्तु आप उसमें गरीबों की चर्चा नहीं किया करते थे। अगर आप चर्चा करते भी थे तो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। एक बार ऐसा भी माहौल था कि केन्द्र में 484 एम0पी0 आपके पास थे लेकिन गरीबों की बात नहीं कही गई। बहुत सी योजनाओं के लिए नेता प्रतिपक्ष ने नाम ले लेकर कहा कि ये तो उस वक्त की योजनाएं हैं, जब हमारी सरकार थी और मुख्य मंत्री आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे। एक माननीय सदस्य ने तो अपने 15-20 मिनट के भाषण में यही कहा कि जब मैं मंत्री था और राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब की ये बजट बुक है और तब की ये सारी योजनाएं हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर आलोचना किस बात की है? अगर ये सारी योजनाएं आपके समय की हैं और इसमें आपका ही किया हुआ सारा दर्ज़ है तो आलोचना क्यों कर रहे हैं? इसका तो आप सबके द्वारा पक्ष लिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप ही सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और अपने ही दल में आप प्रतिस्पर्द्धा से भी कुण्ठित हैं। आपकी वाकपटुता, बॉडी लैंग्वेज, उछल-कूद और बार-बार पत्रकारों की ओर निहारना इस ओर

इंगित करता है कि आप इस प्रतिपक्ष की सीट से छलांग लगाकर एक नम्बर की सीट को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं इनको सचेत भी करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आपके लिए रुकावट हम नहीं हैं और आपके रास्ते में हम कांटे नहीं हैं। आपके रास्ते में अगर कोई कांटे हैं तो वे इनके पास ही हैं और वे कांटे इनके अपने दल में ही हैं क्योंकि बहुत से लोग प्रतिस्पर्द्धा में हैं। इसलिए मैं इनको सचेत करना चाहता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष को इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्भल कर छलांग मारने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण के अन्त में एक व्यथा से पीड़ित दिखे कि हमने एक नई योजना "मेरा परिवार भाजपा परिवार" शुरू कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इससे इनको क्या तकलीफ है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने जन-मानस का काम किया है तो जन-मानस से लोकतंत्र में वोट मांगने का, वोट बनाने का और उस परिवार को अपने साथ जोड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पास है परन्तु आपने क्या किया? देश की आजादी के तीन दशक तक आप इस देश की जनता को गुमराह करते रहे। आपने कहा कि इस देश की आजादी में कांग्रेस के सिवा किसी का कोई रोल ही नहीं है। सन् 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी और उसे झांसी की महारानी ने शुरू किया था। क्या आप उसको भूल गए हैं? आप क्या सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानी को भूल गए हैं? फिर आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ही इस देश को आजाद करवाया है। इतना ही नहीं, तीन दशक तक इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को फेल करने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया कि इस देश में अन्य दलों को अछूत बनाकर रखा और कहा कि केवल-मात्र यहां कांग्रेस है और कोई अन्य दल नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि आपको 60 साल इसलिए सत्ता नहीं मिल पाई क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि 60 साल आपने इस देश के वोटर को गुमराह किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी को ...(घण्टी)... दोहरे चरित्र वाली पार्टी मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय एट्रोसिटी के बारे में एक फैसला करता है कि किसी व्यक्ति के अंगेस्ट जब एट्रोसिटी का केस बनता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और वह जांच डी0एस0पी0 लैवल का अधिकारी करे। उसमें

ये कहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान ही खत्म कर दिया है परन्तु जब अपने-अपने क्षेत्रों में इनके नेता आते हैं तो सम्माननीय समाज के पास खड़े होकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं।

13.2.2019/1505/जेके/एजी/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को माननीय सदन में रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि इस देश की पीड़ा और इस देश के सामान्य वर्ग की पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने समझा है। सामान्य वर्ग के गरीब को 10 प्रतिशत आरक्षण दे करके उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा लाभ उनको दिया है। इतना ही नहीं कब से अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 परसेंट था। जिसे मंडल कमिशन कहा करते थे लेकिन दस-दस साल लगातार शासन करने के बावजूद भी इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। मैं, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 27 प्रतिशत तक आरक्षण का संवैधानिक दर्ज़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया। यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय अर्थ-व्यवस्था विश्व में तीव्र विकास दर प्राप्त करने वाली अर्थ-व्यवस्थाओं में शुमार हो चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष वर्ष 2018-19 में ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देना है।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनट लेना चाहता हूं। इस देश में कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था परन्तु आज परिस्थिति ऐसी है कि 40 हजार करोड़ के यू0एस0ए0 डॉलर के मुताबिक यहां पर विदेशी मुद्रा का भण्डार है। पिछले वर्ष निर्यात में भी 13.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात जरूर करना चाहूंगा कि ये सारी योजनाएं समाज के कमज़ोर वर्ग पीछे न छूट जाए, इसलिए शुरू की हैं। उसमें प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री सौभाग्य

योजना, प्रधान मंत्री उज्जवला योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री जन-धन योजना, प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत, ये सभी गरीबों के हित की योजनाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक मिनट लूंगा। मुझे कल भी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप बार-बार अपने भाषण में डॉ भीमराव अम्बेदकर का नाम लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड में यह भी दर्ज़ करवाना चाहता हूं कि डॉ भीमराव अम्बेदकर का नाम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए और मेरे समाज के लिए डॉ0 भीमराव अम्बेदकर किसी भगवान से कम नहीं है। अगर वे नहीं होते तो मैं यह दावा करता हूं कि इस सदन में मेरे जैसे लोग नहीं बैठ सकते थे। केवलमात्र राजा, महाराजा और उनके परिवार के सदस्य ही यहां बैठ सकते थे। ये वही महान शक्ति थे, ये वही महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में आरक्षण दिया और उनकी वजह से आज हम इस सदन में सदस्य बनें और इस माननीय सदन का एक हिस्सा है। अब आप याद कीजिए वर्ष 2008 ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में कितनी सरकारें रही और कांग्रेस को कितना वक्त मिला, ये दलित वर्ग का नाम तो लिया करते थे लेकिन दलित वर्ग के लिए कुछ नहीं करते थे। वर्ष 2008 में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार आई। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के लिए बजट में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जाए। उस वक्त वर्ष 2008 में 24.72 प्रतिशत का प्रावधान हुआ। इस बार भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वार्षिक योजना के परिव्यय में 7300 करोड़ रुपये है। उसमें 1788 करोड़ रुपये इन्होंने दलित वर्ग के लिए रखे हैं। वह 24.72 प्रतिशत से बढ़ करके 25.1 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और बजट का भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

13-02-2019/1510/SS-YK/1

श्री पवन काजलः माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया है, मैं उसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने थोड़ा-सा समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यह बजट बहुत लुभावना है परन्तु वास्तविकता से कोसों दूर है। मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूंगाः-

"सिर्फ एक पन्ना पलट कर उसने,
बीती बातों की दुहाई दी है;
फिर वहीं लौट के जाना होगा,
यार ने कैसी रिहाई दी है।"

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में कई योजनाएं हैं, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय पोषण हेतु वर्तमान निर्धारित सीमा को 90 करोड़ रुपये से 105 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा चुनाव क्षेत्र किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। परन्तु मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह 90 करोड़ रुपये से 105 करोड़ रुपये तो कर दी और 1.5 करोड़ रुपये विधायक प्राथमिकता कर दी परन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाबार्ड में आज से दो या ढाई साल पहले जो स्कीमें सैंक्शन कर रखी हैं, उनका आज तक काम शुरू नहीं हो रखा है। जितना मर्जी आप किताबों में छापते रहो, परन्तु आप धरातल पर आओ। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की आई0पी0एच0 की दो स्कीमें थीं। एक 18.90 करोड़ रुपये की और दूसरी 9 करोड़ रुपये की थी। अच्छा होता, अगर उनके लिए पिछले बजट में बजट प्रावधान कर दिया होता। माननीय अध्यक्ष जी, क्या कारण रहा होगा कि यह 2017-18 की नाबार्ड की सैंक्शन है और आज तक इसका काम शुरू न हो सका? यहां पर बजट का कोई समर्थन कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है परन्तु जो धरातल पर चीज़ है उसे देखने की ज़रूरत है। क्या नाबार्ड से दो-तीन साल पहले जो स्कीमें सैंक्शंड हुईं, उनके लिए पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है।

इसी तरह एक और बात है। हम विधायक प्राथमिकता के तहत डी0पी0आर0 बनाने के लिए एम0एल0ऐज़0 प्रायोरिटी में स्कीमें डालते हैं। स्कीम हमने विधायक प्राथमिकता में डाल दी और बजट बुक में उसके लिए 20 या 25 हजार रुपये आ गए। हम जब उसकी डी0पी0आर0 बनाने भेजते हैं, उसका फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए केस भेजते हैं तो वहां फॉरैस्ट के अधिकारी या डी0एफ0ओ0 बोलते हैं कि इसकी AA&ES चाहिए। अब मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि आपने निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपया तो कर दिया लेकिन धरातल पर काम कौन करेगा। फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए डी0एफ0ओ0 बोलता है कि इसके लिए AA&ES चाहिए। नाबार्ड में स्कीम भेजने के लिए फॉरैस्ट क्लीयरैंस चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमें ऐसी-ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने विधायक निधि बढ़ाई, आपका धन्यवाद। आपने विधायक ऐच्छिक निधि बढ़ाई, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल का जो बजट था, उसमें आपने बड़े जोर-शोर से लोक भवन बनाने की बात रखी। एक अच्छी शुरूआत थी। परन्तु उसको आप एक साल तक धरातल में नहीं ला सके। आज की डेट में प्रदेश में एक भी लोक भवन का काम शुरू नहीं हो सका। दोबारा इस बजट में भी उसका प्रावधान रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह लोक भवन अच्छी शुरूआत है। जिस भी पंचायत या गांव में बनेगा तो अच्छा रहेगा। इसमें जो 30 लाख रुपये का टैंडर है, मैं चाहता था कि इसको पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग करता। यदि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग या डी0आर0डी0ए0 करे तो जब टैंडर होगा तो एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है। यह मेरा सुझाव है। क्योंकि पंचायत में जब यह लोक भवन बनेगा, कल को वहां गरीबों की मैरिज़ होगी तो कंट्रैक्टर को बोलकर ऐसी कमेटी बनाई जाए जहां पर कोई एक्स-सर्विसमैन हो, प्रधान हो, उप-प्रधान हो, वार्ड पंच हो क्योंकि कल को जब उसका काम शुरू हो तो वे उसे चैक भी कर सकें। उसमें थोड़ा-सा डर हो कि क्या ठेकेदार प्रॉपर वाइब्रेटर लगा रहा है। क्या ठेकेदार कोई स्टील ठीक कर रहा है, क्या ठेकेदार अच्छा सीमेंट डाल रहा है? इस चीज़ को चैक करने के लिए अगर हम कमेटी बनायेंगे तो ये जो लोक भवन पांच सालों में बनकर पांच तैयार होने हैं, कम-से-कम अच्छे बनकर जनता के सुपुर्द होंगे।

इसी तरह यहां पर बात कही जा रही है।

13.2.2019/1515/केएस/वाईके/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आई.पी.एच. मंत्री जी अभी बैठे नहीं हैं, आई.पी.एच. विभाग में 3200 करोड़ रुपये की ब्रिक्स की योजना जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एन.डी.बी. लोन के तहत, जो ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम पानी की स्कीमें लाने जा रहे हैं, मैं इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि यह स्कीम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, वर्ष 2016-17 में इसकी गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से सेंक्शन मिली है और तत्कालीन सरकार ने कहा था कि जितना भी यह 3267 करोड़ रुपया है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें बराबर रूप से डिवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह ज्यादा मिलेगा और किसी जगह कम।

माननीय अध्यक्ष जी, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों को आरक्षण दिया गया, इसका हम समर्थन करते हैं। परन्तु इस बजट में ओ.बी.सी. के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बात की होती। इस बजट में आपने ओ.बी.सी. का बैकलॉग भरने की बात की होती। आपने अपनी सरकार के रहते नोटिफिकेशन भी की थी कि हम ओ.बी.सी. का बैकलॉग भर देंगे। अच्छा होता ओ.बी.सी. के आरक्षण की बात करते। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ध्वाला जी उठ कर बाहर चले गए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री पवन कुमार काजलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं कि मेरे कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच सालों में दो कॉलेज खोले गए। जिनमें एक में बच्चों की संख्या 500 और दूसरे में 700 के लगभग है। मटौर में चुनाव से 6 महीने पहले एक कॉलेज खुला था और आज वहां पर लड़कियों की संख्या 532 है। आप

कहते हैं कि "बेटी है अनमोल" इस पर हम काम करते हैं। मैं इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि मुझे बताते हुए हैरानी हो रही है कि आपने आज तक उस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं किया। अच्छा होता कि आप पिछले साल उस कॉलेज के लिए बजट रखते। इस बार तो आपने कर दिया और अब तो करना ही पड़ना था क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या 700 है जिनमें से 532 लड़कियां पढ़ रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूं किः-

बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो,
मज़बूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के समय से जो काम चले थे, गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल रानीताल, गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल राजल, गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल चलोल, गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल जमानाबाद हैं, उनमें किसी स्कूल में 80 परसेंट काम हुआ है, किसी में 90 परसेंट काम हुआ है और कहीं पर 3 लाख रु0 की तो कहीं पर 4 लाख रु0 की कमी है। कृपया पिछली कांग्रेस सरकार ने जो काम शुरू किए हैं, उनको पूरा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेल मैदान के लिए 15 लाख रु0 देने का प्रावधान किया है तो मैं इसके लिए सुझाव देना चाहूंगा कि इसको पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के माध्यम से बनाया जाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करिए।

श्री पवन कुमार काजलः माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसी तरह से आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की। स्कूलों में आपने वर्दी दी। प्रदेश में सबसे ज्यादा बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या है। जब तक इसको हम गम्भीरता से नहीं लेगें, आप जितनी मर्जी योजनाएं इस बजट बुक में छापते रहो, तब तक कुछ नहीं होने वाला।

अन्त में मैं सिंचाई योजनाओं के बारे में कहना चाहूंगा। सिंचाई योजनाओं के लिए लाखों, करोड़ों रुपये का बजट रखा गया है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि मेरे कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी सिंचाई योजनाएं हैं, वे सारी डिफंक्ट है। वहां पर करोड़ो रुपया लगा हुआ है। मेरा सजैशन है कि वहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं जाता इसलिए वहां पर जितनी पाइपें पड़ी हैं, अगर उनको हम डिसमैंटल करते हैं तब भी लाखों रुपया रिकवर हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय,ज्यादा न कहता हुआ, यह जो बजट है, मैं इसके समर्थन के चक्र में नहीं हूं। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद।

13.2.2019/1520/av/ag/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री हीरा लाल जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री हीरा लाल (करसोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी व सम्माननीय मुख्य मंत्री ठाकुर जय राम जी ने दिनांक 9 फरवरी, 2019 को इस सदन में जो बजट पेश किया है मैं भी उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में प्रदेश के सभी वर्गों का जिसमें किसान, बागवान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिला, युवा, वृद्ध यानी सबके हितों का संतुलित व विकासशील बजट पेश किया है जिसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इनके लिए यहां पर दो शब्द कहना चाहता हूं कि :-

हे महारथी-पुण्यपथी; आपको इस प्रदेश का चिन्तन करते देखा है।
चिन्ता है प्रदेश के उत्थान की, बजट में प्रावधान करके हमने देखा है।।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर लोगों का मुख्य पेशा खेती, बागवानी और पशुपालन है तथा इनका हमारी देश की आर्थिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं अपने

यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने किसानों के सम्मान के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की है जिसके तहत दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि मिलेगी। किसानों की आत्म रक्षा व इस सम्मान के लिए मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है जिसमें पी0टी0ए0, पैरा टीचर्स को नियमित अध्यापक के समान वित्तीय लाभ प्रदान किए जायेंगे। एस0एम0सी0 टीचर्स का मानदेय 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2018 से सभी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डी0ए0 दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी और दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपये तक बढ़ाई गई है। आंगनवाड़ी से लेकर के पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं से लेकर नगर परिषद के प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। इस साल विभिन्न विभागों में 20 हजार पद भरे जायेंगे। गम्भीर बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को 1500 रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। देसी गायों की खरीद पर 25000 रुपये की उपदान राशि दी जायेगी। दूध खरीद पर सभी परिवारों के लिए 2 रुपये की वृद्धि की गई है। बी0पी0एल0 परिवारों के लिए भेड़-बकरियों हेतु 85 प्रतिशत की अनुदान राशि प्रस्तावित है। किसानों को बिजली 50 पैसे प्रति युनिट कर दी है। कांटेदार बाड़ के लिए 50 फिसदी अनुदान तथा प्रमुख शहरों के लिए हैलीटैक्सी शुरू की जायेगी। पंजीकृत युवक मण्डलों व महिला मण्डलों के लिए भी 25000 रुपये की राशि देने की बात की गई है। महिलाओं को 50 दिन तक मनरेगा में लगातार काम करने पर हिम केयर सुविधा प्राप्त होगी। पांच सौ बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त उज्जवला व गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत एक बार गैस सीलैंडर फ्री दिया जायेगा। इस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। अब मैं करसोग की बात करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर पोलीटैक्निकल कॉलेज, बस अड्डा और

तत्तापानी में जल क्रीड़ा शुरू करने बारे वर्षों से मांगे चली आ रही हैं। आपने सदन में जो यह बजट पेश किया है मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने करसोग में इसी एक साल के अंदर कोटलू में आई0पी0एच0 का सब-डिविजन दिया। हमारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तत्तापानी में सतलुज के घाटों के तटीयकरण के लिए 2.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त आपने सीनियर सैकेंडरी स्कूल लालग और हाई स्कूल तलहेन, हाई स्कूल गुजरोधर और डिग्री कॉलेज करसोग के ऐडिशनल भवन के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। आपने सीनियर सैकेंडरी स्कूल माहूनाग में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करवाई है जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी अग्निशमन के लिए बहुत सालों से मांग थी। आपने अपने करसोग प्रवास के दौरान अग्निशमन की दो गाड़ियां साथ लाकर वहां पर अग्निशमन का उद्घाटन किया। पी0एच0सी0 काओ व तत्तापानी और हैल्थ सब सैंटर भनेरा तथा करसोग सिविल होस्पिटल को सौ बैड से बढ़ाकर डेढ़ सौ बेडिड किया। आपने पांगणा में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करवाई। इसी तरह काहणु से दुरकणु जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 3.31 करोड़ रुपये की एक स्कीम स्वीकृत की गई जिसका दो महीने पहले भूमि पूजन किया गया और अब यह सड़क भी चालू हो गई है। लोअर करसोग से टकरोल और खडार गली से देलगी; दो सड़कों की टारिंग व मैटलिंग के लिए 12.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।

13/02/2019/1525 /टी0सी0वी0/ए0जी0/1

इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं हिमाचल प्रदेश के उत्थान, चहुंमुखी विकास, गतिशील एंव कुशल नेतृत्व के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि

"सौम्य स्वभाव, मृदुल भाषा है आपकी पहचान,
मछली की आंख है, अर्जुन का तीर कमान,

धरती -तो- धरती, आपने जीत लिया आसमान।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। आप भी पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2019-20 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि डॉयरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। मेरे ख्याल से डॉयरेक्टर इस बार बदला है। लेकिन प्रोड्यूसर एक साल पुराने हैं और फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश हुई है। परन्तु फिल्म में कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें लटको-झटको पर ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। इसमें कहानी की कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। पिछले साल के बजट में कोई नए रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए गए और इस साल के बजट में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और हवाई सेवाओं का विस्तार वर्ष 1980 के दशक में हुआ। उस समय कुल्लू के लिए 8-10 हवाई जहाज चलते थे और 8-8 पॉयलट होते थे। उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे। इन्होंने बहुत अच्छी नींव रखी हैं। आपने कोशिश अच्छी की है, विधायकों के इंस्टिट्यूशन की जो नींव इन्होंने प्रदान की, आप उस पर अच्छी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी गति बहुत धीमी है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपको युवक मण्डल जोड़ने में एक साल लग गया, जबकि वह एग्जैक्टिव ऑर्डर होने थे। आपकी कोशिश अच्छी है। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय विधायक ठाकुर जी आप इनकी बातें न सुने और अपनी बात कहें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं लेकिन जिस प्रकार से पंचायतीराज प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं में अंदर घुसकर राजनीति की जा रही है, वह बहुत गलत बात है।

नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत में कई जगह अविश्वास प्रस्ताव लाए गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कुल्लू, बी0डी0ओ0 के खिलाफ़ मैंने अवमानना का नोटिस दिया था, उस नोटिस का क्या हुआ? अब तो काफी दिन हो गए हैं। आप उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि आज भी वहां पर एक पंचायत का पूरा रिकॉर्ड जला है। उस ब्लॉक के अंदर खोखण पंचायत का रिकॉर्ड जलाया गया है। अभी तक हमारी पिछले साल की डी0पी0आर्ज0 तैयार नहीं हो रही है। आप इस दिशा में अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें। आपने दूध के मूल्य में 2 रुपये की बढ़ौतरी की, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे बेटे ने भी एक दूध का सयंत्र लगाया है। हम 24-25 रुपये प्रति लीटर दूध पहले ही खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों है कि आपका मिल्कफैड ग्रांट पर चल रहा है। आज मिल्कफैड को वेरका और वीटा के साथ कंपीटीशन करना चाहिए था। आज वीटा और वेरका दुग्ध कंपनी हिमाचल प्रदेश में घुस रही है। आप मिल्कफैड को हिमाचल में बैसाखियों के सहारे चला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कृपया इन बातों पर गौर करें। खासकर जो वीटा, वेरका, सुपर, मदर डेरी का दूध हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

13-02-2019/1530/NS/DC/1

आज पनीर बाहर से आ रहा है, आज दूध बाहर से आ रहा है। आज प्रदेश में दूध उत्पादन घट रहा है और लोग दूध उत्पादन छोड़ने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें। इसके बारे में, मैं आपको विस्तार से किसी और दिन बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर टूरिज्म की बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यह बहुत चिंता का विषय है। मैं इस सदन में फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि पर्यटन नीति, 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटन से तरक्की कब आएगी? आप राहें ठीक करो, मंजिल खुद मिल जाएगी। आप यहां पर "नई मंजिल, नई राहों" की बात कर रहे हैं। आप इन राहों की कनैक्टिविटी को ठीक कीजिए, पर्यटक अपने

आप डेस्टिनेशन ढूंढ लेता है। हमारी सड़कें ठीक नहीं है इसलिए हम पर्यटन में बीसवें पायदान पर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नेशनल हाईवे की बात करना चाहूंगा। आज मैंने देखा कि आई0एल0एफ0एस0 कंपनी से जोजिला सुरंग का काम आठ महीने के अंदर वापिस ले लिया गया। क्योंकि जोजिला जम्मू-कश्मीर में है और वहां की सरकार ने इसके लिए प्रैशर डाला होगा। आज हमारे यहां पर आई0एल0एफ0एस0 कंपनी अढ़ाई सालों से काम नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसमें कृपा करके कुछ कीजिए और तुरंत इसका फॉलोअप कीजिए। हमारे कुल्लू-मनाली, मण्डी और बिलासपुर की कनैक्टिविटी के बुरे हाल हैं। यही वज़ह है कि पर्यटन पीछे चल रहा है।

इसके अतिरिक्त हमारा ऊर्जा राज्य का सपना नकारात्मकता का मायाजाल है। यह किताब राजकुमार वर्मा ने लिखी है और आप इसे जरूर पढ़िए। ये साईं फाउंडेशन के संस्थापक हैं। माननीय मंत्री जी, कृप्या इन बातों पर ध्यान दीजिए। अभी धरातल पर नीति कुछ नहीं है और अभी जो है पहाड़, नदियां कल-कल बहता पानी, पानी से समृद्धि व सम्पन्नता व सपना, अधिकांश पहाड़ी राज्यों ने कई दशक से देखा है। आज हमारे से उत्तराखंड आगे निकल गया है। आप उन्हें फोलो कीजिए। उन्होंने रेग्यूलेटर ऑथोरिटी को कंट्रोल में रखा है। रेग्यूलेटर ऑथोरिटी उनकी बात मानती है। तभी वहां पर निवेश आ रहा है। लेकिन यहां पर रेग्यूलेटर ऑथोरिटी आपकी बात नहीं सुन रही है और आप कृपा करके इस तरफ कुछ ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस माननीय सदन में रखने जा रहा हूं। आप पंचायतों और ट्रेड यूनियनों की ब्लैकमेलिंग से विद्युत योजना को बचाईए। इसके लिए मैं, माननीय सिंघा जी से अनुरोध करता हूं, अपने बाकी मजदूर संघ और अपने पार्टी के लोगों इंटक से भी अनुरोध करता हूं। इन परियोजनाओं को बचाईए और डी0सी0 व एस0पी0 को स्टैंडिंग ऑर्डर्ज़ दीजिए कि इन परियोजनाओं को लगाने के लिए और ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। आप कृपा करके इस पर काम कीजिए। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने स्टैंडिंग ऑर्डर्ज़ दे रखे हैं और आप इनको दृढ़ता से लागू कीजिए। तभी विद्युत सैक्टर जिंदा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जंगल हमारे और इंडस्ट्रीज पठानकोट और यमुना नगर में। जंगल हमारे पास हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हिमाचल में एक भी वुड वेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं है? मैंने वर्ष 1996 में वहां पर जा करके प्लाई बोर्ड की इंडस्ट्री खुद लगाई थी। आज अगर हिमाचल प्रदेश में कोई प्लाई बोर्ड की इंडस्ट्री लग जाए तो हमारे प्रोड्यूस के आगे चीन क्या है? चीन में टुकड़ों को जोड़ करके फट्टे बनाए जा रहे हैं। आप बोर्डर एरिया से अंदर आईए। बोर्डर एरिया वाले तो पंजाब में भी जा सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए। नूरपुर वाला तो पंजाब में भी जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मंडी में प्लाई बोर्ड का एक युनिट लगाएं। फिर आप देखिए वहां पर कितनी समृद्धि आती है और कितना रोज़गार मिलता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वैस्टर्ज़ को रिझाने के लिए गए थे। मैं पिछले दिनों बद्दी में गया और वहां पर सिंगल विंडो सिस्टम का यह हाल है कि वहां पर अधिकारी इतने बद्तमीज़ है और जिस प्रकार से वे इन्वैस्टर्ज़ को डील करते हैं, आप वहां जा करके उनके हाल देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुल्लू के बारे में कहना चाहता हूं। इस बजट में बूभू जोत (सुरंग) और जलोड़ी जोत (सुरंग) का कोई ज़िक्र नहीं है। मैंने नेशनल हाईवे के बारे में पहले ही बता चुका हूं। भुंतर पुल के काम के लिए पिछली बार मुझे कोई और जवाब आया और इस बार कोई और जवाब आया है। पिछली बार बोला गया कि हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं और इस बार बोला गया कि हम नवम्बर में शुरू करेंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या वाईंडअप करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने विजन डाक्यूमैंट में कहा था कि हम वहां पर फैक्टर-II लागू करेंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे, शहर की दूरी के हिसाब से 10 प्रतिशत बढ़ाएंगे। यह ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बेसहारा पशुओं के मालिक का पता करेंगे।

13.02.2019/1535/RKS/DC-1

लेकिन कुल्लू में पशुओं के हथियारे का क्या होगा? बजौरा में खड्ड के बीच वह गौशाला किसने बनाई थी? सैंकड़ों पशु क्यों बह गए? यदि आप सच में अपने आप को गौ रक्षक मानते हैं तो कृपया इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज से करवाइए। अभी आप हरियाणवी में एक बात कह रहे थे। हरियाणा में कहते हैंः-

भाई मनसा राम मन की मन में जाण।
कम्बल ओढ़ के घी पी ले मुछा में ताव न दियो॥

हिमाचल के संदर्भ में मेरा कहने का यह मतलब है कि भाई जय राम जी जो उधार का घी है उसे कम्बल ओढ़ के पी ले। अगर आप मुछों को ताव देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने घी पिया है और कर्जा बहुत सारा है। कृपया करके आप इस कर्जे के बारे में भी सोचें। प्रदेश किस तरफ बढ़ रहा है। आपको रोजगार के बारे में भी सोचना होगा। इस बजट में आय के साधन, निवेश, रोजगार, पर्यटन नीति और ऊर्जा नीति का कोई जिक्र नहीं है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करने के लिए विवश हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री मुलख राज जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मुलख राजः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र को अपनाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने यह दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में जहां नई सोच व नई प्रहर के आधार पर हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर ले जाने की बात की गई है वहीं पहले बजट में शुरू की गई 30 महत्वकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान कर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी दर्शाया गया है। इस बजट में जहां कृषि-बागवानी व ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है वहीं निवेश, ढांचागत विकास, पर्यटन, ऊर्जा व आद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया है।

कौशल विकास के द्वारा रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में गरीब, शोषित वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलने वाली पैंशन को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह किया है जिससे 5 लाख से अधिक परिवारों लाभान्वित होंगे। 'हिमाचल गृहणी सुविधा योजना' व केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त गैस सिलैंडर मुफ्त में देने से दो लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया गया है। इन विधवाओं को आई.टी.आई. एवं नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आरक्षण भी दिया गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निरंतर देखभाल की आवश्यकता भी रहती है। इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई सहारा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को वित्तीय सहायता के रूप में दो हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

13.02.2019/1540/बी0एस0/एच0के0-1

"हिमकेयर" योजना के अंतर्गत ऐसे मनरेगा मजदूरों की जिन्होंने कम से कम 50 दिन का रोजगार प्राप्त किया है तथा सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। "आयुष्मान" योजना का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार सदन की चर्चा की गई कि यहां कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं । पिछले 20 वर्षों से जहां मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत खराब थी, पेयजल की समस्या गंभीर थी, सिंचाई के लिए कूहलें चलती नहीं थी जिसके उपयोग से लगभग 80 प्रतिशत वहां पर किसान खेती करते हैं। मगर मैं आज दावे केसाथ कह रहा हूं और आज करोड़ रुपये की राशि आज मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पहुंची है जिससे आज मेरे कूहलों के काम भी चले हैं और

पेयजल की समस्या भी दूर हुई है। जहां तक मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं हमारी सरकार ने स्वस्थ्य की गाड़ी को पटरी में लाया है। मेरा जो चढियार क्षेत्र था वहां पर पिछले 5 वर्षों में सिर्फ एक डाक्टर ही था। मगर आज (घंटी) वहां पर 4 डाक्टर हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वस्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं । अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने सिविल अस्पताल की भी घोषणा की है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का तहे-दिल से धन्यवाद करता हूं।

पर्यटन पर थी मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। पर्यटन की दृष्टि से जहां पर वर्ष 1929 से एक ट्रेन चली थी उसके बाद रेलवे का कोई भी कार्य नहीं हुआ परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी एवं केन्द्रीय रेल मंत्री धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सांसद शांता जी का भी इस कार्य के लिए धन्यवाद करता हूं। पर्यटन की दृष्टि से बीड़-बिलिंग में करोड़ों की सौगात दी है, जिससे मेरा विधान सभा पर्यट की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और आज बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षैत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का एक और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पीछे बड़ा-भंगाल में घटना हुई रास्ते बंद पड़ गए लोगों के जीवन में पूरी तरह से संकट आ गया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का तहे-दिल से धन्यवाद करता हूं जब मैंने इस बारे में इनसे बात की तो तुरंत वहां लोगों के लिए राहत प्रदान की गई और राशन पहुंचाया गया। इन्होंने एक ही बात कही कि वहां पर किसी भी प्रकार से राशन की कमी नही आनी चाहिए । यह बहुत बड़ी बात है जो रास्ता कटा उस रास्ते के निर्माण के लिए मापलाचे के स्थान पर पैसे का प्रबंध भी किया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें।

श्री मुलख राज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2019-20 का यहां पर बजट पेश किया है मैं उसका तहे-दिल से सर्मथन करता हूं। जय हिन्द-जय भारत ॥

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिक्रमादित्य सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रमादित्य सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हमेशा छोटा विधायक और कम उम्र का विधायक होने के नाते आखिर में बोलने का भुगतान करना पड़ता है और कम समय मिलता है । इसलिए मेरा आज निवेदन है कि मुझे कम से कम 10 मिनट बोलने के लिए समय देने की कृपा करें।

अध्यक्ष : आप अपने संसदीय दल से कहें कि आपका नाम पहले भेजा करें।

श्री बिक्रमादित्य सिंह : यह वरिष्ठता के आधार पर पीछे चला जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2019-20 का विधान सभा बजट पेश किया है उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आज मुझे यहां पर मौका मिला है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने टैक्स फ्री बजट 44387 करोड़ रुपये का दिया है, यह निश्चित तौर से इसमें कहा गया है कि यह टैक्स फ्री है और यह हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

13.02.2019/1545/डी०टी/एच0के0-1
मगर मैं समझता हूं कि यह एक बहुत पुरानी कहावत है कि 'इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो' और जिस तरह से यहां पर financial constraints की बात की गई है। प्रदेश का रेवेन्यू डेफिसिट 2392 करोड़ रूपये को है। बोरोइंग हमारी तकरीबन 7500 करोड़ की है, फिसकल डेफिसिट हमारा जो है वह है 7350 करोड़ का है तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फिसकल प्रूडेंटस और फिसकल मेनेजमैंट की बात करनी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं सरकार की ओर से हमें कमी देखने को मिली है।

आज जो ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश की है वह 2015-2016 में 10.1 प्रतिशत हुआ करती थी Since last financial year it has come down to 8.1 percent which is a matter of growing concern for the State. हम अनऐम्पलोयमेंट की बात करते हैं। रोज़गार को और स्वरोज़गार को प्रदेश में बढ़ाने की बात की गई है। मगर अभी जो annual employment/unemployment survey हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश 6th highest unemployment rate में 10.6 प्रतिशत बढ़ रहा है। जबकि भारत की जो अनऐम्पलोयमेंट की रेट जिसके बारे में मैंने गवर्नर अड्रैस पर भी जिक्र किया था that was around 6 percent तो इस चीज़ को भी हमें देखने की आवश्यकता है। अभी हम फिसकल प्रूडैंटस् की बात कर रहे हैं। own revenue में हम अगर अपनी तुलना हमारे साथ लगता जो राज्य उत्तराखण्ड से करें तो our generation of revenue is 38 percent in comparison of Uttrakhand State which has 51 percent. जो सैंटर से मिल रहा है that is around 63 percent to Himachal Pradesh and 50 percent to Uttrakhand. यह जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है Himachal Pradesh became State much earlier than that Uttrakhand उसके बावजूद इन आंकड़ों पर उत्तराखण्ड हमसे आगे निकला है so, this is a matter of great concern for us and the Hon'ble Chief Minister should look into these matters. जहां तक 15 नई स्कीमें घोषित करने की बात कही गई है उस पर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पिछली 30 स्कीमें, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने भी बड़े आक्रमात्क तौर से यहां पर अपनी बात रखी है उस पर हमने भी जब सरकार का तकरीबन एक साल पूरा हुआ हमनें एक प्रैस कानफ्रैंस के माध्यम से पूछना चाहा कि हम भी आपकी सरकार की उपलब्धियों को मनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप हमें बतायें कि एक साल की उपलब्धियां क्या है? उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक ब्यान किया कि he is a junior most MLA और इस तरह की ब्यान बाज़ी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, आपने सोलन में यह ब्यान दिया था। But whatever we say it should not be seen only in the way of criticism. मैं यह बात कहना चाहता हूं कि 30 नई स्कीमें इस बारी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट में लाई है। जिसमें 50 प्रतिशत सबसीडी

Barbed Wire को दी गई है, 50 प्रतिशत सबसीडी purchase of indigenous Cows को दी गई है, 150 करोड़ रूपया Nutan Poly House को दिया गया है, 100 Trout Units and Carp Fish Ponds लगाने की बात की गई है। मगर हम को नई स्कीमों को लाने से पहले we have to have a comprehensive plan of what we have done in the last one year and whether the 30 schemes that were announced in the last and previous Budget, क्या वह स्कीमें धरातल पर उतरी हैं, क्या उसका फायदा क्षेत्र के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और जिनको पैंशन मिली है उनको उन स्कीमों का फायदा मिला है । इस पर एक व्हाइट पेपर सरकार को लाना चाहिए जिस पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, जब हमने बजट पढ़ने की कोशिक की इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिली । हांलाकिं हम कोई फाइनेशिंयल एक्सपर्ट या इकोनोमिस्ट नहीं हैं। मगर हर पैराग्राफ में जो नई स्कीमें लाई गई उसमें एक चीज़ लिखी गई कि हम इसको ऐक्सटर्नल फंडिंग के लिए भेज रहे हैं या हम इसको केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और इसके बाद अलग-अलग ऐक्सटर्नल फंडिंग के माध्यम से इसको लाया जायेगा। जैसे कि Integrated Mashroom Development Project, Himachal Pradesh Sub-tropical Horticulture Development Project, Irrigation and Value Addition, Securing Rural Livelihoods through Biodiversity Conservation, Landscape Management and Skill Development, Disaster Risk Reduction and Preparedness Project जो 2240 करोड़ का है।

13-02-2019/1550/वाई.के./एन.जी./1

हालांकि इसका मैंशन बजट में किया गया है । लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हम इसको एक्सटर्नल फन्डिग से करवाऐंगे । मैं कहना चाहूंगा की आज कल हम सरकार के हितैषी हैं । आज वैसे भी देश में फोरेन फन्डिंग से, बहार के लोगों के साथ एमओयू करने पर बहुत बडा माहौल बना हुआ है । उसमें जिस तरह की बातें देश के माननीय प्रधानमन्त्री पर हो रही हैं हम नहीं चाहते की वैसी ही बातें प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री जी के बारे में भी हों । इसलिए आप सोच समझ कर इसके लिए फन्डिंग करवाऐं ताकि सोच समझ कर

इसका कार्य आने वाले समय में हो सके । जहां तक प्रदेश में फिशरीज की बात है इसमें कहा गया कि जो हमारा कोल डैम है which falls in my Constituency इसमें महासीर और सिलवर क्रैप लगाया जा सकता है । इसका पैदावार वहां पर किया जा सकता था जिस पर कुछ भी नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा की इस पर माननीय मुख्यमन्त्री और सम्बन्धित विभाग अपनी दया दृष्टी डालें । उस ऐरिया को एम्पलोयमैंट और सैल्फ एम्पलोयमैंट के माध्यम से अपना हस्तक्षेप करें और मैं कई बार इस मुद्दे को यहां पर उठा चुका हूं । फोरेस्ट फायर जोकि बहुत बडी समस्या हमारे प्रदेश के अन्दर है । पिछले गर्मी के सीजन में भी बहुत सी समस्याऐं निकली, प्रदेश की बहुत सी वन सम्पदा इसमें जल कर राख हो गई । इसमें केवल 50 प्रतिशत सबसिडी पाईन निडल को दी गई है । Which । think is only a lip service to the industry इसमें और भी स्टैपस लेने चाहिए थे और इसमें सरकार पूरी तरह से कार्य करने में सफल नहीं हो पाई है । अर्बन डैवलपमैंट की बात न ही करें तो अच्छा रहेगा । समार्ट सिटी बनाने की बात कही गई, शिमला में और धर्मशाला में । मैं शिमला की बात कहूंगा because some area of Shimla falls under my Constituency also. इसमें 1500 करोड रूपये के प्रोजैक्ट आज अटके हुए हैं और 2906 करोड के पैन्डिग प्रोजैक्टस हैं । जिसमें एनजीटी के बैन की वजह से the Government has not been able to move even an inch एक स्नेल की पेस पर सरकार चली हुई है । जो टीसीपी की मन्त्री महोदय है वह कहतीं हैं कि हम सूर्पीम कोर्ट में जा रहे हैं कभी कहते हैं हाई कोर्ट में कर रहे हैं, but there has been no conclusive steps taken by the Government as far as the NGT ban is concerned. Because of this the developmental projects of thousands of crore is stuck. एक इन्डस्ट्री के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा की माननीय मुख्यमन्त्री स्वांलम्बन योजना के अन्तर्गत आपने हर इलाके के बारे में कहा ।लेकिन हमारा भी एक इलाका है शोघी जोकि बिलकुल आपकी नाक के नीचे है । Which is just outside the town वहां पर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया डैवलप किया जा सकता है । आज भी वहां पर हुन्दाई के और अलग-अलग छोटे उद्योगपति और एमएसएमई के उद्योग वहां पर है । उसको किसी तरीके से कोम्प्रीहैन्सिव प्लैन के अन्दर

लाने का सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया गया है । Soghi is an area which is just outside the Shimla . जिससे हमारे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज जल्दी किजीए ।

श्री विक्रमादित्य सिंह : 5 मिनट ओर दे दीजिए माननीय अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष : पांच मिनट नहीं आपको 10 मिनट हो गए है ।

श्री विक्रमादित्य सिंह : केवल 2 मिनट अध्यक्ष जी, टूरिजम के बारे में कहना चाहूंगा कि केवल लिप्स सर्विस बजट में की गई है । यह कहा गया है कि इको टूरिजम के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा । पोंग डैम डैवलपमैंट बोर्ड के बारे में भी बात की गई है । होम स्टेज, जिसे बढाया गया है, 3 से 4 किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं । But there is a grave problem with the hoteliers in Shimla today. I have been able to interact with them and they tell me and जहां तक होटलियर्स की बात है उनको इतनी समस्या है कि आज होम स्टेज के अन्तर्गत एक पूरी बिल्डिंग में परिवार के अलग-अलग लोग उस पर रिजिस्ट्री करवाते हैं उनको कोई भी टैक्सेशन चाहे वो कैपिटल सबसिडी होटलियर्स को नहीं मिलती है, सैस उनको देना पडता है, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से उनको एनओसी लेनी पडती है । टीसीपी से उनको एनओसी लेनी पडती है । मगर आज कोई भी फायदा उन होटलियर्स को नहीं दिया जा रहा है । साथ ही साथ एक advisory to top it all as icing on the cake advisory by the Deputy Commissioner दी जाती है कि the tourists in Shimla are not invited. In a state where the livelihood of the people depends on Tourism, this is a mockery of the democratic set-up of the State.

13/02/2019/1555/RG/YK/1

अगर इस तरह की धज्जियां पर्यटन की उड़ाई जाएंगी तो इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां एक Light and Sound Show की बात कही गई। अब अगर सरकार लाईट एण्ड सॉउन्ड शो चलाने लग जाएगी तो नगर निगम क्या कार्य करेगी? इतने छोटे-छोटे कार्य जो पंचायत स्तर के हैं, वे बजट बुक में लिखे जा रहे हैं। जो विज़न एक सरकार का होना चाहिए, who is stopping the State Government from signing MoUs like the Congress Government did with ski resorts. Who was stopping the Congress Government for signing MoUs with Walt Disney? We can get straight of the art projects from multinational companies. मगर यहां लाईट एण्ड सॉउन्ड शो की बात की जा रही है, शिव धाम इत्यादि की बात की जा रही है। ये छोटे-छोटे प्रोजैक्ट्स जो राज्य स्तर के नहीं बल्कि उपायुक्त स्तर के, पंचायत स्तर या म्यूनिसपल कमेटी स्तर के प्रोग्राम्ज हैं। They have been included in the Budget, which is a shame on the State Government. माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई, यहां शिमला एयरपोर्ट की बात की गई कि यहां इसको हैली टैक्सी बनाना है। यदि आप कभी यहां से जुब्बलहट्टी जाएंगे तो 2,500/-रुपये का किराया लगता है। इतने में यहां से आदमी टैक्सी में चण्डीगढ़ पहुंच जाता है। यहां उड़ान-1 एवं उड़ान-2 की बात की जा रही है, तकरीबन 20,000/-रुपये का टिकट शिमला से वन वे दिल्ली के लिए लगता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए।

श्री विक्रमादित्य सिंह : तो इन चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है और सही बात करने की आवश्यकता है। यहां बैंटनी कैसल की बात की गई। When the BJP was in Opposition, they oppose the acquisition of Bantony Castle and fight tooth and nail for opposing it, when Sh. Virbhadra Singh Ji was the Chief Minister, उस समय जब बैंटनी कैसल को ऐक्वायर करने की बात की जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। उस समय की सरकार पूर्व भाजपा की सरकार ने यहां का जो कोर एरिया या फौरेस्ट एरिया है, उसको भी बदलने की कोशिश की ताकि यहां बैंटनी कैसल में प्राइवेट इनवेस्टमेंट की जाए। आज जब यह एक स्टेट असेट्स बना है और आज इसको इस बजट में लाया गया है। इस पर पूरा बजटरी प्रोविजन श्री वीरभद्र सिंह जी की पूर्व सरकार द्वारा करवाया गया था। मैं इसमें ज्यादा न कहता हुआ केवल इतना कहना

चाहूंगा कि बजट के बारे में तो हमने बात की। लेकिन जो कट्स वर्तमान सरकार ने इस बजट में लगाए हैं, उनके बारे में कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 'दीन दयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना', इसमें 51 करोड़ रुपये थे, रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में वर्ष 2018-19 में इसको कम करके 32 करोड़ रुपये किया गया है, under the National Rural Livelihood Mission, the allocation has been reduced in the revised estimate of financial year 2018-19 from 25.00 crore to 20.00 in its Budget estimate of 2019-20. जो पांच करोड़ रुपये कम किया गया है। Under the Rashtriya Swasthya Bima Yojna, there is hardly any allocation in the Budget. केवल मात्र दो लाख रुपये का इसमें लिप सर्विस किया गया है और under the Pradhan Mantri Sadak Yojna Scheme for developing rural roads, the State Government has cut short its allocation by Rs. 10.00 crore between the revised estimate of last year and Budget estimate of this year. इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की वर्ष 2019-20 की कमिटिड लायबिलिटी है, वह तकरीबन 23,596 करोड़ रुपये है और अगर इसी हाल से हम चलते रहे तो वर्ष 2022-23 तक जो सरकार का आखिरी साल होगा, उसमें सरकार की committed liabilities will be around hoping Rs. 30260 crores. With this kind of financial backlog and with this kind of financial accumulation on the State, I don't understand that without financial prudence and without resource mobilization, how the State will go ahead. This is a matter of grave concerned, for which I request the Hon'ble Chief Minister to think over all these matter.

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं मीसा अरेस्ट के बारे में कहना चाहूंगा। इसके लिए सरकार ने 11,000/-रुपये दिए हैं। यह एक कोशिश की जा रही है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों के साथ उनकी तुलना करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहां सदन में याद दिलाना चाहूंगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर कई साल जेल में रहकर देश को आजादी दिलवाई है और उन लोगों की तुलना ऐसे लोगों के

साथ की जा रही है जिन्होंने जब वर्ष 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय कानून तोड़कर उसका उल्लंघन किया था, उनको यह दिया जा रहा है

13/02/2019/1600/MS/एजी/1

which is totally uncalled for. I welcome the steps taken by the Madhya Pradesh Government जिसमें कमलनाथ जी ने इसको विद्ड्रो किया है और आज यहां पर भी इसका बहिष्कार करने की हमें आवश्यकता है। इस पूरे मुद्दे को मध्यनज़र रखते हुए हम इस बजट का सहयोग करना चाहते थे but we don't believe in criticism for the sake of criticism. There is nothing in this budget that can be appreciated. जो पी0टी0ए0, पैरा टीचर्ज और आउट-सोर्स कर्मचारी थे बल्कि आउट-सोर्स कर्मियों का आज यहां विधान सभा के बाहर जमावड़ा इकट्ठा हुआ है क्योंकि उनको भी झुनझुना दिया गया। जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, जो उस समय मुख्य मंत्री फेस थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और हम आउट-सोर्स कर्मियों को पक्का करेंगे। आज उनको भी झुनझुना पकड़ा दिया गया है। न पी0टी0ए0 के लिए कुछ किया गया और न ही पैरा टीचर्ज के लिए कुछ किया गया है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। यह बजट केवल मुख्य मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल।

अध्यक्षः अभी दो माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास चर्चा के लिए हैं। अब 4.00 बजे का समय हो गया है। अगर दोनों माननीय सदस्य अपना नाम सरेण्डर करते हैं तो मुख्य मंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे। इसमें श्री राजिन्द्र गर्ग जी और एक माननीय महिला सदस्य है।

श्री अरूण कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, तीन दिन पहले चर्चा के लिए नाम दे दिए थे।

अध्यक्षः मेरे पास यह सूची है। आप अपने नेता से पूछिए। सारी सूचियां मेरे पास हैं।

दोनों सदस्यगणः जी, हम नाम सरेण्डर करते हैं।

अध्यक्षः अभी दो माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास बजट पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए थे। अब दोनों नाम वापिस हो गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बजट की चर्चा का उत्तर देने हेतु आमंत्रित करता हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 के लिए जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस बजट पर मैं बहुत ही सार्थक चर्चा अपने समक्ष होता देख रहा था।

सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। सबने बहुत ही अच्छी और सार्थक चर्चा की तथा कई अच्छे सुझाव भी दिए। उसके साथ-साथ, हमारे विपक्ष के मित्रों ने एक मजबूरी-वश विवशता के साथ अपनी बातें कही हैं और बात कहने के साथ-साथ बजट का समर्थन करने में असमर्थता जाहिर की है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी खासियत यही है कि अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। यदि अच्छा लगे तो अच्छा कहो, अगर बुरा लगे तो बुरा कहो। हमने उन सारी बातों को सुना भी है और सुनने के बाद हमने सभी बातों को सहजता से लिया भी है।

बजट की चर्चा में इस माननीय सदन के 37 सदस्यों ने भाग लिया है। जिसमें पक्ष के 18 और प्रतिपक्ष के 16 माननीय सदस्य शामिल हुए हैं। इसके अलावा दो हमारे आजाद साथी जो हमें सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने भी चर्चा में भाग लिया। इसके अलावा

सी0पी0आई0(एम) की तरफ से श्री राकेश सिंघा जी ने भी चर्चा में भाग लिया। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद और अभिनन्दन करता हूं। मैं क्षमा भी चाहूंगा कि कुछ साथी हमारे चर्चा में भाग नहीं ले सके हैं। जब बजट सत्र होता है, बजट पर चर्चा होती है तो सभी माननीय सदस्यों को इसमें अपने विचार रखने का एक अवसर होता है और उस अवसर का वे लाभ उठाते भी हैं।

13.2.2019/1605/जेके/एजी/1

उसके साथ-साथ प्रदेश में, अपने क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित अगर कुछ बात कहनी है, उसके सन्दर्भ में भी बात कह सकते हैं। समय की कमी के कारण हमारे तीन माननीय सदस्य शायद बोल नहीं पाए। आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे कि जब अवसर मिले तो आप प्राथमिकता में पहले बोलें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा है, हमारी सरकार के कार्यकाल का एक साल बीता और अब 13 महीने हो गए। "ईमानदार प्रयास का, एक साल विकास का", हम इस नारे के साथ आगे बढ़े हैं। इस बात में, इस नारे में कहीं पर भी अहंकार नहीं है। आप सफलता में कहां पहुंचते हैं, यह अलग विषय है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए क्या आपने ईमानदार प्रयास किए? माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही मंजिल तक पहुंचना हमारे लक्ष्य का हिस्सा है लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साल के कार्यकाल में जो ईमानदार प्रयास होने चाहिए थे, वे हमारी सरकार ने किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हमने बजट प्रस्तुत किया, उसके बाद दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों में उसके बारे में आया। हमारे लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारा मीडिया है, वह स्वतंत्र है। वह न यहां का है, न वहां का है। उन्होंने बेबाकी से सारी बातों का जिक्र किया। मैं लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ का भी सम्मान करते हुए, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत ही प्राथमिकता के साथ बजट पर स्टीक टिप्पणियां की हैं। अधिकांश टिप्पणियों में, अधिकांश समाचार-पत्रों के बारे में मैं कह सकता हूं कि हमारा जितना भी मीडिया है, चाहे वह सोशल मीडिया है, चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया है और चाहे हमारा प्रिंट मीडिया है, एक भी समाचार-पत्र में उस बजट की आलोचना नहीं हुई। ...(व्यवधान)... मुकेश अग्निहोत्री जी, आप तो वहां से आए हैं। आप तो उन पर विश्वास करो। उन्होंने कम-से-कम हमारे और आपके कहने के हिसाब से नहीं लिखा है। एडिटोरियल लिखे और अधिकांश एडिटोरियल में एक ईमानदार प्रयास

की दिशा से जो किया जा सकता है, उसका भी जिक्र हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ तो आपकी मज़बूरी रही होगी, वरना आप ऐसे तो नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं किः

मशरूफ़ है यहां लोग दूसरों की कहानियां जानने में,
इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्रों ने बात कही, कभी शिमला की बात करते रहे, कभी दिल्ली की बात करते रहे। दिल्ली की बात तो करते ही रहे लेकिन अब हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि कुछ दिन रह गए हैं। ये दिन गिनने में लगे हुए हैं। सबकी उम्र लम्बी हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये केन्द्र सरकार की बात करते रहे कि इतने दिन रह गए। हर दिन जब एक दिन कम होता है तो उसको बोलते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।

13-02-2019/1610/SS-DC/1

और मैं यह भी कहना चाहता हूंः-

"मिलकर बैठ गए, महफिल में जुगनू सारे,
मिलकर बैठ गए, महफिल में जुगनू सारे;
और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जायेगा।"

सब ऐलान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह अपमान नहीं है। आपको शायरी के भाव में जाने की आवश्यकता है। ये शब्द मेरे नहीं हैं। आप दिल पर मत लीजिए। ...(व्यवधान)... हम यह बात नहीं बोल रहे हैं। हम तो वहां की बात कर रहे हैं जो आप ज़िक्र कर रहे थे। शायर की भावनाओं में जाने की कोशिश करो। यह शेरो-शायरी मेरी नहीं है, यह किसी और का शेर है। मैंने तो उसे सिर्फ पढ़ा है। आप इस बात को अपने ऊपर मत लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बजट 2019-20 का प्रस्तुत किया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलने शुरू हुए और मैं पूरे भाषण का अंत तक इंतजार करता रहा कि कहीं तो 2019-20 के बजट का भी ज़िक्र आयेगा। 2019-20 के बजट का ज़िक्र ही नहीं आया लेकिन वह बात खत्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष 2018-19 के बजट भाषण पर ही बोलते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह परिस्थिति पहली बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन में देखी है। आमतौर पर जब विपक्ष के नेता बजट पर बोलते हैं तो बजट प्रस्तुत होने के बाद उनके पास एक अवसर होता है कि विपक्ष के नेता को डिस्कशन को इनीशियेट करना होता है। जब डिस्कशन को इनीशियेट करना होता है तो बजट क्या बनाया गया है, बजट में क्या है, उन सारी बातों पर जाये बिना आपने 2018-19 का बजट भाषण पकड़ा कि आपने उस वक्त यह कहा था, आपने यह करने को बोला था लेकिन यह नहीं हुआ या वह नहीं हुआ। यह कहते-कहते आपका भाषण ही समाप्त हो गया। काश, आपने उसमें 2019-20 के बजट का भी ज़िक्र किया होता! अगर 2019-20 का बजट प्रस्तुत हुआ है तो उसका ज़िक्र किये बिना बात खत्म होना, सचमुच में हमें थोड़ा-सा अटपटा लगा। आपको कैसा लगा, अब वह आप जाने। आपकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन मैं कुछ बातों पर ज़रूर कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि इसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होते-होते, आपको सब कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया कि आप परेशान हो गए। आप अंदर बैठने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। आप सदन से बार-बार बाहर जा रहे हैं। सदन में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं हुआ। हमने एक शुरूआत की। 70 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए उनको पैंशन लगाने का एक निर्णय लिया। ...(व्यवधान)... मैं ज़िक्र कर रहा हूं। मुझे विवश होकर कुछ कहना पड़ रहा है जो आपने कहा हुआ है। राजा साहब उस वक्त यहां नहीं थे। किसने कहा, यह मुझे मालूम नहीं है। शायद आप नहीं थे। राजा साहब ने शुरूआत की थी कि 80 साल से ऊपर उम्र के लोगों को पैंशन आय सीमा के बिना लगेगी। देखिये, एक बात को मानकर चलना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र बड़े टेक्निकल आदमी हैं। घोषणा की कि 80 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पैंशन बिना आय सीमा के दी जायेगी। 80 साल एक ऐसी

उम्र होती है, जिस पर पहुंचने से पहले बहुत सारे निकल गए होते हैं और जो बाकी बचे हैं वे पैंशन मांगने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए कहने में क्या हर्ज है? अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कुछ ही लोग बचे हैं जो जमीन पर हैं। परन्तु जो ऊपर चले गए हैं उनको तो पैंशन नहीं लगेगी। आपका वश चले तो आप ऊपर वालों को भी पैंशन लगा दें। यह पैंशन का प्रावधान आपने जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं किया था, जो ऊपर चले गए उनके लिए किया हुआ था।

13.2.2019/1515/केएस/डीसी/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 2.53 लाख हो गई और इस योजना के लागू होने से 70 से 80 वर्ष की आयु के करीब 1.58 लाख बुजुर्गों को नई पैंशन लगी। हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। यहां पर मुख्य मंत्री लोक भवन का ज़िक्र आया। आपने कहा कि मुख्य मंत्री को सब जगह डाल दिया । आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुख्य मंत्री का नाम हटा दीजिए और लोक भवन बनाइए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना को हमने पिछले बजट में डाला था और 41 विधान सभा क्षेत्रों में लोक भवन की प्रथम किश्त जारी होने के बाद काम शुरू हुआ है। अब आप नहीं कर पाए होंगे तो आप अपने क्षेत्र की बात अपने तक रखिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुड़िया और होशयार हैल्प लाइन की बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन मित्रों को कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो शिकायतें आईं, उनमें से 99 प्रतिशत शिकायतों का इन हैल्प लाइन्ज़ के माध्यम से निवारण करने में मदद की है।

आपने हिम केयर का जिक्र किया, हालांकि यह योजना हमने दो योजनाओं को क्लब करके बनाई और इस योजना के अंतर्गत 12 फरवरी, 2019 तक 2.89 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ दिया गया है लेकिन हमारे मित्रों को कुछ नहीं दिखा।

...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप बोले तो हम बीच में एक बार नहीं बोले हैं। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... मैं बजट पर ही आ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः कृपया बीच में मत बोलिए।

मुख्य मंत्रीः मुकेश जी, क्या आपको बैठे-बैठे भी असुविधा हो रही है? ...(व्यवधान)... देखिए, जो इस माननीय सदन में ज्यादा उछल-कूद करते हैं, उनका अच्छा नहीं हुआ है, यह यहां का अनुभव है जिसको मैं सांझा कर रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ...(व्यवधान)... भाई, मुझे पीड़ा होती है।...(व्यवधान)... अभिमान की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या बोलना है, ये तय नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)... मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं। हम भी चुनकर ही आए हैं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुकेश जी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ज़िक्र किया कि बहुत उछल-कूद करने वाले लोग कुछ वर्षों से हमें यहां इस माननीय सदन में दोबारा दिखे नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में एक व्यवस्था रही है । आप बोल रहे थे तो इस तरफ से हमने एक भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलने दिया और न ही हमने बोला है। आप लगभग 50 मिनट बोले हैं और जब हम आपकी चर्चा का जवाब दे रहे हैं आप पांच मिनट भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ...(व्यवधान)... क्या आप तय करेंगे कि हमें क्या बोलना है?...(व्यवधान)... मैं बजट पर ही आ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः कृपया आप लोग मत बोलिए। कृपया बैठे-बैठे मत बोलें।

13.2.2019/1620/av/HK/1

मुख्य मंत्री : आगे जाकर के ...(व्यवधान)... चलिए कोई नहीं।

मैं यहां पर गृहिणी सुविधा योजना की बात कर रहा हूं। इसके अंतर्गत दिनांक 12.2.2019 तक 52104 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया मगर यह जिक्र उन्हीं बातों का हो रहा है। आपने यहां पर प्राकृतिक खेती की बात की है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके कन्सैप्ट को समझने की आवश्यकता है। यहां पर हमारे बहुत सारे मित्रों ने इस बात को लेकर अलग-अलग टिप्पणियां की हैं कि यह हो जायेगा, वह हो जायेगा। यह हमारी सरकार का उस दिशा में एक कदम है। हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, पैस्टिसाइड का इतना ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है कि हम भोजन नहीं बल्कि ज़हर खा रहे हैं। कैंसर के कितने मरीज हो गये हैं। इसके अतिरिक्त हाइपोटैंशन, डायबिटीज, शुगर इत्यादि सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये पैस्टिसाइड्ज हैं। केमिकल खाद इत्यादि यूज़ करने से हमारे भोजन से प्राकृतिक पौष्टिक तत्व खत्म हो गये हैं। ज्यादा हासिल करो और अभी हासिल करो; यह हमारा स्वभाव बन गया है। इस प्रकार की जो कम्पनियां आती हैं मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यह बात सच है कि उनका मेन मकसद प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। हम ज्यादा प्रोडक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस बढ़ रही प्रोडक्शन में जो केमिकल के नुकसानदायक तत्व आ रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य जीवन और जानवरों के जीवन पर भी सोचने की आवश्यकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि संतुलित भोजन होना चाहिए और excess of everything is bad. हमने इसी उद्देश्य से प्राकृतिक खेती की तरफ कदम उठाया है। इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम खत्म कर पाओगे। हमारी यह आदत बन गई है कि अगर सेब का बागीचा है तो उसमें इतने दिन के अंदर खाद डालनी है और इतने दिन के बाद यह स्प्रे या वह स्प्रे करना है। इसके लिए सारा शैड्यूल बना हुआ होता है। मगर हमने थोड़ा हटकर के एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है और हमें धीरे-धीरे इस ओर भी शुरुआत करनी चाहिए। इसी शुरुआत की दृष्टि से हमने 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना' शुरू की है। मुझे इस बात की भी

खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत 18000 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण लेकर उन किसानों-बागवानों ने अपने खेतों में इसकी शुरुआत करने की पहल की है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे हमने कृषि उपकरण सुविधा योजना भी शुरू की है और इसके अंतर्गत 4222 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है। सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत 408 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है मगर आप बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हमने किसानों के लिए बिजली की प्रति युनिट दर अपने पिछले बजट में एक रुपये से घटाकर 75 पैसे की थी और उसको इस बजट में 50 पैसे कर दिया है। हमने जो 1 रुपये से घटाकर 75 पैसे किया उसके अंतर्गत भी 33500 किसानों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त अगर टूरिज्म की बात कहें तो हमने 22 करोड़ रुपये की लागत से 'नई राहें, नई मंजिलें योजना' लाई है। आपने मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना का जिक्र किया। यह भी नई योजना है और हर चीज के लिए कुछ वक्त तो लगता ही है। सारी चीजें अभी हो जायेगी, ऐसे हो जायेगी; ऐसे एकदम से कुछ नहीं होता। हर योजना को सफल करने में समय लगता है। यह योजना बनी है और इसके लिए युवाओं की तरफ से बहुत रुझान आ रहा है। हम यहां पर चाहे कितनी ही बातें कर लें मगर प्रदेश के नौजवानों को अच्छी तरह से पता है कि सरकारी क्षेत्र में सभी बेरोजगारों को रोजगार न तो आप दे सकते हैं और न ही हमारी पार्टी की सरकार दे सकती है। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की है।

13/02/2019/1625 /टी0सी0वी0/एच0के0/1

मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 1099 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बार इस योजना को और स्ट्रेंथन करने के लिए आयु सीमा 45 वर्ष की गई है। खासतौर से जो असैट्स हैं, अब उनमें भी पैसा लगाया जा सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ जगह दिक्कत आ रही है। जैसाकि आप कह रहे हैं कि बैकों में जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। हम इस सत्र के तुरन्त बाद बैंकर्ज़ के साथ बैठक करके उनसे आग्रह करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करें कि यदि इस तरह का प्रोजैक्ट लेकर कोई नौजवान आता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर लोन उपलब्ध करवाएं। माननीय अध्यक्ष

महोदय, यहां पर स्वास्थ्य/चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं सभी योजनाओं का ज़िक्र कर सकता हूं लेकिन आपको कहीं जाने की जल्दी तो नहीं है? ये सारी योजनाएं प्रदेश में शुरू हुई हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ मिलें और उस दृष्टि से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां जरुर कहना चाहूंगाः-

'खामोश रहने का अपना ही एक मज़ा है,
नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही आ रहा हूं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः प्लीज, प्लीज ।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। बजट की अगर बात करें ---(व्यवधान)----आप बैठें तो सही ---(व्यवधान)--- मैं बजट पर ही बोल रहा हूं---(व्यवधान)--- आगे वही है---(व्यवधान)---

(कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए)

13-02-2019/1630/NS/YK/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें परंपरा से हट करके हो रही हैं। एक तो विपक्ष के नेता हमें इस बात का आभास करवा रहे हैं कि हमें क्या बोलना है? सबसे पहले शुरूआत उन्होंने (विपक्ष) की थी कि पिछले साल यानी वर्ष 2018-19 की योजनाएं शुरू नहीं हुई हैं। वर्ष 2018-19 में जब बज़ट प्रस्तुत हुआ तो वे योजनाएं धरातल पर थी। मैंने इनके द्वारा खड़े किए गए प्रश्नों का उत्तर देने से ही शुरूआत की। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले यह आवश्यक था कि जो ये (विपक्ष) कहते थे कि कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है, वह इनके व्यवहार से प्रदर्शित हो रहा है। जिन योजनाओं के माध्यम से हमने वर्ष 2018-19 में काम की शुरूआत की थी और ये योजनाएं इस बार ठीक प्रकार से शुरू होंगी।

अब जो योजनाएं थोड़ी शुरू हुई हैं तो उनकी शुरूआत से ही इनको (विपक्ष) इतनी परेशानी है तो आने वाले समय में यह परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष वाले ऋण का ज़िक्र कर रहे थे और ऋण का ज़िक्र करते-करते ये बाहर चले गए। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में हमारे पास सत्ता आई तो लगभग 46,500 करोड़ रुपये का ऋण ये (विपक्ष) छोड़ करके गए थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक साल के कार्यकाल में अगर हमने वित्त प्रबंधन की दृष्टि से कुछ कदम उठाए हैं तो इसका परिणाम भी निकला है। आप एक साल में जितना ऋण लेते थे, हमने उसकी तुलना में बहुत कम ऋण लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं और आज ही इनका यह प्रश्न लगा हुआ था तथा इस प्रश्न के माध्यम से ही मैं इनको उत्तर दे रहा था। यह प्रश्न इस माननीय सदन में लगा था लेकिन ये (विपक्ष) खुद उपस्थित नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 की मदवार अगर हम डिटेल दें तो बाज़ारी ऋण यानी मार्किट लोन लगभग 3000 करोड़ रुपये के हैं और 901.90 करोड़ रुपये हमने वापिस किए हैं तथा मार्किट लोन का शुद्ध ऋण लगभग 2098.10 करोड़ रुपये का बचता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा लोन नाबार्ड के तहत लगभग 371.49 करोड़ रुपये का है और इसमें हमने लगभग 296.35 करोड़ रुपये वापिस किए हैं तथा शुद्ध ऋण 75.14 करोड़ रुपये का शेष रह गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो हमने ऋण लिए हैं, वे 51.60 करोड़ रुपये का है और हमने 67.97 करोड़ रुपये के ऋण वापिस किए हैं तथा इसमें शुद्ध ऋण - 16.37 करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जो ऋण लिया गया है, वह 28.35 करोड़ रुपये का है और इसमें से अभी हमने लोन वापिस करना है। अन्य ऋण मिला करके मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमने ऋण लिए, वे 3451.44 करोड़ रुपये और ऋण जो वापिस किए 1612.69 करोड़ रुपये और इसके बाद 1838.75 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण शेष है।

13.02.2019/1635/RKS/yk-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम ऋण की बात करें तो ऋण की सीमा निर्धारित होती है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 5400 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अनुमति थी लेकिन उसके बावजूद भी हमने उतना ऋण नहीं लिया। हमने उससे बहुत कम ऋण लिया है। इन्होंने वर्ष 2017 में एक कलैण्डर इयर में 7148 करोड़ रुपये का ऋण लिया था जबकि हमने वर्ष 2018 में 3,004 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। लेकिन मुझे इनके शोर डालने की वजह समझ में नहीं आती। ऋण लेने के लिए जो परिस्थितियां पैदा की गई उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है जो यहां से बहिर्गमन कर गए। मैं चाह रहा था कि उनके सामने तथ्य रखे जाएं लेकिन इन्होंने पहले ही अपनी मन स्थिति ऐसी बनाई थी कि वे तथ्यों को सुनना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने अपने बजट में पता नहीं कितनी योजनाओं की घोषणा की है? उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात तो छोड़िए अपितु वे योजना ही नहीं बनी। पांच साल का कार्यकाल बीत गया परंतु वे योजना धरातल पर नहीं उतरी। जिन योजनाओं की घोषणा इन्होंने अपने बजट भाषण में की थी उनकी सूची मेरे पास उपलब्ध है । ये लोग इधर से उधर चले गए परंतु वे योजना ही नहीं बनी। इस तरह बिना योजना बनाए ही इनका कार्यकाल पूरा हो गया। इन्होंने वर्ष 2015-16 में हैलीकॉप्टर चलाने का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था पर्यटकों की सुविधा के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी लेकिन इसकी शुरूआत कहीं भी नहीं हुई। आपने इंडक्शन चूल्हा देने की बात कही थी परंतु इस बात का पता किया जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को इंडक्शन चूल्हे मिले? इस योजना की शुरूआत ही नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं इन बातों को छोड़ देना चाहता हूं। मैं अपने विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहूंगाः-

बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर।
आओ एक मुलाकात जरा आइने से भी कर लें॥

इस बार हमने तय किया है कि बहुत सारी योजनाओं की बजाय सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और होर्टिकल्चर क्षेत्र में छोटे-छोटे इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि नई चीजों की शुरूआत की जा सके और उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की है। एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग, सामान्य वर्ग जो योग्यता रखता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको अवसर नहीं मिल पाता उसे 10 प्रतिशत आरक्षण देते हुए मुझे बहुत

13.02.2019/1640/बी0एस0/ए0जी0-1

प्रसन्नता हो रही है कि इस आरक्षण की शुरूआत आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के माध्यम से हुई और हम इसे हिमाचल प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं।

हम पैंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम पैंशन 750 से बढ़ाकर 850 की, 1300 से 1500 रुपये की। उसके बावजूद भी हमारे मित्र कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं हुआ। अब यह हमारे कार्यकाल में लगभग डबल हो गई है। 5 लाख से अधिक इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। मैंने जिक्र किया उज्ज्वला योजना के प्रार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रीफिल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यह बहुत बड़ी शुरूआत हमने बजट में की परंतु उसके बावजूद हमारे मित्रों को लगता है कि कुछ नहीं हुआ। इसमें सीधा 2 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। केन्द्र की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से गैस चूल्हा और पाइप प्रदान करेगी लेकिन इसके बावजूद कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया।

उसके साथ-साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के 13 महीनों के छोटे से कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को हमने बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं दिहाड़ी की बात कहूं तो मेरे पास यहां पर आंकड़े हैं। निश्चित रूप से एक महीने में 750 रुपये का लाभ एक व्यक्ति को एक महीने में हो रहा है। उसके बावजूद हमारे मित्र कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। मुझे कह रहे थे कि आपने तो चिल्लर की तरह लॉलीपॉप बांट रहे हैं। इन्होंने अपनी सरकार के समय वर्ष 2014 में 70 रुपये से 80 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई। इसमें 10 रुपये बढ़ाए गए थे। वर्ष 2015-16 को 80 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये की गई, इसमें इन्होंने

20 रुपये बढ़ाए थे। इसके बाद फिर इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछली साल 210 रुपये से सीधे 225 रुपये बढ़ाया इसमें हमने 25 रुपये की बढ़ौतरी की और इस बार सीधा 25 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लाभ दिया है। यह मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ग्रोथ हमारे दिहाड़ीदार जो गरीब लोग हैं उनके वेतन में होगी। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, उन योजना के माध्यम से जिन योजनाओं के माध्यम से हमने शुरूआत की है। चाहे वह हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं मिनि आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर्ज हैं, वाटर गार्ड हैं, स्कूलों के वाटर कैरियर हैं , मिड-डे-मील वर्मकर्ज हैं, या हमारे पंप सहायक ऑप्रेटर्ज हैं, पैरा फिटर्ज हैं, चाहे चौकीदार है, रेवेन्यू चौकीदार हैं, एस.पी.ओज. हैं इन सब के मानदेय को बढ़ाने के लिए जो हमारे संसाधन हमें अनुमति देते थे उसके मुताबिक हमने थोड़ी-थोड़ी बढ़ौतरी सबके वेतन में करने का प्रयास किया है।

श्री राकेश सिंघा : जो आपने आंगनगाड़ी की कार्यकर्ता के वेतन का खाका तैयार किया है उसमें उसके वेतन को गलत दिखाया गया है।

मुख्य मंत्री : जो आप सुझाव दे रहे हैं उस पर अवश्य गौर करेंगे। इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री आवास योजना के अतंर्गत पहले यह राशि 1.20 लाख मिलती थी हमने इस बजट में 1.50 हजार किया है । यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है। उसके साथ-साथ रिपेयर करने के लिए मरमत करने के लिए उनके मकान के 25 हजार से बढ़ा करके 35 हजार किया है । उसके बावजूद हमारे मित्र बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। हमने समाज के उस वर्ग को छूने की भी कोशिश की है जो सारी जिंदगी भर किसी की मदद के लिए मोहताज रहता है। यदि कोई आदमी बीमार है और बीमारी के कारण उसको पैरालाइज हो गया है उसके कारण वह चल नहीं सकता यदि किसी व्यक्ति की दुघटना में टांगे चली गई हों तो वह चल नहीं सकता, सारी जिंदगी भर वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसी परिस्थिति में चाहे वह कैंसर की दिक्क्त है, चाहे अधरंग है, मसकुलर डिस्ट्रोपी है,

थैलिसीमियां है, रीनल फेल्युअर है, इन सारे ऐसे वर्ग के लोगों को जिनकी मदद के लिए जिनकी बिमारी के लिए आदमी को 24 घंटे जैसे कोई मां अपने बच्चे की देखभाल करती है उसी प्रकार इनकी देखभाल करनी पड़ती है । इसमें पैसा हम बहुत कम दे पाए पारंतु इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि उनके लिए सहारा योजना के अंतर्गत 2000 रुपये प्रदान किया जाएगा ।

13.02.2019/1645/dt/ag-1

ब्रैस्ट कैंसर के केसिज पिछले कुछ अरसे से बहुत बढ़ रहे हैं उसके लिए भी हमने शुरूआत की है। इसके अर्ली डिटैक्शन के लिए एक मोबाइल वैन ली जाएगी जिसमें सभी उपकरणों की सुविधा होगी।

इसके अलावा जिन परिवारों में कमाने वाला एक आदमी है और उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस परिवार को बहुत कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में जब उस परिवार का सदस्य नौकरी के अप्लाई करता था तो उसे कहा जाता था कि उस व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से ऊपर हो गई थी इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि रिटायरमैंट के एक दिन पहले भी यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उस परिवार के व्यक्ति को करूणामूलक आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया। यह छोटे-छोटे इनिशिएटिव हमने मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लिए हैं। चाहे कृषि या बागवानी की बात हो हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसको सप्लीमैंट करने के लिए जो कंपोनैंट थे, उसमें हमने काम करने की कोशिश की है। चाहे उसमें देसी नस्ल की गाय की बात है, उस योजना को जमीन पर और मजबूत करने के लिए काम किया है।

हमारे मित्र सदन से बाहर चले गए मैं उनको कहना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं दो-तीन तथ्य यहां पर रखना चाहूंगा। विकास के लिए सभी देश तथा उनकी राज्य सरकारें ऋण लेती है। हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य जिसके अपने आय के साधन सीमित हों के विकास कार्यों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है। पिछली सरकार ने वर्ष 2013 से 2017 तक

18787 करोड़ अतिरिक्त ऋण लिया जिसके कारण 18 दिसम्बर, 2017 को प्रदेश पर ऋण 46385 करोड़ रुपये का भार हो गया था। वर्ष 2008 से 2012 तक भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुल ऋण 7621 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि यही वृद्धि 2013 से 2017 तक कांग्रेस के कार्यकाल में 18787 करोड़ रुपये की हुई। आप क्या करके चले गए और हमें भाषण दिए जा रहे हैं। किस तरह से इस प्रदेश को तहत-नहस करके चले गए। किस तरह आर्थिक व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त करके चले गए। इसके बावजूद भी हमें सीख सिखा रहे हैं। इनको अपने किए हुए पर शर्म होनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है कि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। उन्होंने इस प्रदेश को अंधकार में धकेला है। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त किया है। जनता के ऊपर इतना कर्ज का बोझ डाल दिया है और अपने आप सरकार को आनंद के माहौल में चलाना, और पूरे पांच साल तक जश्न मनाते रहना, इस माहौल में इन्होंने समय गुजारा हैं । राज्य सरकार के कौशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम यह है कि राजस्व प्राप्ति के में वृद्धि के कारण कलैण्डर इयर 2017 में की तुलना में 2018 में कम ऋण उठाए।

13-02-2019/1650/डी.सी./एन.जी./1

वर्ष 2018 में कुल ऋण वृद्धि केवल 3 हजार करोड रूपये की हुई जबकि कैलेन्डर ईयर 2017 में यह ऋण 7148 करोड रूपये की हुई थी । इन्होंने हमसे दोगुना ऋण लिया उसके बावजूद भी, बेरहमी की भी एक हद है उन्होने कभी भी प्रदेश पर रहम नहीं किया और उसके बाद बेशर्मी की भी हद है । सारी हदें पार करके ऐसे कह रहें है कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है । हमसे दोगुना ऋण लेकर के हमको सिखा रहे हैं कि हमने ऋण बहुत ज्यादा ले लिया । हमारी सरकार कर्जों पर निर्भरता कम करने के पक्ष में है और अधिक केन्द्रीय साहयता, कुशल वित्तीय प्रबन्धन और प्रदेश के अपने संसाधनो पर ही निर्भर होना चाहती है ।

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय अनुमानित राजस्व घाटा 3167 करोड रूपये आंका गया था । 2019-20 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 2342

करोड रूपये आंका गया है । जोकि पहले की तुलना में कम हुआ है यह बात उनको समझनी चाहिए । इसी प्रकार से 2018-19 के बजट अनुमानों में राज कोषीय घाटा 7821 करोड रूपये आंका गया था जबकि 2019-20 के बजट अनुमानों में यह घाटा 7352 करोड रूपये आंका गया है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 500 करोड रूपये कम है । राज्य के ऋण को यदि हम राज्य के सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात में देखें तो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में इसे 34.61 प्रतिशत आंका गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इसे 34.04 प्रतिशत आंका गया है । यह आंकडा निश्चित रूप से वित्तीय प्रबन्धन में सुधार का सूचक है । अध्यक्ष महोदय, यह मैं उनको कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय 15वें वित्त आयोग के सामने भी प्रदेश पर कर्ज का जो बोझ है उसे बडे प्रभावी ढंग से मामला उठाया गया है । अगर आपको याद हो तो पूर्व की ही कांग्रेस सरकार ने सन् 1994 में Off Budget Borrowings" की प्रथा चलाई थी । जब बिजली बोर्ड और वन निगम के माध्यम से कर्जे उठाए थे और उसका खमियाजा प्रदेश की जनता आज भी भुगत रही है । अध्यक्ष महोदय, असली में सबसे खराब स्थिति 1993-94 में शुरूआत हुई थी और उस वक्त सरकार हिमाचल प्रदेश में उन्ही महानुभाव की थी जो आज सदन चले गए है । उन्होनें ही शुरूआत करके आज सारी व्यवस्था यहां तक पहुंचाई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि :

कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में,
कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में,
लम्हों ने खत्ता की थी और सदियों ने सजा पाई ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत विस्तार से बजट के उन सारी चीजों में जाने की आवश्यक्ता महसूस नहीं करता हूं क्योंकि सारी चीजों में हमारे मित्र जिस प्रकार से यहां जोर डाल रहे थे और अपनी बात कह रहे और बात कहते-कहते चले गए । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी कहना है कि externally aided agencies का जिक्र भी यहां पर हुआ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि आर्थिक दृष्टी से परिस्थिती ठीक नहीं है और ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश के लिए मदद का रास्ता कहां से निकल सकता है । एक वक्त होता था कि केन्द्र से पैकेज मिलता था और वो दौर समाप्त

हो गया है । आज आपको उस प्रकार से untied grants केन्द्र सरकार से किसी भी प्रदेश को नहीं मिल पा रही है । एक-दो प्रदेशों को छोड कर के, क्यों कि वहां की परिस्थितियां अलग हो सकती है । लेकिन इस प्रकार से किसी भी प्रदेश को untied grants मिलने के सिलसिला किसी जमाने में होता था अब वो सारा सिलसिला बन्द हो गया है । ऐसी प्ररिस्थिती में हमने बहुत सारे प्रोजैक्टस बना कर के तैयार किए और वो प्रोजैक्टस हमने externally aided agencies के लिए भेजे और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साल के कार्यकाल में 10330 करोड रूपये के प्रोजैक्टस भेज कर के और उनकी स्वीकृतियां आना, यह हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में और कठीन परिस्थितियों में भी विकास की दर कम ना हो, विकास की गति कम ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार का एक दिशा देने का प्रयत्न है ।

13/02/2019/1655/RG/DC/1

हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद जो नए इनिशियेटिव्य लिए हैं इनकी वजह से हमारे मित्रों को बहुत असुविधा हो रही है। हम जनमंच की बात करते हैं तो जनमंच इनके लिए ऐसी आफ़त बन गई है जिसके कारण वे इतने परेशान हो गए हैं कि वे कुछ समझ नहीं पा रहे और हम यह कह सकते हैं कि उनमें एक तरह से हड़कम्प मचा हुआ है। कभी कोई पूछ रहा है कि इस कार्यक्रम में कहां से खर्चा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और कितना खर्चा किया जा रहा है? मैं एक बहुत ही स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुसार जब ये लोग सरकार चलाते थे, हम इनको कहते थे कि योजनाएं बनाओ और आप अपना विज़न दें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप पर्यटन के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं या आप प्रदेश में विकास के लिए क्या करना चाहते हैं? लेकिन उसमें होता कुछ नहीं था। इनका भाषण लम्बा होता था और विज़न उसमें होता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में सारी चीजें इसी प्रकार से आगे बढ़ाई जाती थीं। सिर्फ पांच साल का कार्यकाल पूरे आनन्द और आराम के साथ कैसे व्यतीत किया जाए, सारी योजनाएं उस प्रकार से बनाई जाती थीं और उसी प्रकार से उन योजनाओं का संचालन होता था। इसीमें इनका कार्यकाल पूरा हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो पहल की हैं, उनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और जब परिणाम सार्थक आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी बैचेनी इस कदर

बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी पहल की हैं उनके और अधिक सार्थक परिणाम हमारे समक्ष आएंगे। ड्रग्ज के मुद्दे को लेकर हमने गंभीरता से प्रयत्न किए। आप तो प्रयत्न ही नहीं करते थे। हम बहुत सारी चीजों को लेकर कहना नहीं चाहते, बातें छिपी नहीं रहती हैं, हमने कई सारे राज़ अपने दिल में छिपाकर रखे हुए हैं और हम उनका जिक्र भी यहां नहीं करना चाहते। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि कुछ लोगों को संरक्षण प्राप्त होता था कि ये हमारे आदमी हैं, इनको पूछा न जाए। जब पूछने लगते थे तो कहते थे कि उनको छोड़ दिया जाए। ऐसी परिस्थितियां यहां उत्पन्न होती रही हैं। लेकिन आज की तारीख में हमने सख्ती की है और उसका परिणाम यह हुआ है कि मामले दर्ज हुए हैं। हमारे कुछ मित्र पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इतने मामले बढ़ गए, तो जब हमने कार्रवाई की तभी तो मामले बढ़े। अगर हमने कार्रवाई न की होती और अगर हम भी यही कहते कि इस आदमी को मत पूछना, तो मामला थोड़े ही दर्ज होने थे। अगर कोई पकड़ा जाता है
तो हम कहते हैं कि मामला दर्ज करो और कार्रवाई करो। मामले तब दर्ज हुए। जिसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए हैं और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अभी और सख्ती करने की आवश्यकता है। हमने तय किया था कि इस मामले में कानून को सख्त बनाएं और उसमें हमने पहल भी की है। इसके साथ-साथ में अपने व्यवहार में भी सख्ती करेंगे। दूसरे प्रदेशों के साथ मिलकर इस मामले में तालमेल भी करेंगे। उस दृष्टि से हमने और योजनाएं भी हिमाचल प्रदेश में ड्रग्ज को कंट्रोल करने के लिए और इसके नैक्सस को तोड़ने के लिए शुरू की हैं और मुझे लगता है कि उसके परिणाम भी बहुत सार्थक होंगे। इसका हमने इस बार अपने बजट में विस्तार से जिक्र किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना चलाई कि गरीब लोगों के घरों में बिजली पहुंचे। मुझे बहुत हैरानी होती है कि हमारे कुछ मित्र खड़े हो गए, कहने लगे कि हिमाचल में एक भी परिवार बिजली के बिना नहीं है और कुछ लोग कहने लगे कि राजा साहब ने सबके घरों में बिजली लगा दी थी। मैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि हर साल हिमाचल प्रदेश में 40-45 हजार नए घर बनते हैं और जब इतने नए घर बनते हैं तो क्या उनको बिजली का कनैक्शन पहले ही दे रखा है? जब नया घर बनेगा तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी और जब बिजली की आवश्यकता होगी तो खंभाऔर वहां तार भी लगेगा। इसलिए हमने यह कदम उठाया और

हमने अपने बजट में 'मुख्य मंत्री रोशनी योजना'इसकी शुरूआत की। तो ये उस पर भी मजाक करने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे गरीब लोग इसी में रह जाते थे कि मीटर लगाना है, उसका पैसा देना है, खंभा लगाना है, उसका पैसा देना है, तार लगानी है, उसका पैसा देना है और वे इस परिस्थिति में नहीं हो पाते थे और कई साल उनके ऐसे ही बीत जाते थे। घर तो बना है लेकिन बिजली का कनैक्शन घर तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि वे उन पर होने वाले खर्चों को करने में असमर्थ होते थे। उसके लिए पैसा देना पड़ता था।

13/02/2019/1700/MS/yk/1

इसलिए हमने रोशनी योजना की शुरुआत की। किसी भी गरीब आदमी के लिए बिजली का कनैक्शन उसके घर तक दिया जाएगा और इसके लिए उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यह हमने एक शुरुआत की है जिसके कारण हमारे विपक्ष के मित्रों को परेशानी हो रही है। मैं एक शेर भी बोलना चाहता था लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। अगर मैं शेर बोलूंगा तो हमारे उन मित्रों को फिर से परेशानी होगी। अगर हम थोड़ा जिक्र करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारी तुलना जुगनू से कर दी। मैं इनकी तुलना जुगनू से नहीं कर रहा हूं लेकिन जो शेर किसी ने लिखा है उसकी भावना में जाने की इनको कोशिश करनी चाहिए। परन्तु हकीकत यह है कि सारे जुगनू मिलकर सूरज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात तो कहनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगे यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे पी0टी0ए0/पैरा/ पैट वालों के जो कुछ मसले थे, उन सारी चीजों को लेकर हम गम्भीर हैं। ये लोग इनको बुलाते रहे और श्रीमान विक्रमादित्य सिंह जी जो वर्तमान में इस सदन के नौजवान माननीय सदस्य है,

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया एक मिनट के लिए बैठिए क्योंकि सदन का समय बढ़ाना है। अभी आपको कितना समय लगेगा?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, 15-20 मिनट का समय लगेगा।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए बढ़ाई जाती है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि हमने बहुत संयम और सब्र रखा है। हमने वे भी परिस्थितियां देखी हैं कि पूर्व में 5 साल जो सरकार रही, उस सरकार का संचालन कैसे हो रहा था। आज हमारे वे मित्र इस सदन के माननीय विधायक हैं और मैं उनका अदब करता हूं। वे मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन सरकार की ऑथोरिटी का किस तरह से इस्तेमाल करते थे, मैं उस बात का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। ये यहां बेरोजगारों की बात कह रहे हैं लेकिन पिछले पांच सालों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बेरोजगारों को गुमराह किया है तो इन्होंने किया है। परिवार और सरकार के लोग उन बेरोजगारों को कहते थे कि टिक्का साहब से मिलिए। सबको ये आदेश होते थे कि टिक्का साहब से मिलिए और पीटरहॉफ में प्रदेश के बेरोजगारों को जो आज भी प्रदर्शन करने के लिए यहां आए हुए हैं, इकट्ठा किया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हें एक शर्त को मानना पड़ेगा तथा वह शर्त यह थी कि जो नारा लगाया जाएगा, उसको पीछे-पीछे आप लोगों ने भी दोहराना है कि सातवीं बार राजा साहब। हजारों की तादाद में जो लोग आज यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनको वहां खड़ा कर दिया गया और एलान किया गया कि सबको रोजगार दिया जाएगा लेकिन सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल निकल गया और आज वे लोग दर-दर भटक रहे हैं। इस प्रकार का नारा लगवाने वाले आज कहां चले गए? माननीय अध्यक्ष जी, बोलना बहुत ही सरल होता है इसलिए मैं उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता लेकिन पिछले पांच साल के कार्यकाल में जो सरकार का एक सिस्टम होता है कि सरकार कहां से चलेगी, उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा प्रदेश जानता है। आज हमें नौजवानों के लिए कुछ करने को कहा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं आप भी सत्ता में थे और नौजवान थे। आप उस वक्त स्टेट की यूथ की एक युनिट को हैड कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक अवसर था कि उनके लिए कोई योजना बनाते और उनके लिए नौकरी का प्रावधान करते। लेकिन कुछ नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सबसे सरल काम किसी को नसीहत देना है क्योंकि उसमें कुछ नहीं लगता है। जो नसीहत हमारे मित्रों ने दी है, उसमें हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है और हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसके बावजूद भी उन नौजवानों के लिए जो पी0टी0ए0 के अंतर्गत लगे हैं, हम देख रहे हैं कि वे वर्षों से सर्विसिज

दे रहे हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा वे एक उम्मीद में लगे रहे और टिके रहे

13.2.2019/1705/जेके/एजी/1

और काम करते रहे। भले ही बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। आज हमको लोग पूछते भी हैं लेकिन हमने कहा अब हमको इन्हें एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ देखना है और उस मानवीय दृष्टिकोण की झलक इस बजट में है। हमने कहा कि जितने भी पी.टी.ए. पर लगे हैं, किसी को नहीं हटाया जाएगा। रैगुलर कर्मचारियों का जो पे-स्केल है और जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं, वे सारी-की-सारी सुविधाएं उनको भी दी जाएंगी। हमने तो यह किया लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग तो यह कहते रहे कि सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने तुम्हें लगाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई चुनावों में उनको यही कहा गया कि तुम लोगों को हमने लगाया है इसलिए जाओ और पोलिंग बूथ पर खड़े हो जाओ। वर्ष 2006 से कितने चुनाव हो गए, कितनी बार उनका शोषण करते रहे लेकिन उसके बावजूद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जा कर रैगुलर करने की स्थिति में हम नहीं हो पाए। कम-से-कम जो हम आज कर रहे हैं, उसको करने की तो आप लोगों के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि हम इस काम को करेंगे और हमने उस दृष्टि से यह काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि कुछ लैफ्ट आउट का जो थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास रहता है, जो कि लगभग 1300 के करीब है, उसकी भी सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उनके प्रति भी वही दृष्टिकोण और उनके प्रति भी जो भी मदद की जा सकती है, पे-स्केल में और दूसरी चीजों में जो व्यवस्थाएं उनके हिसाब से की जा सकती हैं, वे सारी सुविधाएं उनको देने का भी हमने

इसमें अपनी मंशा रखी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे जल रक्षक हैं, प्रदेश में जल रक्षकों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में हम शरीक हुए और उनके साथ जो बात हुई थी, उनकी कुछ बातों का हमने बजट में जिक्र कर लिया है। वे सारी चीजें

हमने स्वीकार कर ली है और इसमें सबसे ज्यादा हाइक दी है क्योंकि वे भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम अगर गांवों में शुद्ध पेयजल देने की बात करते हैं तो उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जल रक्षकों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। जहां नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी, सरकार शीघ्र उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। जो नियमित होने की सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की स्थिति में हैं, उनकी बहुत ज्यादा मदद इसके माध्यम से होगी लेकिन संशोधन की जो आवश्यकता है,उसका जिक्र यहां पर करना उचित नहीं है, जब केबिनैट मीटिंग होगी तब उसमें उसका निर्णय लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी करैक्शन करनी है कि जो हमारा बजट प्रिंट हुआ था, बजट भाषण के पैरा 132 में थोड़ी सी शुद्धि करना चाहूंगा वह यह है कि इस पैरा में "मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना" का जिक्र किया गया था उस योजना को "प्रधान मंत्री सड़क योजना" पढ़ा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक नौजवान मित्र ने, पूरे सदन में एक भी सदस्य ने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया कि इमरजैंसी के दौरान जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कानून का उल्लंघन किया और जो जेल चले गए, उनको सम्मानित करने की कोशिश की है, आपने स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान किया है, मैं उनको कहना चाहता हूं क्योंकि शायद वे उस वक्त इस दुनिया में नहीं आए थे, उनका जन्म उसके बाद का ही हुआ है। उन सारी चीजों में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं

इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन्होंने दौर नहीं देखा है। अगर दौर नहीं देखा है तो इतिहास जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी । सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए देश में 1975 में इमरजैंसी लगा दी थी और पूरे देश को जेल बना दिया था।

13-02-2019/1710/SS-YK/1

जेल में जगह नहीं थी तो जहां संस्थान मिलते थे वहां लोगों को उठाकर डाल दिया गया था। उनमें से पूरे देश भर में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस प्रकार की यातनाएं दी थीं, जिस प्रकार की यातनाएं अंग्रेज़ों के जमाने में अंग्रेज देते थे। ऐसी परिस्थितियां देश में स्वतंत्रता के बाद भी देखी गई हैं। इसलिए उनको इस बात की जानकारी नहीं है। एक सुझाव हमारे पास आया कि बहुत सारे प्रदेशों में इस प्रकार से लोकतंत्र प्रहरी के नाम से योजनाओं की शुरूआत हुई है जिसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने 19-19, 20-20 महीने जेल की सलाखों के पीछे काटे हैं। हमारी पार्टी के बड़े नेता,श्री शांता कुमार जी भी उसमें शामिल थे। श्री सुरेश भारद्वाज जी यहां पर बैठे हैं ये भी जेल की सलाखों के पीछे गए हुए हैं।

अध्यक्षः मैं भी उसी में था।

मुख्य मंत्रीः आप स्वयं वहां पर बैठे हैं, आप भी स्वयं जेल की सलाखों के पीछे गए। उस दृष्टि से हमने एक छोटा-सा निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में उनकी संख्या 100 से भी बहुत कम है। क्योंकि इस पर पहले विचार हुआ नहीं लेकिन हमने विचार किया और विचार करने के बाद हमने तय किया कि लोकतंत्र प्रहरी योजना हिमाचल प्रदेश में उन लोगों के लिए शुरू की जाए, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज़ बुलन्द की कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। लोकतंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए। उस दृष्टि से जेल की सलाखों के पीछे वक्त काटा है, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें भी एक छोटी-सी कॉरैक्शन करना चाहता हूं। उसमें हमने 11000 रुपये वार्षिक का ज़िक्र किया है। वहां पर "वार्षिक" का ज़िक्र हुआ है। वह छोटी-सी गलती और हुई है। उसको "प्रतिमाह" गिना जाए। हमने उनको प्रति माह 11000 रुपये देने का निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे पैट साथी हैं। हमने उनकी समस्याओं को भी सुना है। उनकी समस्याओं से भी हम अवगत हैं। अवगत होने के साथ-साथ में हम उनकी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से भी कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्तुत बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास किये गए हैं। विपक्ष के माननीय विधायकों का यह कथन कि बजट चुनावों के वायदों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मुझे उनका कहना बहुत विचित्र लगा। एक तरफ से बोलते हैं कि बजट में कुछ नहीं है और दूसरी तरफ से बोलते हैं कि यह बजट चुनाव के लिए बनाया हुआ है। जब इसमें कुछ नहीं है तो चुनाव के लिए क्या बनाया है? चुनाव में इसका क्या लाभ होने वाला है? हमको तो नुकसान ही होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, हमने अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया है, हमने विशुद्ध हिमाचल प्रदेश के विकास के संबंध में पेश किया है। विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। विकास के लिए हम सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारी बातों का ज़िक्र करने के साथ-साथ में हमने उनका बजट में समावेश किया है। चुनाव से इस बजट का कोई लेना-देना नहीं है। चुनाव आ रहा है, हम उसे लड़ने में सक्षम हैं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बजट हमारा उसके लिए आधार नहीं है। बजट में जो भी हमने किया है, समाज के प्रति जो करने की हमारी मनःस्थिति है, भावना है उसको मूल रूप से ध्यान में रखते हुए पूरा करने की कोशिश की है। यह मैं कहना चाहता हूं। उस दृष्टि से हम चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की बात कह रहे है या दूसरे संस्थान खोलने की बात कह रहे हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके सिरमौर जिला में आ करके तीन आई0टी0आई0 की बात कही थी। उसमें दो का ज़िक्र हुआ। एक आई0टी0आई0 छूट गई थी। एक ज़िक्र जो छूट गया था वह कोलावाला भूड नामक स्थान है, वहां पर हमने तीन आई0टी0आईज़0 का ज़िक्र किया था, उसको भी पूरा करने के लिए हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं, वृद्धों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं तथा सामाजिक

सुरक्षा दायरे को बढ़ाया गया है। ऊर्जा, सिंचाई, सड़कों तथा पेयजल के क्षेत्र में अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

13.2.2019/1715/केएस/वाईके/1

प्रदेश की जनता की विकास प्राथमिकता को जानने के लिए उससे सीधा संवाद स्थापित करने के भी प्रयास किए गए हैं। राजकीय आंकड़ों पर वर्णन माइक्रो लैवल पर किया गया है जबकि विस्तृत सूचना बजट के अन्य दस्तावेजों में निहित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट के माध्यम से कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखें लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत सारे वर्ग ऐसे भी हैं जहां अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष रूप से सत्ता पक्ष के सदस्यों, जिन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं। हम उन सुझावों पर निश्चित रूप से अमल करने की कोशिश करेंगे और उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात का जिक्र किया गया, सरकाघाट के बल्साड़ में सैनिक कोचिंग अकेडमी खोलने की बात कही थी, इस बारे में मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ औपचारिकताएं हैं लेकिन यह अच्छा सुझाव है और इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र से बहुत से युवाओं को सैनिक बनने का अवसर प्राप्त होगा, मैं यह समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, "**बस एक अल्फाज़ उनको सुनाने के लिए, जाने कितने अल्फाज़ लिखे हमने जमाने के लिए**" यह मैं कहना चाहूंगा। जो हमने वर्ष 2019-20 का बजट यहां पर प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है, जिनका हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बजट हमने प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से गरीबों और समाज के उन सभी वर्गों को

वह लाभ मिले जिस मन्शा के साथ हमने इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह चुनाव का वर्ष है । चुनाव की दृष्टि से हमारे विपक्ष के मित्रों को यह सब करने की आवश्यकता महसूस हो रही है क्योंकि जो भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुझाव कम और बाधा ज्यादा डालने का प्रयत्न हो रहा है। उनको यह लग रहा है कि वर्ष 2019 में चुनाव है। हम इस प्रकार का माहौल खड़ा करें कि हमने सरकार का इस बात पर विरोध किया, उस बात पर विरोध किया। हमने उनको सरल शब्दों में एक बात कही कि इस माननीय सदन की एक स्थापित व्यवस्था रही है। जब भी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, चर्चा होती है, चर्चा पर जब सदन के नेता जवाब देते हैं तो उस जवाब को पूरा सुना जाता है। सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। उसके बाद क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, अपना प्रोटैस्ट दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आवश्यक लगता है कि हमको एक राजनैतिक विवशता से बाहर जाना है तो जा सकते हैं लेकिन यह नई परम्परा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है, हम पांच मिनट बोलते हैं, पांच मिनट बाद ही हमारे विपक्ष के लोग बाहर चले जाते हैं। इनको सुनना ही नहीं है। उसके बाद अब जब बजट प्रस्तुत किया, बजट पर चर्चा में 37 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेते वक्त सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कहीं । स्वभाविक रूप से माननीय सदस्यों द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं, किसी के क्षेत्र में सड़क का मामला है, किसी के क्षेत्र में बिजली की समस्या है, पुल की समस्या है या बस सर्विसिज़ या स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, स्कूलों की आवश्यकता है तो माननीय विधायक उन बातों का जिक्र करते हैं। यहां पर भी जिक्र किया गया ।

13.2.2019/1720/av/ ag/1

जब सदन की ओर से अपनी बात कहने के लिए मुख्य मंत्री को प्राधिकृत किया जाता है कि मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे तो हमारी विपक्ष से स्वाभाविक रूप से इतनी उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि वे यहां पर बैठकर हमारी बात को सुनें। हमें सुनने के बाद जहां पर उन्हें लगता है कि यह बात संतोषजनक नहीं है तो वहां पर वे प्रश्न करें तथा उसके बाद उनको जो उचित लगता है वही करे। लेकिन पांच मिनट के अंदर ही बैठे-बैठे टिप्पणी करना शुरू कर देना तो उचित नहीं है। उन्होंने पांच मिनट के अंदर ही लगातार उठना-बैठना शुरू कर दिया। हम तो इनको पिछले तीन दिनों से सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि इन तीन दिनों में मैंने केवल एक-आधे मिनट के लिए इन्टरवीन किया होगा। लेकिन मेरे विपक्ष के मित्र लगातार बोलते रहे और मेरे पांच मिनट बोलने के बाद ही हमें सलाह देने लगे कि बजट पर बोलो। हमने कहां से बोलना है और क्या बोलना है; इसको विपक्ष तय नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे दौर आते हैं जब हमें अपनी बात कहने के अलग-अलग अवसर प्राप्त होते हैं मगर हर वक्त इस सदन की गरीमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। मैं आज सुबह से देख रहा हूं और इससे आहत भी हूं। हमारे विपक्ष के मित्र हर जगह व हर वक्त इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं जो कि एक परिहास का विषय बन गया है। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उस ओर नेतृत्व का एक भारी संकट पैदा हो गया है और वह भारी संकट इनकी इस प्रकार की हरकतों से दिख रहा है। उनको लग रहा है कि मेरा नेतृत्व तभी स्थापित हो पायेगा जब हम सदन में इस प्रकार का शोर डालकर बाहर चले जायेंगे। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नेतृत्व को मजबूत नहीं करता बल्कि उलटे कमजोर करता है। ऐसा व्यवहार नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त नहीं करता बल्कि एक अविश्वास की परिस्थिति पैदा करता है। उस तरफ इस प्रकार की हलचल पैदा हो रही है कि कौन सलाह दे, कौन न दे और कौन ज्यादा बोले, कम बोले या कहां बोले; इन सारी बातों को लेकर के हमारे मित्र परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे विपक्ष के मित्रों ने यहां जो भी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की है उससे इस सदन

की गरीमा को ठेस पहुंची है। इस बजट के संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि हमने बजट में जो कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की है वह हमारा एक ईमानदार प्रयास है। पिछले वर्ष के बजट में भी हमने यह प्रयास किया था तथा आने वाले वित्तीय वर्ष में भी हमारा वही ईमानदार प्रयास जारी रहेगा।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सचिव,**

दिनांक : 13 फरवरी, 2019 **हि0प्र0विधान सभा।**